



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2018/वैशाख 7, 1940

No. 155]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 2018/ VAISAKHA 7, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2018

अंतिम जांच परिणाम

(मामला सं. 01/03/2017)

विषय : कोरिया जन. गण. और चीनी ताईपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए डायकटिल फेथालेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

सं. 6/2/2017 – डी जी ए डी : - समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम 1975 (इसके पश्चात भी अधिनियम के रूप में संदर्भित) और समय-समय पर यथा संशोधित इसका सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली 1995 (इसके पश्चात भी नियमावली के रूप में संदर्भित) के संबंध में :

- जबकि मैसर्स के एल जे प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड, (इसके पश्चात याचिकाकर्ता अथवा आवेदक अथवा घरेलू उद्योग के रूप में संदर्भित) ने पाटन एवं परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए कोरिया जन. गण. और चीनी ताईपेई (इसके पश्चात संबद्ध देशों के रूप में संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "डायकटिल फेथालेट" (इसके पश्चात संबद्ध वस्तुओं के रूप में भी संदर्भित) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच आरंभ करने के लिए इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात प्राधिकारी के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष के आवेदन दायर किया है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया।
- और जबकि, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर कथित पाटन के मौजूद होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क जो, यदि लगाया जाए, घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की राशि की सिफारिश करने के लिए इस नियमावली के उप नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच आरंभ करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 1 जून, 2017 के अधिसूचना संख्या 6/2/2017 – डी जी ए डी के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

क. प्रक्रिया

4. यहां नीचे उल्लेख की गई प्रक्रिया का पालन प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के संबंध में किया गया है :

- (i) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए कार्यवाही करने के वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया है।
- (ii) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 1 जून, 2017 के द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- (iii) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों इन आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये पते के अनुसार जांच प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे जांच प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।
- (iv) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को और ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को इस आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- (v) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी यह अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें। इन उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ साथ उन्हें भेजी गयी थी।
- (vi) प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावली भेजी।

- क. मैसर्स चेमक्रॉस इंक. एशिया
- ख. मैसर्स ह्यूमडे कोरपोरेशन
- ग. मैसर्स वूरी पी एंड कोरपोरेशन
- घ. मैसर्स यू पी सी टेक्नोलॉजी कोरपोरेशन
- ड. मैसर्स एडवांस टेनकोकैम
- च. मैसर्स दाह शेंग प्लास्टाइजर्स कं. लिमि.
- छ. मैसर्स एल जी केम कं. लिमि.

(vii) संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर दायर किया।

- क. मैसर्स ओ सी आई कंपनी लिमि. कोरिया जन. गण.
- ख. मैसर्स नॉन या प्लास्टिक्स कोरपोरेशन, चाईनीज ताईपेई
- ग. मैसर्स एवरलाइट कोरिया कं. लिमि., कोरिया जन. गण.
- घ. मैसर्स जे सी पेट्रोकेम लिमिटेड, हांगकांग
- ड. मैसर्स एकयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमि. कोरिया जन. गण.
- च. मैसर्स केनको मार्केटिंग इंक, कोरिया जन. गण.
- छ. मैसर्स चेमटॉन कं. लिमि., कोरिया जन. गण.
- ज. मैसर्स ह्यूमाडे कोरपोरेशन, कोरिया जन. गण.
- झ. मैसर्स हुंडई कोरपोरेशन, कोरिया जन. गण.
- ञ. मैसर्स यूबेस्को कोरपोरेशन, कोरिया जन. गण.
- ट. मैसर्स वूरी पी एंड सी कोरपोरेशन, कोरिया जन. गण.

(viii) प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावली भेजी:

- क. मैसर्स अल्फा पोलिमर्स
- ख. मैसर्स अनुकंपा पोलिमर्स एंड टेक्नोलॉजिज प्रा. लिमि.
- ग. मैसर्स ग्लोस्टर केबल्स लिमिटेड
- घ. मैसर्स प्राइम पोलिमर्स
- ङ. मैसर्स एस. गोपाल कामथ (कोचिन)
- च. मैसर्स कोयर टफ्ट इंटरनेशनल प्रा. लिमि.
- छ. मैसर्स केराफिबरटेक्स इंट. प्रा. लिमि.
- ज. मैसर्स द एलेप्पी कंपनी
- झ. मैसर्स केरला बार्स (प्रा.) लिमि.
- ञ. मैसर्स टयूब प्रॉडक्ट्स
- ट. मैसर्स जी टी (इण्डिया) अहमदाबाद
- ठ. मैसर्स निशान मार्केटिंग
- ड. मैसर्स सिगमा आर्गेनिक एंड केमिकल्स प्रा. लिमि.
- ढ. मैसर्स लेजर केबल्स प्रा. लिमि.
- ण. मैसर्स प्लास्टिक पैक
- त. मैसर्स जैन केमिकल्स (जयपुर)
- थ. मैसर्स जैन केमिकल्स एंड प्लास्टिक (दिल्ली)
- द. मैसर्स लियो विनायल्स कपूरथला रोड
- ध. मैसर्स जेनको इंटरप्राइसेस
- न. मैसर्स अरविंद प्लास्टिक उद्योग
- प. मैसर्स राधा प्लास्टिक इंडस. (दमन)
- फ. मैसर्स वरुन आर्गेनिक प्रा. लिमि.
- ब. मैसर्स कृष्णा इंटरप्राइसेस
- भ. मैसर्स ए. डी. इण्डस्ट्रीज
- म. मैसर्स डायमण्ड पाइप्स एंड ट्यूब्स प्रा. लिमि.
- य. मैसर्स बी डी एस इंडस्ट्रीज
- र. मैसर्स पूनम इंटरनेशनल
- ल. मैसर्स. रॉयल क्यूशन विनयल प्राडक्ट्स लिमि.
- व. मैसर्स विनयल रॉयल प्लास्टिकोट्स लिमि

(ix) निम्नलिखित आयातकों ने निर्धारित प्रपत्र में आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:

- क. मैसर्स स्टरलिंग इम्पेक्स
- ख. मैसर्स शिव पोलिमर्स
- ग. मैसर्स किवी ओवरसिस
- घ. मैसर्स आर एम जी पोलिविनिल इण्डिया लिमि.
- ङ. मैसर्स स्वास्तिक पॉलीविनिल्स प्रा. लि.
- च. मैसर्स सोनार्ग प्लास्टिक्स प्रा. लि.
- छ. मैसर्स कक्लपना इंडस्ट्रीज

- ज. मैसर्स बिहानी मैनुफैक्चरिंग कं. प्रा. लि.
 झ. मैसर्स शंकला इंडस्ट्रीज
 ज. मैसर्स बिहानी ग्रुप
- (x) निम्नलिखित पक्षकारों से भी अनुरोध प्राप्त हुए थे।
- i. आई ई ई एम ए
 ii. ऑल इण्डिया प्लास्टिसाइजर्स कंज्यूमर एसोसिएशन
 iii. टाईपेई इकोनोमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इण्डिया
- (xi) ऊपर में उल्लेख किए गए प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों के अलावा इस जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों की ओर से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हालांकि, आयातक की प्रश्नावली निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा दायर नहीं की गई है।
- i. मैसर्स बीटापोली कोट्स प्रा. लिमि.
 ii. मैसर्स यस इंटरप्राइस
 iii. मैसर्स टक्कर इंडस्ट्रीज
 iv. मैसर्स यशराज इंडस्ट्रीज
 v. मैसर्स गोपाल प्लास्टिक्स
 vi. मैसर्स हेवल्स
 vii. मैसर्स एस ए सी पोलिमर्स
 viii. मैसर्स बी एल एस पोलिमर्स लिमि.
 ix. मैसर्स के ई आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 x. मैसर्स यश पोलि इंडस्ट्रीज
 xi. मैसर्स फिनालेक्स केबल्स लिमिटेड
 xii. मैसर्स एस ए सी पोलिमर्स लिमिटेड
 xiii. मैसर्स टेक्नोविनयल पोलिमर्स इण्डिया लिमिटेड
 xiv. मैसर्स जे एंड के इंडस्ट्रीज
 xv. मैसर्स फारकॉम केवल सिस्टमस प्राइवेट लिमिटेड
 xvi. मैसर्स कोनार्क पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
 xvii. मैसर्स रियलटो केबल्स प्रा. लिमि.
 xviii. मैसर्स दुगर पोलिमर्स लिमिटेड
 xix. मैसर्स पोलीनोवा
 xx. मैसर्स वेलसेट
 xxi. मैसर्स करेंसी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
 xxii. मैसर्स पोलियस्टर इंडस्ट्रीज
 xxiii. आल इण्डिया प्लास्टिसाइजर्स कंज्यूमर्स एसोसिएशन
 xxiv. मैसर्स प्लास्टइम्पेक्स
 xxv. मैसर्स मारवेल विनयल लिमि.
- (xii) निम्नलिखित उपभोक्ताओं/ प्रयोक्ताओं ने इस जांच के आरंभ होने के पश्चात पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने के लिए घरेलू उद्योग के दावे का समर्थन करते हुए पत्र प्रस्तुत किया।

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	क्र. सं.	पक्षकार का नाम
1	आशीष एग्रो प्लास्ट प्रा. लिमि.	40	जैनको इंटरप्राइसेस
2	आशीष पोलि प्लास्ट लिमि.	41	कृष्णा इंटरप्राइसेस
3	आर्शीवाद पोलिमर्स	42	निशान मार्केटिंग
4	डी. आर. जी. लेदर क्लोथ प्रा. लिमि.	43	प्लास्टि पैक
5	डावर सन्स प्रा. लिमि.	44	प्रिटसन्स पोलिमर्स
6	डूट्रान प्लास्टिक्स (बारुच)	45	राको मर्केन्टाइल ट्रेडर्स
7	डूट्रान प्लास्टिक्स लिमि	46	एस. गोपाल कामथ (कोचिन) प्रा. लिमि.
8	ईएलईएस विनयल प्रा. लिमि.	47	वरुन आर्गेनिक्स
9	इवा सिंथेटिक्स एल एल पी	48	एसी पोलिकोटर्स प्रा. लिमि.
10	फ्रंटियर एलॉयस	49	एसी यूनिक्वोटर्स प्रा. लिमि.
11	गजिन्द्र प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	50	एलर्ट इण्डिया
12	जे एंड के इंडस्ट्रीज	51	एल्फा मेडिकेयर एंड डिवाइसेज प्रा. लिमि.
13	जनता फूटवियर प्रा. लिमि.	52	एल्फा आर्गेनिक्स
14	कमल पोलिमर्स	53	एमको इण्डिया लिमि.
15	लोड्स इंडस्ट्रीज	54	आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमि.
16	लक्की प्लास्ट लिमि.	55	अरविंद प्लास्टिक उद्योग
17	मेडिकेयर इंडस्ट्रीज	56	बजाज पोलिमर्स
18	नेशनल हेल्थकेयर	57	बंसल पोलिप्लास्ट प्रा. लिमि.
19	नेशनल इंडस्ट्रीज	58	धन लक्ष्मी इंडस्ट्रीज
20	नेशनल प्रॉडक्ट्स	59	फलीटगार्ड फिल्टर प्रा. लिमि.
21	निप्पन पोलिमर्स प्रा. लिमि.	60	हरिहोम पोलिमर्स
22	ओपेरा पोलिमर्स	61	हिल्सन फूटवियर प्रा. लिमि.
23	पारस उद्योग	62	आई. जी. पेट्रोकेमिकल्स लिमि.
24	पार्श्व पोलिमर्स प्रा. लिमि.	63	जैन केमिकल्स
25	पाटकर एक्सट्रूजन्स प्रा. लिमि.	64	जयाश्री पोलिमर्स प्रा. लिमि.
26	पोलिफाइन्स इण्डिया लिमि	65	महालक्ष्मी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज
27	प्रभात इंडस्ट्रीज	66	मेजर फूटवेयर्स प्रा. लिमि.
28	रेनबो इंटरप्राइजेज	67	नेशनल ट्रेडर्स
29	रामा व्यापार प्रा. लिमि.	68	पारस उद्योग
30	रिधि सिद्धी पोलिमर्स	69	पाटफिंडर वूडप्लास्ट
31	शक्ति पोलिमर्स	70	प्लास्टीलामी कोट्स प्रा. लिमि.
32	श्री श्याम पोलिकोट्स प्रा. लिमि.	71	प्रगति इंटरप्राइजेज
33	सॉफ्ट टर्क	72	पीवीसी कबटर्स इण्डिया प्रा. लिमि.
34	श्री डी. आर. जी. विनयल इंडस्ट्रीज	73	रेक्सिटाइल लेदर प्रा. लिमि.
35	टेकमार्क केबल्स इण्डिया (प्रा.) लिमि.	74	रोमन इंडस्ट्रीज एल एल पी
36	त्रिरुपति प्लास्टिक्स	75	शिथल टेक्स प्रा. लिमि.
37	यश इंटरप्राइसेस	76	स्टेडर्ड फेक्स प्रा. लिमि.
38	हरियाणा प्लास्टिक	77	तिरुमलेई केमिकल्स लिमि.
39	जैन केमिकल एंड प्लास्टिक्स	78	वंदना इंटरप्राइजेज प्रा. लिमि.

(xiii) प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक याचिका के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

- (xiv) वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन देन वार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है और इन लेन देन की उचित जांच के पश्चात विश्लेषण को आवश्यक बताया है।
- (xv) सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांत (जी ए ए पी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत तथा उसका निर्माण करने एवं उसकी बिक्री करने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एन आई पी) इस प्रकार से तय की गयी है जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में अपेक्षाकृत कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (xvi) आवेदक घरेलू उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का उस सीमा तक सत्यापन जिस सीमा तक इसे आवश्यक समझा गया, प्राधिकारी द्वारा किया गया था, जहां भी लागू हो आवश्यक सुधार के साथ केवल इस प्रकार की सत्यापित सूचना पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के उद्देश्य से विचार किया गया है।
- (xvii) वर्तमान पाटनरोधी जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 (12 महीने) की अवधि है। हालांकि, क्षति की जांच की अवधि 2013-14, 2014-15, 2015-16 की अवधि तथा जांच की अवधि मानी गई है।
- (xviii) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 22 दिसंबर, 2017 तथा उसके बाद 3 जनवरी, 2018 को आयोजित एक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी प्रदान किया। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, को सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए इन दृष्टिकोणों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें। इन पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोणों की प्रतियां प्राप्त करें और अपने खंडन को प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।
- (xix) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गए मुद्दों के आधार पर सार्वजनिक सुनवाई के बाद घरेलू उद्योग को दिनांक 28 मार्च, 2018 के ई-मेल के द्वारा मुख्य रूप से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में साक्ष्य के साथ स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि क्या कानाटोल-800 और कोनाटोल 800 एफ जी, स्टेब्लाइज्ड सॉफ्टनर कोनाटोल-800 और स्टेब्लाइज्ड सॉफ्टनर कोनाटोल-800 एफ जी के अलावा अन्य सभी कानाटोल कोरपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष जांच की अवधि के लिए डी ओ पी के रूप में कुल कारोबार के उनके प्रकटन और अन्य उत्पादों की बिक्री और उत्पादन के प्रकटन के संबंध में विचाराधीन उत्पाद नहीं होते हैं।
- (xx) हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों और प्रत्युत्तरों में दिए गए तर्कों वर्तमान जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- (xxi) इस जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, जहां भी उन्हें संगत पाया गया, किए गए अनुरोधों का समाधान प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया है।
- (xxii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, इस प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे जहां भी आवश्यक हुआ को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना पर गोपनीय के रूप में माना गया है और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें।
- (xxiii) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना देने से इन्कार किया है अथवा अन्य प्रकार से इसे उपलब्ध नहीं कराया है अथवा पर्याप्त रूप से जांच में अवरोध उत्पन्न किया है, प्राधिकारी ने इस प्रकार के पक्षकारों को गैर सहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस जांच परिणाम को रिकार्ड किया है।
- (xxiv) ऊपर में दी गई नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को 12 अप्रैल, 2018 को आवश्यक तथ्य प्रकट किए गए थे। 19 अप्रैल, 2018 तक टिप्पणियां मांगी गई थी। प्रकटन विवरण के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- (xxv) इस जांच परिणाम में*** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार की गई सूचना का द्योतक है।
- (xxvi) प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 67.95 रुपये है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. याचिकाकर्ता द्वारा दायर सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच शुरू की तथा विचाराधीन उत्पाद को "डायकिल फेथालेट (डी ओ पी)" के रूप में परिभाषित किया है। रसायनिक रूप से इसे बिस (2 – एथिलहेक्सिल) फिथालेट के रूप में जाना जाता है और इसका संक्षिप्त नाम डी ई एच पी के रूप में भी है। डायकिल फिथालेट रासायनिक सूत्र सी8एच4

(सी8एच17सीओओ) 2 वाला आर्गेनिक कम्पाउंड है और इसे 29173920 में सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के तहत अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया था।

ख. 1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

6. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किए गए अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :

- (i) घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की बिक्री निम्नलिखित ब्रांड नामों अर्थात् कानाटोल 800, कोनाटोल 800एस, कानाटोल 800एफ जी और स्टेब्लाइज्ड सॉफ्टनर के 800 के अंतर्गत कर रहा है।
- (ii) घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री "प्लास्टिसाइज्ड सॉफ्टनर" के रूप में नहीं कर रहा है। घरेलू उद्योग ने कभी यह नहीं कहा कि वे 'प्लास्टिसाइज्ड सॉफ्टनर' के नाम के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कर रहे हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का सत्यापन पहले ही कर लिया है। घरेलू उद्योग 'प्लास्टिसाइज्ड सॉफ्टनर' के रूप में अपने उत्पाद की बिक्री नहीं कर रहा है।
- (iii) डी पी ओ और कानाटोल 8080 दो अलग अलग उत्पाद हैं और इनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता है। जबकि, डी ओ पी फेथालेट आधारित प्लास्टिसाइजर और कानाटोल 8080 फेथालेट आधारित प्लास्टिसाइजर नहीं है। दोनों उत्पादों के लिए कच्चा माल अलग अलग होता है। डी ओ पी और कानाटोल 8080 दोनों की तकनीकी सीट से यह देखा जा सकता है कि दोनों उत्पादों का पूर्ण रूप से अलग लक्षण हैं। दोनों उत्पादों के उपयोग भी अलग हैं। जबकि डी ओ पी का उपयोग लचीले विनाइल उत्पादों का निर्माण करने के लिए किया जाता है, कानाटोल 8080 का उपयोग विनायल ग्लब्स, वॉल कवरिंग आदि के लिए किया जाता है। जहां तक डी आई एन पी, डी आई ओ पी, डी ओ टी पी (कानाटोल 8080) और कानाटोल 1056 का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि ये उत्पाद न केवल लक्षणों में अलग अलग हैं बल्कि इनके उपयोग भी अलग-अलग हैं।
- (iv) डी ओ टी पी पर यू एस के जांच परिणामों का संदर्भ लिया गया है जिसमें यू एस आई टी सी ने उल्लेख किया कि डी ओ टी पी और डी आई एन पी का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे रासायनिक रूप से अलग अलग उत्पाद होते हैं। ये दो उत्पाद मोलिक्यूलर भार, रासायनिक सूत्र, कच्चा माल और नशीलापन में अलग अलग हैं।
- (v) घरेलू उद्योग ने अपने आंकड़ों में कानाटोल 800 की बिक्री और उत्पादन को शामिल किया है। कानाटोल 800 डी ओ पी के एक प्रकार के अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने विभिन्न व्यापार/ ब्रांड नामों का उपयोग कर डी ओ पी का उत्पादन किया है और इनकी बिक्री की है। याचिकाकर्ता ने इस याचिका में उत्पादन किए गए डी ओ पी और याचिकाकर्ता द्वारा बेची गई डी ओ पी के विभिन्न प्रकारों अथवा रूपों के संबंध में सूचना प्रदान की है।
- (vi) घरेलू उद्योग ने डी ओ पी के विभिन्न श्रेणियों के लिए सभी आंकड़े उपलब्ध कराये हैं। जहां तक व्यवहार्य प्रतिस्थानापन्न का प्रश्न है, यह दोहराया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए विचाराधीन उत्पाद का कोई व्यवहार्य प्रतिस्थानापन्न नहीं है। उसी उत्पाद के अलग अलग ब्रांड नामों का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि वे इस उत्पाद के व्यवहार्य प्रतिस्थानापन्न हैं।
- (vii) जहां तक, डी आई एन पी, डी बी पी, टी ओ टी एम, डी आई बी पी और डीआई (2-प्रोपीहेप्टिल) फेथालेट का प्रश्न है, यह देखा जा सकता है कि ये उत्पाद न केवल लक्षणों में अलग अलग हैं बल्कि इनके उपयोग भी अलग अलग हैं। घरेलू उद्योग ने मुख्य इकाई सिलवासा से शीर्ष 29173920 के अंतर्गत डी ओ पी की बिक्री की है और डी ओ पी की बिक्री उसी स्टेब्लाइज्ड सॉफ्टनर के-800 के नाम पर इकाई-111 सिलवासा से शीर्ष 29173400 के अंतर्गत की है। घरेलू उद्योग ने उसे सिद्ध करने के लिए ई आर-1 की प्रतियां उपलब्ध कराई हैं। स्टेब्लाइज्ड सॉफ्टनर विचाराधीन उत्पाद रूपों में से एक है और उसके आंकड़े शामिल किए गए हैं। वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिसाइजर ही नहीं हैं बल्कि डी ओ पी भी है।
- (viii) पायल पेट्रोकेम प्रा. प्लास्टिसाइजर के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन कर रहा है। जहां तक पायल पेट्रोकेम प्रा. के उत्पादन आंकड़ों की स्टीकता का प्रश्न, घरेलू उद्योग ने पत्र उपलब्ध कराया है जो उक्त कम्पनी द्वारा घरेलू उद्योग के कानूनी प्रतिनिधि को डी ओ पी के अपने उत्पादन की सूचना उपलब्ध कराते हुए दिया गया है।
- (ix) घरेलू उद्योग ने केवल डी ओ पी पर पाटनरोधी शुल्क की मांग की है और न कि सभी फेथालेट प्लास्टिसाइजरो पर।

ख. 2 निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :

- (i) घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद और अन्य फेथालेट प्लास्टिसाइजर्स और विशिष्ट प्लास्टिसाइजर्स की बिक्री "प्लास्टिक सॉफ्टनर्स" के गुप्त नाम के अंतर्गत नहीं कर रहा है। घरेलू उद्योग दो अथवा उससे अधिक उत्पादों जिसमें से एक उत्पाद विचाराधीन उत्पाद है और दूसरा गैर विचाराधीन उत्पाद है, की बिक्री और उसका बीजक उसी नाम के अंतर्गत नहीं बना रहा है, उनके उत्पादन और बिक्री के संबंधित व्यौरों की प्रमाणिकता के संबंध में संदेह है। सुनवाई के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया है कि "प्लास्टिक सॉफ्टनर्स" के संबंध में बीजकों को विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया गया है। रिकार्ड पर ऐसी कोई व्याख्या नहीं है कि इस प्रकार के घरेलू उद्योग ने "प्लास्टिक सॉफ्टनर्स" के नाम के अंतर्गत देखी गई गैर विचाराधीन उत्पाद पर विचार किया है।
- (ii) घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद की प्रतिस्थापनियता के मुद्दों के संबंध में बिल्कुल गलत घोषणाएं की गई हैं। विशिष्ट प्लास्टिसाइजर कानाटोल 8080 विचाराधीन उत्पाद का एक संपूर्ण प्रतिस्थानापन्न है, यह उल्लेख किया जाता है कि कुछ छोटे छोटे संरचनात्मक अंतरों को छोड़कर इन दोनों के बीच कोई "तकनीकी अथवा रासायनिक" अंतर नहीं है और कानाटोल 8080 वास्तव में विचाराधीन उत्पाद का एक बेहतर प्रतिस्थानापन्न है। विचाराधीन उत्पाद के कम से कम पांच और प्रतिस्थानापन्न हैं जो डी आई एन पी, डी ओई ओ पी, डी आई एम टी, डी ओ टी पी (कानाटोल 8080) और कानाटोल 1056 हैं। घरेलू उद्योग यह दावा करते हुए उन्हें अपेक्षाकृत सस्ते दर पर बिक्री करते हैं कि वे विचाराधीन उत्पाद की तुलना में बेहतर इनपुट्स का निष्पादन करते हैं।
- (iii) जांच शुरूआत गलत सूचना पर आधारित है। घरेलू उद्योग ने डी ओ पी के नाम के अंतर्गत बेची गई वस्तुओं के संबंध में ही सूचना उपलब्ध कराई है और कानाटोल 8080 के ब्रांड नाम जो स्वीकार्य रूप से डी ओ पी है, के अंतर्गत डी ओ पी के बिक्री को प्रकट करने में असफल रहा है। यदि बिक्री और उत्पादन से संबंधित सूचना को सही रूप में दर्शाया जाए तब जांच की अवधि के दौरान कोई गिरावट नहीं होगी।
- (iv) घरेलू उद्योग ने इस याचिका में डी ओ पी की सभी श्रेणियों को प्रकट नहीं किया है जिसकी बिक्री वे कर रहे हैं और एक गलत कथन "विचाराधीन उत्पाद के लिए तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से कोई व्यवहार्य प्रतिस्थानापन्न नहीं है" इस याचिका में दिया है। मैसर्स के एल जे प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड विभिन्न नामों अर्थात् "प्लास्टिसाइज्ड सॉफ्टनर/ स्टेब्लाइज्ड सॉफ्टनर्स" आदि के अंतर्गत डी ओ पी का निर्माण अथवा बिक्री कर रहा है, जिस इस याचिका में कहीं भी प्रकट नहीं किया गया है।
- (v) डी ओ पी विभिन्न प्रतिस्थानापन्न डी आई एन पी, डी बी पी, टी ओ टी एम, डी आई बी पी और डीआई (2-प्रोपीहेप्टिल) फेथालेट हैं। याचिकाकर्ता इन प्लास्टिसाइजर्स की बिक्री व्यापार नाम – कानाटोल 900 – डी आई एन पी, कानाटोल 3800, टी ओ टी एम, कानाटोल 8005 (डी ओ पी सुपर), कानाटोल 1010 कानाटोल 400 (एम) के अंतर्गत कर रहा है। याचिकाकर्ता अन्य फेथालेट प्लास्टिसाइजर्स की बिक्री कर रहा है जो डी ओ पी के आंशिक प्रतिस्थानापन्न हैं, के एल जे के अपने ब्रोसर से स्पष्ट है।
- (vi) घरेलू उद्योग ने शुल्क शीर्ष 29173920 के संबंध में उपलब्ध कराये गए आंकड़े को सीमित कर दिया है जबकि वे अन्य शुल्क शीर्ष के अंतर्गत भी जैसे शुल्क शीर्ष 29173400 के अंतर्गत डी ओ पी का आयात कर रहा है और उसकी बिक्री कर रहा है। घरेलू उद्योग प्लास्टिसाइज्ड/ स्टेब्लाइज्ड साफनर के व्यापार नाम के अंतर्गत डी ओ पी का संवर्धन कर रहा है। याचिकाकर्ता ने आंकड़ों को प्रशुल्क शीर्ष 29173920 के तहत जोड़कर प्राधिकारी को भ्रमित किया है, जबकि वे डीओपी का आयात एवं बिक्री प्रशुल्क शीर्ष 29173400 के तहत भी करते रहे हैं।
- (vii) अन्य उत्पादकों के उत्पादन आंकड़े गलत और भ्रामक हैं। वर्ष 2015-16 के लिए मैसर्स पायल पेट्रोकेम प्रा. लिमि. की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, प्लास्टिसाइजर्स की बिक्री 419 करोड़ रुपए अर्थात् 60,000 मी. टन है। इस याचिका में अन्य उत्पादकों की यह बिक्री 25,421 मी. टन दर्शाई गई है जो किसी एक उत्पादक की बिक्री को ही नहीं दर्शाता है।
- (viii) विशेषताओं, तकनीकी लक्षणों, उपयोगों, प्रयोक्ताओं, सांझा संयंत्र और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनियता के मामले में विचाराधीन उत्पाद का समान उत्पाद है। विचाराधीन उत्पाद और स्टेब्लाइज्ड सॉफ्टनर का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है और ये समान वस्तु हैं, दोनों का निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है। स्टेब्लाइज्ड सॉफ्टनर विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया जा सकता है और इसे जांच की परिधि से बाहर नहीं रखा जा सकता है। घरेलू उद्योग इन सामानों (डी ओ पी के रूप में स्टेब्लाइज्ड सॉफ्टनर) को देखने के लिए अनेक एच एस कोड का उपयोग किया होगा। के एल जे: उत्पाद कानाटोल 800: एच एस कोड 29173400 है, पायल: उत्पाद: पेयफेक्सपीएसओ(ओ) : एच एस कोड 29173990 है और रिटजी: उत्पाद: रिटजी 100: एच एस कोड 29173990 है। डी ओ पी एक प्रकार का फेथालेट प्लास्टिसाइजर है और इस कारण विचाराधीन उत्पाद अपने आप में डी ओ पी नहीं है बल्कि यह फेथालेट प्लास्टिसाइजर्स है।

- (ix) घरेलू उद्योग का कथन अपने आप में गलत है कि कानाटोल 8080 एक प्रकार डी ओ पी है और याचिकाकर्ता ने विभिन्न व्यापार/ ब्रांड नामों के अंतर्गत डी ओ पी का उत्पादन किया है और उसकी बिक्री की है। डी ओ पी के उपलब्ध प्रतिस्थानापन्नों के संबंध में कोई औचित्य नहीं दिया गया है। उत्पाद आकंड़ा शीर्ष पर भरोसा किया गया है जिसमें कानाटोल 8080 डी ओ पी का एक प्रतिस्थानापन्न के रूप में है और इसमें "भौतिक रासायनिक लक्षणों में प्रायः किसी अंतर" का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (x) घरेलू उद्योग ने यह माना है कि अन्य उत्पाद जैसे स्टेब्लाइज्ड सॉफ्टनर यद्यपि आयात किए गए उत्पाद के अनुरूप नहीं है परंतु इसकी विशेषताएं विचाराधीन उत्पाद के जैसी ही बिलकुल है और यह भौतिक रूप से और वाणिज्यिक रूप से विचाराधीन उत्पाद के प्रतिस्थापन के योग्य है। इस आधार पर स्टेब्लाइज्ड सॉफ्टनर वर्तमान जांच के भाग के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के डी ओ पी के उत्पादन और बिक्री जिसे अलग अलग अध्याय शीर्षों/ ब्रांड नामों के अंतर्गत की गई है, की जांच उन्हें उत्पाद संबंधी अभिलेखों से मिलान करते हुए तथा इस याचिकाकर्ता के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार की जानी चाहिए।
- (xi) यदि डी ओ पी पर ये शुल्क लगाए जाते हैं तब याचिकाकर्ता प्रतिस्थानापन्नों की कीमतों को बढ़ायेगा जिसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ताओं का कठिनाई होगी। याचिकाकर्ता डी आई एन पी की बिक्री का संवर्धन उन्हें डी ओ पी के प्रतिस्थानापन्न के रूप में दावा करते हुए कर रहा है। याचिकाकर्ता ने इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है कि डी ओ पी का एक प्रतिस्थानापन्न डी आई एन पी है, केवल समान वस्तु का मुद्दा उठाया गया है। भारतीय उत्पादकों के ई-मेल पर विश्वास किया गया है जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि डी ओ पी का एक प्रतिस्थानापन्न डी आई एन पी है।
- (xii) बाजार में उपलब्ध डी ओ पी का प्रतिस्थानापन्न डाई आईसोनोनिल फेथालेट (डी आई एन पी), डाईब्यूटिल फेथालेट (डी बी पी), ट्राई आक्साइल ट्रीमेलिटेट (टी ओ टी एम), डाई आइसो ब्यूटिल फेथालेट (डी आई बी पी), डाई (2-प्रोफिहेटिल) फेथालेट हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता व्यापार नामों के अंतर्गत इन प्लास्टिसाइजरो की बिक्री कर रहे हैं जो कानाटोल 900 – डी आई एन पी, कानाटोल 3800 – टी ओ टी एम, कानाटोल 800 एस (डी ओ पी सुपर), कानाटोल, 1010, कानाटोल 400 (एम) हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अपने केटालॉग में स्वीकार किया है कि ये आंशिक स्थानापन्न कानाटोल – 800एस, कानाटोल – 800, कानाटोल – 900, कानाटोल – 1001, कानाटोल – 1010, कानाटोल – 1210, कानाटोल – 1212, कानाटोल – 400 (I), कानाटोल – 400 (एम), कानाटोल – 40 (एन), कानाटोल – 1056, कानाटोल – 8ए, कानाटोल – 8एस, कानाटोल – 40 एस, कानाटोल – 80 एस, कानाटोल – 4 एम, कानाटोल – 4 एस, कानाटोल – टी एम 8-10एल, कानाटोल – 3800, कानाटोल – 3430 ई, कानाटोल – 8080, कानाटोल – 3400 एसी हैं।

ख. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा पेशकेश किए गए विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कार्यक्षेत्र के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट कर लिया है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि :
- (i) वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद "डायकिल फेथालेट (डी ओ पी)"। इसे रासायनिक रूप से बिस (2-हेथिहेक्सिल) फेथालेट के रूप में जाना जाता है और इसका संक्षिप्त नाम डी ई एच पी के रूप में है। डायकिल फेथालेट रासायनिक सूत्र सी8एच4 (सी8एच17सीओओ) 2 के साथ एक सार्वजनिक कम्पाउंट है। इसे (बिस (2-हेथिहेक्सिल) नेंजीन 1, 2-डायकार्बोसिलेट) के रूप में भी जाना जाता है।
- (ii) विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद पर विचार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दिनांक 1 जून, 2017 के जांच प्रारंभन संबंधी अधिसूचना के समय किया गया है जिसमें विचाराधीन उत्पाद को प्रशुल्क शीर्ष 29173920 के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- (iii) घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद में डी ओ टी पी (कानाटोल 8080), डी आई ओ पी, डी आई एम टी, कानाटोल 1056, डी आई एन पी (कानाटोल 900), टी ओ टी एम (कानाटोल 3800), डी बी पी और डी आई बी पी शामिल नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने डायकिल फेथालेट (डी ओ पी) पर पाटनरोधी शुल्क की मांग की है और विचाराधीन उत्पाद के कार्य निष्पादन के संबंध में क्षति का दावा किया है।
- (iv) विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने स्टेब्लाइज्ड सॉफ्टनर के विभिन्न प्रकारों के संबंध में इन मुद्दों को उठाया है और उल्लेख किया है कि ये सभी स्टेब्लाइज्ड सॉफ्टनर डी ओ पी हैं और इनकी बिक्री ब्रांड कानाटोल के अंतर्गत की जा रही है। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता सहित विभिन्न घरेलू उत्पादकों द्वारा बनाए गए बीजकों की प्रति प्रस्तुत की है कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्राधिकारी के समक्ष सही सूचना प्रस्तुत नहीं की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग ने प्रशुल्क शीर्ष 29173400 के तहत सूचना प्रकट नहीं की है क्योंकि प्रशुल्क शीर्ष 29173920 के संबंध में सीमित सूचना उत्पाद को डीओपी के रूप

में मानते हुए जांच की शुरुआत के समय दी गई है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने यह साक्ष्य उपलब्ध कराये हैं कि स्टेबलाइज्ड सॉफ्टनर के 800 के अलावा, अन्य स्टेबलाइज्ड सॉफ्टनर में, जिसका उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा की जा रही है, विचाराधीन उत्पाद अर्थात् डी. ओ. पी. नहीं है। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने रासायनिक संरचना, मोलिक्यूर संरचना, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, कार्बन चैन और विशिष्ट प्रयोक्ता अनुप्रयोग के संदर्भ में उत्पाद के विनिर्देशन के संबंध में सूचना उपलब्ध दायर की है।

- (v) उन तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए जिनको विरोधी पक्षकारों ने उठाया है, प्राधिकारी ने केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सी आई पी ई टी) के दृष्टिकोण को प्राप्त किया है। सी आई पी ई टी ने 5 अप्रैल, 2018 के अपने पत्र में उल्लेख किया है कि, "सामान्य रूप से फेथालेट प्लास्टिसाइजर्स का बहुधा उपयोग विभिन्न उपयोगों के लिए प्लास्टिसाइज्ड/ लचीले पी वी सी उत्पादों को बनाने के लिए पी वी सी उद्योगों में किया जाता है। के एल जी ग्रुप (के-800 और के-100 एफजी) से प्लास्टिकसाइजर्स का उपयोग पी वी सी रेसिंग में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है और यह इन उत्पादों में प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों पर निर्भर करता है। जब हम इन उत्पादों की तलाश कर रहे होते हैं जहां दुर्गंध रहित अपेक्षाकृत अधिक मात्रा, संवेदनशीलता, कम उतार चढ़ाव आदि जैसे लक्षणों को महत्वपूर्ण माना जाता है, तब वे कंपनी के ब्रोचर में दी गई सूचना के अनुसार सर्वोत्तम विकल्प हो सकता है। के एल जे ग्रुप के केटालॉग में, अन्य फेथालेट उत्पादों में इस प्रकार की विशेषताएं नहीं होती हैं और इस कारण से इसकी सिफारिश नहीं की जा सकती है। हालांकि, के-800 के रूप में समान लक्षण प्रोफाइल के साथ फेथालेट (किसी स्रोत से) का उपयोग इस संबंध में अंतिम उत्पाद की उचित गुणवत्ता की जांच के बाद इस प्रकार के उपयोगों के लिए किया जाता है। इस ब्रोचर में दिए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि इस सूची में ऐसा कोई फेथालेट उत्पाद नहीं है जो अंतिम उत्पाद के इस प्रकार के लक्षण का मुकाबला कर सके।" प्रकटन विवरण की टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने पॉलीमर एवं सरफेस इंजीनियरिंग विभाग, रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीटी), मुंबई से ई-मेल उत्तर यह उल्लिखित करते हुए दायर किया है कि के 800 और के 800 एफजी में विशिष्ट गुणधर्म अर्थात् ऑडर में कम, कम वोलेटिलिटी और अधिक मात्रात्मक प्रतिरोधकता, होते हैं जो उन्हें केएलजे उत्पाद सूची में उल्लिखितानुसार अन्य फिथालेटों से भिन्न बनाते हैं। तथापि, पीवीसी कंपाउंडिंग में भिन्न-भिन्न मात्राएं हो सकती हैं। किसी अन्य स्रोत से फिथालेट को 800 और के 800 एफजी के रूप में समीपस्थ मेल खाने वाले गुणधर्मों के साथ अंतिम प्रयोक्ताओं की समुचित गुणवत्ता जांच के बाद समान अनुप्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सीआईपीईटी और आईसीटी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करने में सक्षम नहीं हैं कि अन्य स्टेबलाइज्ड सॉफ्टनर डीओपी नहीं है, जैसा कि हितवद्ध पक्षकारों द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है। यहां तक कि याचिकाकर्ता साक्ष्य के साथ यह सिद्ध नहीं कर पाए कि अन्य स्टेबलाइज्ड सॉफ्टनर का प्रयोग अन्य विशिष्ट प्रयोगों/अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है और उनका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गए मुद्दे को सिद्ध करने अथवा उसे निरस्त करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका कि अन्य स्टेबलाइज्ड सॉफ्टनर जिनकी बिक्री कानाटोल के रूप में की जा रही है, डी ओ पी नहीं होता है और उसका प्रयोग सामान्य अनुप्रयोग के लिए नहीं किया जा सकता।

- (vi) जहां तक डी ओ पी के उत्पादन और बिक्री प्राप्त करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न एच एस कोड का प्रश्न है, घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि उनके पास विचाराधीन उत्पादन और बिक्री के लिए दो इकाईयां नामतः मुख्य इकाई और इकाई 3 हैं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि मुख्य इकाई से याचिकाकर्ता ब्रांड नाम "कानाटोल 800 जो एच एस कोड 29173920 के अंतर्गत 100 प्रतिशत डी ओ पी है और इकाई 3 से याचिकाकर्ता डी ओ पी का उत्पादन करता है और इसकी बिक्री ब्रांड नाम "स्टेबलाइज्ड सॉफ्टनर" जिसमें एच एस कोड 29173400 के अंतर्गत 99.5 प्रतिशत के रूप में (ऑर्थोफेथालेट्स का अन्य स्टेप) के अंतर्गत करता है" के साथ विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करता है। हालांकि, अन्य हितवद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि और कानाटोल के स्टेबलाइज्ड सॉफ्टनर के बीजकों की प्रतियां उपलब्ध कराई हैं कि याचिकाकर्ता ने एच एस कोड 29173400 के अंतर्गत बिक्री है। घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आयात आंकड़ों और एचएस कोड 29173920 के तहत एकत्रित किए गए आंकड़ों के मद्देनजर प्राधिकारी अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए डीओपी की पूरी सूचना के बजाए केवल इस शीर्ष के तहत सूचना के साथ ही इस जांच पर आगे बढ़े और जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री एचएस कोड 29173400 के तहत तथा उसी आईटीसीएचएस कोड के तहत अन्य स्टेबलाइज्ड सॉफ्टनरों की भी की गई है। जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विरोधीभासी सूचना के साथ आए हैं और विचाराधीन उत्पाद डीओपी को केवल डीओपी और कानाटोल 800 होने को औचित्यपूर्ण नहीं बता पाए हैं।

- (vii) उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "डायक्विल फेथालेट (डी ओ पी)". इसे रासायनिक रूप से बिस (2-हेथिहेक्सिल) फेथालेट के रूप में जाना जाता है और इसका संक्षिप्त नाम डी ई एच पी के रूप में है। डायक्विल फेथालेट रासायनिक सूत्र सी8एच4 (सी8एच17सीओओ) 2 के साथ एक सार्वजनिक कम्पाउंट है। यह सबसे महत्वपूर्ण (फेथालेट) है और यह फथालेटिक एसिड और शाखाबद्ध 2-एथिल हेक्सानोल का डाइस्टर है। इस रंग रहित विसकस तरल पदार्थ को तेल में मिलाया जा सकता है लेकिन पानी में नहीं। इसमें अच्छी प्लास्टिसाइजिंग लक्षण होते हैं। संबद्ध वस्तुओं का व्यापक रूप से उपयोग पी वी सी की बनी वस्तुओं के निर्माण में एक प्लास्टिसाइजर के रूप में किया जाता है। प्लास्टिक में आवश्यकताओं के आधार पर डी ओ पी का 1 प्रतिशत से 40 प्रतिशत हो सकता है। इसका उपयोग एक हाइड्रोलीक तरल पदार्थ के रूप में तथा केपेसिटर में एक डाय इलेक्ट्रिक तरल पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग ग्लो स्टिक में एक घुलनशील पदार्थ के रूप में भी होता है क्योंकि इसमें उपयुक्त लक्षण होते हैं और इसकी लागत कम होती है। इस उत्पाद की बिक्री प्राथमिक रूप से वजन के आधार पर की जाती है। विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत 29173920 और 29173400 में वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक हैं और यह विचाराधीन उत्पाद और वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

ग. घरेलू उद्योग का कार्य क्षेत्र एवं स्थान

ग. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

9. घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र एवं स्थान के संबंध में किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :
- वर्तमान जांच में याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और यदि घरेलू उद्योग के इस दावे का खण्डन नहीं किया जाता है तब अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन के संबंध में कोई तर्क बिना किसी आधार अथवा संगतता के हैं।
 - यदि मैसर्स रिटजी केमिकल्स प्रा. लिमि. के उत्पादन को भी शामिल किया जाता है तब याचिका दायर करने वाले घरेलू उद्योग अब भी भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा होता है। वर्तमान जांच में याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होता है।
 - याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। हालांकि याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के आयातों से संबंधित है।
 - अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन आंकड़े घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार उपलब्ध कराये गए हैं।
 - याचिका दायर करने वाले घरेलू उद्योग इन संबद्ध वस्तुओं के जो आयातकों से संबंधित है। याचिका दायर करने वाले घरेलू उद्योग को (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विगत में दिए गए निर्णयों (ii) भारत में इस कंपनी का उत्पाद बहुत अधिक होने के कारण (iii) कंपनी का ध्यान घरेलू उत्पादक पर होने के कारण (iv) संबंधित कंपनियों द्वारा किए गए आयात कुल आयात 0.73 प्रतिशत होता है, भारतीय उत्पादन का 0.59 प्रतिशत और जांच की अवधि में मांग का 0.51 प्रतिशत होता है, को देखते हुए उनकी संबंधित कंपनी द्वारा आयातों के बावजूद एक पात्र घरेलू उत्पादक के रूप में माना जाना चाहिए।

ग. 2 निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

10. निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र एवं स्थान के संबंध में किये गये अनुरोध नीचे दिए गए हैं :
- अन्य भारतीय उत्पादकों के नाम नहीं प्रकट किए गए हैं। मैसर्स रिटजी केमिकल्स प्रा. लिमि. (संयंत्र - दमन एवं जम्मु) जो डी ओ पी का एक उत्पादक है, को घरेलू उत्पादक के विवरण में शामिल नहीं किया गया है। यदि मैसर्स रिटजी केमिकल्स को जोड़ा जाता है, तब घरेलू उद्योग इस वर्तमान जांच में अपने स्थान को सिद्ध करने में असफल रहेगा और उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
 - याचिकाकर्ता स्वयं संबद्ध वस्तुओं के आयातक हैं। डी ओ पी को स्वयं आयात किया गया है और इसकी बिक्री याचिकाकर्ता द्वारा डी ओ पी का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त कच्चे माल के रूप में किया गया है और यह भारत में उपलब्ध नहीं है।
 - आवेदक संबद्ध देशों के आयातकों से संबंधित हैं। नियम 2(ख) का संदर्भ लिया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किए गए निर्णय अब अच्छे कानून नहीं हैं और उसका उपयोग किसी मोल तोल वाले मूल्य के लिए भी नहीं किया जा सकता है।

- (iv) घरेलू उद्योग द्वारा याचिका में यह तथ्य सामने आता है कि आवेदक का संबंध विचाराधीन उत्पादक के आयातकों से है। नियम 2(ख) के अनुसार, घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है यदि उनका स्वयं का आयात हो अथवा उनका संबंध आयातकों/ निर्यातकों से हो। घरेलू उद्योग द्वारा आयातकों/ निर्यातकों के साथ एक घरेलू उत्पादक के संबंध का दावा करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय और कोलकता उच्च न्यायालय के फैसलों पर विश्वास किया गया है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के रूप में घरेलू उत्पादक पर विचार करने के लिए अपने विवेकाधिकार को लागू करते हैं। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत किए गए निर्णयों से प्रभावित हुए बिना घरेलू उद्योग के मुद्दे के संबंध में निर्णय लें।
- (v) घरेलू उद्योग ने डी ओ पी उद्योग की तस्वीर को सामने रखा है जो "दो दशक" पुरानी है और इस कारण से यह वर्तमान जांच में संगत नहीं है। यह उल्लेख किया जाता है कि इस उद्योग ने पिछले 20 वर्षों से गिरावट देखी है परंतु पाटित आयात हाल के मूल के हैं। अंत में, याचिकाकर्ता का यह दावा कि केवल 5 कंपनियां विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में लगी हुई हैं, इस याचिका में दिए गए आंकड़ों के अनुरूप नहीं है।
- (vi) यह नोट किया जाना है कि वे उत्पादक जिन्होंने घरेलू उद्योग के रूप में अपने उत्पादन बंद कर दिए हैं, पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हैं बल्कि याचिकाकर्ता जो बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं और जिन्हें कोई क्षति नहीं हो रही है, विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क लगाए जाने के लिए प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए। इसके अलावा घरेलू उद्योग ने अन्य भारतीय उत्पादक, मैसर्स रिटजी केमिकल्स प्रा. लिमि., जिन्होंने पर्याप्त उत्पादन किया है, के नाम को प्रकट नहीं किया है। यदि उसे शामिल किया जाता है तब याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के स्थान को सिद्ध करने में असफल रहेगा। घरेलू उद्योग का यह दावा कि डी ओ पी के अन्य भारतीय उत्पादक पाटन के विरुद्ध आयात कर रहे हैं क्योंकि डी ओ पी का उत्पादन एवं बिक्री भारत में व्यवहार्य नहीं है, बिना किसी कानूनी एवं वास्तविक आधार के हैं।
- (vii) पिछले दो दशकों में इन कंपनियों को बंद किए जाने की वर्तमान जांच में कोई संगतता नहीं है। भारतीय उत्पादकों का उस कीमत जिस पर आयात किए गए और स्वदेशी डी ओ पी को लाया जाता है और उसकी बिक्री की जाती है सहित बाजार की गतिशीलता पर नियंत्रण है। इस कारण से, भारतीय उत्पादकों को लघु उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- (viii) घरेलू उद्योग द्वारा किया गया यह अनुरोध कि डी ओ पी के केवल 5 उत्पादक हैं सही नहीं है। मैसर्स रिटजी केमिकल्स प्रा. लिमि. पी सी एल ऑयल एंड सॉल्वेंट लिमि. का एक संबंधित स्थान है जो डी ओ पी के निर्माण में लगा हुआ है। मैसर्स रिटजी को निर्माताओं की सूची बाहर निकालकर, याचिकाकर्ता ने डी ओ पी के कुल उत्पादन को कम कर दिया है।
- (ix) मैसर्स के एल जे, मैसर्स रिटजी और मैसर्स पायल वर्क सहित सभी निर्माता एक साथ कार्य करते हैं जो उनके बीजकों और कीमत निर्धारण संबंधी नीतियों से स्पष्ट है। पूर्व में, वे अध्याय शीर्ष 2917 39 20 के अंतर्गत डी ओ पी के रूप में डी ओ पी के बिक्री कर रहे थे जबकि, हाल में पिछले 3 वर्षों से उन्होंने अलग अलग अध्याय शीर्षों 2917 34 00, 2917 39 90 और अलग अलग नामों के अंतर्गत डी ओ पी की बिक्री करना शुरू किया है। पाटन रोधी शुल्क के लिए याचिका डी ओ पी निर्माताओं के उत्पादन और बिक्री से संबंधित आंकड़ों को छुपाने और उसकी सम सूचना देने के स्पष्ट उद्देश्य से दायर की गई थी जिससे यह आसान रूप से विलोप करने योग्य हो जाए। हम विश्वास करते हैं कि बिक्री से संबंधित आंकड़े बहुत ही कम हैं और यह कि बिक्री की बहुत अधिक मात्रा को प्राधिकारी से दबाया गया है।

ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. नियम 2(ख) में नीचे दिए अनुसार प्रावधान है :-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

12. यह याचिका मैसर्स के एल जे प्लास्टिसाइजर्स लिमि. (के एल जे) द्वारा दायर किया गया था जो भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक बड़ा उत्पादक है। याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। हालांकि, याचिकाकर्ता इन संबद्ध वस्तुओं के दो आयातकों नामतः मैसर्स के एल जे आर्गेनिक लिमिटेड और मैसर्स के एल जे पोलिमर्स एंड केमिकल्स लिमि. से संबंधित है। संबंधित कंपनियों द्वारा किए गए आयात डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के अनुसार 945 मी. टन है। संबंधित कंपनियों द्वारा किए

- गए आयात भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों, विचाराधीन उत्पाद के इसके उत्पादन और खपत की तुलना में मामूली हिस्सा होता है। याचिकाकर्ता को संबंधित पक्षकारों द्वारा मामूली आयात को देखते हुए, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को एक पात्र घरेलू उद्योग होने की हकदारी से अलग करने के लिए इस प्रकार के आयात को पर्याप्त मानना उपयुक्त नहीं पाया।
13. जांच की अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि भारत में डी ओ पी के अन्य उत्पादकों की संख्या है, हालांकि, इन्होंने पांच अन्य भारतीय उत्पादकों नामतः मैसर्स पायल पेट्रोकेम प्रा. लिमि., मैसर्स पी सी एल ऑयल एंड सॉल्वेंट लिमि. मैसर्स रचना प्लास्टिसाइजर्स प्रा. लिमि. मैसर्स एन के पोलिमर्स एवं मेनि. कंपनी और ललिता केम इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि. के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोधों में उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग ने अन्य प्रमुख उत्पादकों नामतः मैसर्स रिटजी केमिकल्स और अन्य कि उत्पादन और बिक्री के संबंध में सूचना घरेलू उद्योग को क्षति सिद्ध करने के उद्देश्य से उपलब्ध नहीं कराई। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री के संबंध में साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराये। मौखिक सुनवाई के बाद घरेलू उद्योग ने मैसर्स रिटजी केमिकल्स के उत्पादन और बिक्री से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई लेकिन मैसर्स रिटजी के संबद्ध वस्तुओं के एक प्रमुख आयातक में से एक आयातक मैसर्स रिटजी को घरेलू उद्योग का एक संघटक नहीं माना जा सका। यह भी नोट किया जाता है कि डी जी सी आई एंड एस के आयात सांख्यिकी के आधार पर, मैसर्स रिटजी केमिकल्स प्रा. लिमि. और इसके संबंधित पक्षकारों ने जांच की अवधि के दौरान डी ओ पी का बहुत अधिक मात्रा में आयात किया है और इसके साथ ही एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में, उन्होंने उत्पादन और बिक्री के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की।
14. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या (क) घरेलू उत्पादकों जो इस आवेदन का स्पष्ट तौर पर समर्थन कर रहे हैं, घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन का पच्चीस प्रतिशत से अधिक होते हैं और (ख) इस आवेदन का उन घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थन किया गया है जिनका सामूहिक उत्पादन उस घरेलू उद्योग को या तो इस आवेदन का समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं, के उस भाग द्वारा उत्पादन किए गए समान वस्तु के कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत से अधिक होता है। केवल आवेदकों का इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर कुल घरेलू उत्पादन 73 प्रतिशत होता है, हालांकि, यदि अन्य स्टेबलाइज्ड सॉफ्टनर को विचाराधीन उत्पाद के भाग के रूप में माना जाता हो तब इसके हिस्से में आगे और वृद्धि हो सकती है।
15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर शुरू की गई थी। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान जो सूचना अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस प्राधिकारी के ध्यान में लाई गई है, पर इस पाटनरोधी जांच में विचार किया गया है। उत्पादन और बिक्री के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये मुद्दों को देखते हुए, प्राधिकारी ने प्रशासनिक मंत्रालय से उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों को प्राप्त करने की भी कोशिश की हालांकि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि इस प्रकार की सूचना इनके द्वारा नहीं रखी जाती है क्योंकि वे केवल चुने गए बड़े एवं मध्यम एककों की मॉनीटरिंग करते हैं। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना पर मांग की गणना के लिए विचार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन आंकड़े दिए गए होते तो उन्होंने मांग एवं प्रतिशतता हिस्से सहित मात्रात्मक मानदंडों में परिवर्तन किया होता।
16. उपर्युक्त को देखते हुए और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आवेदक नियमावली के अंतर्गत स्थान की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इसके अलावा, आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय के अनुसार घरेलू उद्योग होते हैं।

घ. गोपनीयता

घ. 1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

17. गोपनीयता के संबंध में, इस जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :
- घरेलू उद्योग में जहां भी अपेक्षित हुआ गोपनीयता का दावा किया है और जहां भी संभव हुआ अगोपनीय सारांश भी उपलब्ध कराया है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकार किसी एक मात्र उदाहरण को सिद्ध करने में असफल रहे हैं जहां याचिकाकर्ताओं ने गोपनीयता का दावा किया है, जहां सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी और जिसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा वर्तमान मामले की आवश्यकता के एक मामले के रूप में अनुमति नहीं दी गई है। इन याचिकाकर्ताओं से गोपनीयता संबंधी दावे प्राधिकारी के रिवाज के अनुरूप है। घरेलू उद्योग ने क्षति संबंधी सभी मानदण्डों की प्रवृत्तियां उपलब्ध कराई हैं जो इस मामले के गुण दोष के आधार पर तर्क करने के लिए विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के लिए पर्याप्त है।
 - डी जी सी आई एंड एस के आंकड़े "तृतीय पक्षकार बिजनैस प्रॉपराइट्री सूचना" है और घरेलू उद्योग इसे प्रकट करने के लिए अधिकृत है। इसके अलावा, यह गोपनीय के रूप में डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों को मानने के लिए इस प्राधिकारी का सतत रिवाज रहा है।

- (iii) इसके अलावा, यदि विरोधी हितबद्ध पक्षकार को डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों की आवश्यकता हो, तब वे इस प्राधिकारी से अधिकरण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और इन आंकड़ों को खरीद सकते हैं। यह आंकड़े सभी के लिए भुगतान के आधार पर उपलब्ध हैं, बशर्ते की प्राधिकारी द्वारा अधिकरण प्राप्त किया गया हो।

घ. 2 **निर्यातकों आयातकों, प्रयोक्ताओं एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध**

18. निर्यातकों आयातकों, प्रयोक्ताओं एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोध और इस प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं:

- (i) अत्यधिक गोपनीयता का दावा इस स्थिति में भी किया गया है जब आर्थिक मानदण्ड इस याचिका में गोपनीय हैं। इसके फलस्वरूप प्रतिवादी इस उद्योग के क्षति संबंधी मानदण्डों की पूर्ण रूप से सार्थक जांच करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। न तो कुछ मानदण्डों के संबंध में गोपनीयता का दावा करने के उद्देश्य से कोई सही कारण और न ही एन सी वी में इसे उपलब्ध कराया गया है। गोपनीयता का दावा क्षमता और क्षमता का उपयोग, उद्योग की लागत – विवरण ख, प्रपत्र सी।, प्रपत्र सी।।, प्रपत्र घ, प्रपत्र ङ और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए किया गया है।
- (ii) इस वर्तमान जांच को आरंभ करने के समय पाटनरोधी महानिदेशालय में अपनाई जा रही स्थापित परम्परा के अनुसार, आयात के आंकड़ों का अगोपनीय पाठ प्रत्येक याचिका के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया गया था और उसे सार्वजनिक याचिक रखी गई थी, हालांकि, इस नियम के विपरीत प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है।
- (iii) गोपनीयता के दावे के लिए, प्रतिवादी ने अपने निजी प्रति उत्तरों की छानबीन की है और यह पाया है कि कोई अधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया गया है।
- (iv) प्रभावी टिप्पणियां करने के अधिकार में कटौती की गई है क्योंकि घरेलू उद्योग ने एन सी वी याचिका में पूर्ण सूचना दायर नहीं की है। हम जब और जैसे ही हमें सूचना उपलब्ध कराई जायेगी टिप्पणी करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हैं।
- (v) जांच का आरंभन उस सूचना के आधार पर किया गया है जो सही नहीं है और इस कारण से पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 में पर्याप्तता और स्टीकता की जांच को पूरा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने केवल डी ओ पी के नाम के अंतर्गत बेची गई संबद्ध वस्तुओं के संबंध में आंकड़े/सूचना प्रस्तुत की है। यदि इस उत्पाद की पूर्ण बिक्री और उत्पादन दिया गया होता तब जांच की अवधि के दौरान डी ओ पी की बिक्री में कोई गिरावट नहीं हुई होती। याचिकाकर्ता स्वयं कानाटोलस के अलग अलग प्रकारों के अंतर्गत प्लास्टिसाइजर की बिक्री कर रहे हैं और उन्होंने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह डी ओ पी के तटीय स्थापन के करीब है।
- (vi) याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि डी ओ पी के सभी प्रकारों को क्षति संबंधी मानदण्डों जैसे क्षमता का उपयोग, उत्पादन और बिक्री के उद्देश्य से शामिल किया गया है। यदि ऐसी स्थिति हो तब विचार किए गए डी ओ पी के विभिन्न प्रकारों के ब्यौरे का खुलासा क्यों नहीं किया गया था।
- (vii) घरेलू उद्योग का भारत में एकाधिकारवादी स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ता उद्योग का दमन करने के लिए व्यापार सुधारात्मक उपाय के तंत्र का उपयोग करने का एक इतिहास है। पूर्व में, घरेलू उद्योग ने डी ओ पी के आयात पर लगाई गई सुरक्षात्मक शुल्क जैसी सुरक्षा मांगी है और अब वे इन आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पाटनरोधी नियम के अंतर्गत सुरक्षा के मार्ग की तलाश कर रहे हैं।
- (viii) घरेलू उद्योग एक फेथालेट प्लास्टिसाइजर्स है और इसके द्वारा सभी उत्पादों के लिए कुल संस्थापित क्षमता उसकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1,80,000 मी. टन प्रतिवर्ष है। हालांकि, विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई समर्पित संस्थापित क्षमता नहीं है।

घ. 3 **प्राधिकारी द्वारा जांच**

19. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है :-

“गोपनीय सूचना” (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

20. घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों पर संगत मानी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जांच किया गया और तदनुसार उसका समाधान किया गया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, इस प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे जहां भी आवश्यक हुआ को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया है और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करावें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक याचिका के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार से संबंधित को गोपनीय के रूप में दावा किया है।
21. डी जी सी आई एंड एस लेन देन वार आंकड़ों के प्रकटन के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इस प्रकार के आंकड़ों की खरीद प्राधिकारी से अधिकरण प्राप्त करने के वाद की गई है। घरेलू उद्योग ने यह भी उल्लेख किया है कि डी जी सी सी आई एंड एस के आंकड़े गोपनीय सूचना है और याचिकाकर्ता डी जी सी आई एंड एस से विशिष्ट अधिकरण के बिना इसे प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं है। हालांकि, कोई भी हितबद्ध पक्षकार पाटनरोधी महानिदेशालय के अधिकरण के प्राप्त होने पर डी जी सी आई एंड एस के आंकड़े प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, आयात संबंधी सांख्यिकी का सारांश सभी हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका के अगोपनीय पाठ में उपलब्ध कराया गया है।

४ विविध अनुरोध

४.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

22. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध अनुरोध नीचे दिए गए हैं :

- (i) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का विधिवत सत्यापन इस प्राधिकारी द्वारा किया गया है और लागतों का भी प्रमाणन लागत/ चार्टर्ड एकाउंट द्वारा किया गया है।
- (ii) इस याचिका का उद्देश्य पाटनरोधी शुल्क से किसी प्रकार का लागत लाभ लेना नहीं है जिसे लगाये जाने का प्रस्ताव किया गया है। याचिकाकर्ता केवल बाजार से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी क्षति भारतीय उत्पादकों द्वारा आयातों से हुई है। याचिकाकर्ता को इस देश में पाटन के फलस्वरूप प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव की हानि हुई है। यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाते हैं तब याचिकाकर्ता उन मात्राओं को फिर से प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे जिनका उन्हें नुकसान हुआ है और वे बाजार में अपने हिस्से को बनाये रख सकेंगे। इस प्रकार से जब याचिकाकर्ता कीमत में वृद्धि अथवा कमी जो कच्चे माल में परिवर्तनों के कारण आवश्यक हो सकता है, को छोड़कर किसी रूप में कीमतों में वृद्धि करने का उद्देश्य न रख रहे हों; किसी भी मामले में उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण से हितबद्ध पक्षकारों को उस पाटनरोधी शुल्क जिसे लगाये जाने का प्रस्ताव किया जाता है के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) विरोधी हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुलन पत्र सभी उत्पादों और न कि डी ओ पी की कुल बिक्री को दर्शाता है। वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद सभी प्लास्टिसाइजर नहीं हैं बल्कि केवल डी ओ पी हैं। विरोधी हितबद्ध पक्षकार डी ओ पी के उत्पादन के साथ सभी प्लास्टिसाइजरो के उत्पादन के बराबर हो रहा है। इसके अलावा, मैसर्स ललिता केम इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि. के उत्पादन आंकड़े जिन्हें विरोधी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं वर्ष 2015-16 के लिए है जो जांच की अवधि भी नहीं है।
- (iv) विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि 8500 मी. टन आयात शुल्क मुक्त आयात है। ऐसे अनेक मामले हुए हैं जिन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की जांच करने के लिए अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयातों को शामिल किया है। यह हितबद्ध पक्षकारों की ओर से विशुद्ध से अनुमान है कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयात घरेलू उद्योग को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार के आयात स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं। निर्यात उत्पादन के लिए आयात को भारत सरकार द्वारा अग्रिम अधिकरण योजना के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क के क्षेत्राधिकार के भारत सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है। इसका यह मतलब नहीं होता है कि इन आयातों से क्षति नहीं हो रही है। यह पाटनरोधी शुल्क लगाते समय भारत सरकार के विवेकाधिकार को ही दर्शाता है।
- (v) वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि अप्रैल 2016 – मार्च 2017 है और इस मामले को 1 जून, 2017 को आरंभ किया गया था। इस कारण से याचिका में जांच की एक अवधि और जांच आरंभ करने की अवधि के बीच 2 महीनों का ही अंतर है। इस कारण से यह विश्व व्यापार संगठन की पाटनरोधी समिति के दस्तावेज जी/एडीपी/6 के अनुरूप है।

जांच की अवधि में परिवर्तन के संबंध में, यह प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि को उससे बदलने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी सहित वैश्विक रूप से सतत परंपरा रही है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा उनकी याचिका में अपनाई गई है। इस प्रकार की परंपरा में कोई असंगतता नहीं है।

- (vi) मैक्सिको – गुआटेमाला से स्टील पाइप और ट्यूब पर पाटनरोधी शुल्क के मामले में पैनल की रिपोर्ट का संदर्भ लिया गया है जिसमें पैनल में यह उल्लेख किया कि जांच की अवधि के अंत और जांच प्रारंभ करने के बीच अंतर यदि 8 महीने भी होता है तो कोई असंगतता नहीं है। घरेलू उद्योग को अन्य हितवद्ध पक्षकारों की तरह अध्यतीत सूचना प्रस्तुत करने के लिए 40 दिनों की समयावधि भी प्रदान की गई थी और अन्य हितवद्ध पक्षकारों को जांच के उद्देश्य से आंकड़े देने थे। यह निर्दिष्ट प्राधिकारी की विगत परंपरा के अनुरूप थी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को अध्यतीत सूचना पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए हितवद्ध पक्षकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अध्यतीत सूचना का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में रखा गया था।
- (vii) जबकि, डी ओ पी उपभोक्ताओं के लिए एक प्रमुख लागत मद नहीं है फिर भी यह प्लास्टिक फिल्म, इमिग्रेशन लेदर, बिजली के तार, केवल बियरर आदि का उत्पादन करने के लिए पोलि बिनायल क्लोराइड (पी वी सी) के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री है। इस प्रकार से व्यवहार्य और गतिशील घरेलू उद्योग देश के व्यापक हित में है।
- (viii) अनेक पक्षकारों ने अंतिम समय सीमा के पांच महीनों के बाद पहली बार अपने आप को अवगत कराया। ऐसा मामला होने के कारण, इन पक्षकारों में किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोधों को विलंब से प्रस्तुत किए जाने के आधार पर अस्वीकार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने दिनांक 9 जनवरी, 2012 के व्यापार सूचना संख्या 01/2012 के माध्यम से हितवद्ध पक्षकारों के पंजीकरण के लिए 15 दिनों की एक समय सीमा का पूर्व में उल्लेख किया था। उक्त पक्षकारों में से न केवल किसी ने व्यापार सूचना के अनुसार निर्धारित समय के भीतर के हितवद्ध पक्षकार के रूप में अपने आप को पंजीकृत कराया है बल्कि इन पक्षकारों ने प्राधिकारी के पास प्रश्नावली का उत्तर अथवा अनुरोध कभी भी प्रस्तुत नहीं किया। इस व्यापार सूचना का भारी दुरुपयोग किया गया है।

ऊ 2 निर्यातकों आयातकों, प्रयोक्ताओं एवं अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

23. निर्यातकों आयातकों, प्रयोक्ताओं एवं अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच की अवधि के दौरान विविध मुद्दों के संबंध में किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं :
 - (i) प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के प्रावधानों के संबंध में जांच आरंभन के लिए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार किए गए आंकड़ों/सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। इस जांच में भाग लेने के लिए अधिकार में कटौती की गई है। 22 दिसंबर को सम्पन्न हुई सुनवाई को नियम 6(6) के संबंध में प्रभावी सुनवाई के रूप में उल्लेख नहीं किया जा सकता है।
 - (ii) वर्तमान कार्यवाही जारी रखने योग्य नहीं है क्योंकि उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार आरंभ नहीं किया गया है। जांच आरंभन के उद्देश्य से, सभी मानदण्डों को आवश्यक रूप से गिरावट के रूप में दर्शाना है। हालांकि, जहां तक क्षति की कीमत से संबंधित पहलुओं का प्रश्न है, क्षति अथवा गिरावट नहीं हुई है। घरेलू उद्योग ने सुनवाई में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वर्तमान मामले में कीमत में क्षति नहीं हुई है और पर्याप्त लाभ अर्जित किया जा रहा है।
 - (iii) भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए 1500 से 2000 मिश्रण इकाईयां हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने का मिश्रण और डाउनस्ट्रिम उद्योगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। शुल्क को लगाये जाने से लागत में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप करों और शुल्कों के कारण कीमतों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी। याचिकाकर्ता डी ओ पी और मिश्रण का निर्माण कर रहे हैं, पाटनरोधी शुल्क लगाने से इन आयातकों/प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा अपेक्षाकृत बहुत कम कीमत पर मिश्रण का निर्माण होगा। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता और प्रयोक्ताओं के हितों में संतुलन स्थापित करें क्योंकि दोनों भारतीय उद्योग हैं और उन्हें समान दर्जा प्राप्त करने का हक है।
 - (iv) जांच की अवधि के लिए मैसर्स के एल जे प्लास्टिसाइजर्स की वार्षिक रिपोर्ट में डी ओ पी की बिक्री का 1100 भारतीय करोड़ रुपए के रूप में उल्लेख है, जिसके फलस्वरूप लगभग 1,40,000 – 1,50,000 मी. टन की मात्रा हुई है। याचिका में दिए गए आंकड़ों के संबंध में यह उल्लेख है कि बिक्री 45,310 मी. टन हुई है। घरेलू उद्योग गलत आंकड़े प्रस्तुत कर प्राधिकारी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है।
 - (v) डी ओ पी के कच्चे माल पर पाटनरोधी शुल्क पहले ही लगाया गया है, विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क से कठिनाई उत्पन्न होगी और इसका नीचे अंतिम प्रयोक्ताओं तक प्रभाव पड़ेगा, जिसमें इस उत्पाद पर तीन शुल्क आम हित के

विरुद्ध होगा। कच्चे माल की लागत में वृद्धि के साथ, उनके उत्पादों के क्रेता घरेलू लघु निर्माताओं से खरीदने के बजाय आयात करना पसंद कर सकते हैं, यह सरकार की मेक इन इण्डिया की नीति के विरुद्ध जायेगा।

- (vi) डी ओ पी के उपभोक्ता पूर्ण रूप से लघु एवं मध्यम उद्योग में हैं; वे भारी संख्या में रोजगार पैदा कर रहे हैं और "मेक इन इण्डिया" पहल को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस कारण से पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप अनेक उद्योगों को बंद किया जाना होगा और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को हानि होगी और याचिकाकर्ता का एकाधिकारवादी मनोवृत्ति में वृद्धि होगी।
- (vii) याचिका में दी गई अवधि और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई अवधि के बीच जांच की अवधि में अंतर अलग अलग है और यह गंभीर चिंता उत्पन्न करता है। विश्व व्यापार संगठन की पाटनरोधी समिति के दस्तावेज जी/ए डी टी/6 के अनुसार, एक पाटनरोधी जांच में आंकड़ों के संकलन की अवधि इस मामले के जांच प्रारंभ की तिथि के करीब समाप्त होना चाहिए। वर्तमान मामले में, यह याचिका सितंबर 2016 में समाप्त हो गई। हालांकि, 1 जून, 2017 को प्रारंभ किया गया था जो 8 महीने की एक अवधि को दर्शाता है।
- (viii) अद्ययुतीत याचिका इस मामले में आरंभ होने के तत्काल में सार्वजनिक फाइल में नहीं रखी गई थी। घरेलू उद्योग ने उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया है चूंकि, इसने मामले के आरंभ किए जाने के बाद संशोधित याचिका का अगोपनीय पाठ प्रस्तुत किया।
- (ix) पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से न केवल विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप विदेश में निर्माण को अंतरित तथा भारत में मूल्यवर्धित उत्पाद का आयात करना पड़ेगा जिससे उनके बचे रहने के लिए खतरा उत्पन्न होगा और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को भी खतरा उत्पन्न होगा।
- (x) डी ओ पी के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के फलस्वरूप घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को इस स्थिति का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा और डी ओ पी की कीमत में आगे और वृद्धि होगी। उसके कारण, पी वी सी कम्पाउंड लागत अधिक हो जायेगी और इसके फलस्वरूप बाजार में केवल और तार की कीमत में वृद्धि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से केवल तार उद्योग तथा उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- (xi) याचिकाकर्ता ने यह दावा करते हुए कुछ अनुरोध किए हैं कि उपयोग में न लाई गई क्षमताओं के बाजवूद, अन्य भारतीय उत्पादक विचारधीन उत्पादन का आयात करने के लिए बाध्य हो गये थे। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया गया है वे इस निवेदन को अस्वीकार कर दें क्योंकि अन्य भारतीय उत्पादकों ने यह अनुरोध किया है कि उत्पादकों को विचाराधीन उत्पाद के कच्चे माल पर पाटनरोधी शुल्क के कारण उत्पादन की बढ़ी हुई लागत तथा कच्चे माल की उपलब्धता के मुद्दे का सामना करना पड़ा। यह स्वीकार किया गया था कि बढ़ी हुई लागत और कच्चे माल की उपलब्धता की कमी मौखिक सुनवाई के दौरान इस प्रकार के आयात के कारण थे।
- (xii) विलंब से दिए गए प्रति उत्तर को स्वीकार किए जाने के संबंध में, चीन जन. गण. – एम टी आर, पी वी सी सस्पेंशन ग्रेड, पी वी सी फैलक्स और बारियम कार्बोनेट चीन जन. गण. जिसमें विलंब से दिए गए उत्तर को न केवल हितबद्ध पक्षकारों से बल्कि घरेलू उद्योग से भी स्वीकार किया गया है, से पी टी एफ ई पर विश्वास किया गया है।
- (xiii) इन आयातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विलंब से प्रत्युत्तरों के संबंध में, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में प्रमुख आयातकों/ प्रयोक्ताओं के नामों को जानबूझकर प्रकट नहीं किया है। चूंकि, इस याचिका में आयातकों/ प्रयोक्ताओं का उल्लेख नहीं किया गया था। अतः उन्हें इस जांच को आरंभ किए जाने अथवा प्रश्नावली के उत्तर के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी और वे समय सीमाओं के भीतर अनुरोध दायर करने के लिए सक्षम नहीं थे।
- (xiv) याचिकाकर्ता यह जानते हैं कि भारत में इस उत्पाद के 500 उपभोक्ता हैं, जिनमें 425 उपभोक्ता पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने पर सहमत नहीं हुए हैं और उनकी भागीदारी इस जांच में आवश्यक है। ऑटोमोटिव टायर मेनिफेक्चर्स एसोशिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी जिसमें यह माना गया था कि किसी प्रतिरोधी कार्यवाही में, अर्थन्यायिक प्रकृति होने के कारण विरोधी पक्षकारों की भागीदारी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सही परिणाम पर पहुंचा जा सके, पर विश्वास किया गया है।
- (xv) जांच की अवधि के दौरान मैसर्स के एल जे ने पाटित आयातों के कारण क्षति का दावा किया है। हालांकि, उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने अपना सबसे अधिक लाभ प्राप्त करते हुए अपने लाभों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है। जब कोई पाटन नहीं हुआ था तब नियोजित पूंजी पर लाभ नकारात्मक था। हालांकि, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान जब आयात सबसे अधिक स्तर पर, के दौरान नियोजित पूंजी पर सबसे अधिक लाभ हुआ है। इस प्रकार से क्षति जिसका दावा किया गया है, आयातों के कारण नहीं हुआ है।

- (xvi) जांच की अवधि के दौरान, के एल जे उत्पादन कर रहा है और अपनी बिक्री से लाभ अर्जित कर रहा है। सामान्य तौर पर डी ओ पी के उत्पादक इस उद्योग में विकास की अच्छी संभावना की आशा करते हुए क्षमता में वृद्धि करने की प्रक्रिया में हैं। उद्योग को पाटित आयातों के कारण नुकसान होने का कोई संकेत नहीं है बल्कि वे इन आयातों के साथ अच्छी तरह से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
- (xvii) स्वयं डी ओ पी पर पाटनरोधी शुल्क शुरू करने के फलस्वरूप डी ओ पी के कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग ने प्रत्येक दिन इन कीमतों में वृद्धि पर एक कृत्रिम अभाव पैदा किया है। पी वी सी उद्योग को उन देशों जहां कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया है, से पी वी सी फ्लोरिंग, पी वी सी जिमोमेंब्रेन, शीटिंग्स और फिल्म आदि जैसे तैयार उत्पादों के सस्ते आयातों से बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। डी ओ पी पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना भारत में प्रसंस्करण उद्योग के बचे रहने के लिए बहुत अधिक हानिकारक होगा।

३ प्राधिकारी द्वारा जांच

24. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विविध मुद्दों के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों की जांच और उसका समाधान नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :

- (i) घरेलू उद्योग की अपर्याप्त सूचना का तर्क जिन्हें उनके द्वारा विधिवत दायर किया गया था, के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस आवेदन में जांच आरंभ करने के उद्देश्य से संगत सभी सूचनाएं शामिल थीं। प्राधिकारी ने यह संतुष्टी प्राप्त करने के बाद ही कि आवेदन में इस जांच के आरंभन को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य निहित थे, वर्तमान जांच को आरंभ करने का निर्णय लिया।
- (ii) जहां तक जांच की अवधि के संबंध में तर्क का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि (पी ओ आई) अप्रैल 2015 से सितंबर 2016 (18 महीने) की अवधि के लिए थी। हालांकि प्राधिकारी को अपेक्षाकृत अधिक अध्यतीत आंकड़ों के आधार पर अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए समर्थ बनाने हेतु, प्राधिकारी ने जांच की अवधि की अपेक्षाकृत हाल की अवधि को अप्रैल 2016 से मार्च 2017 (12 महीने) के रूप में माना है। हालांकि, क्षति की जांच की अवधि में 2013-14, 2014-15, 2015-16 की अवधियां और जांच की अवधि शामिल थी। जांच की संशोधित अवधि के संबंध में सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई थी।
- (iii) प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच की अवधि इस जांच के आरंभ होने पर घरेलू उद्योग को सूचित किया गया था। प्राधिकारी ने जांच की अध्यतीत अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दी गई अवधि के सदृश्य घरेलू उद्योग को 40 दिनों की अवधि प्रदान की। अध्यतीत सूचना को घरेलू उद्योग द्वारा समय पर दायर किया गया था और उसे सार्वजनिक याचिका में रखा गया था।
- (iv) जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से कम्पाउंडिंग और डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाये जाने का उद्देश्य अनुचित बाजार परंपराओं को ठीक करने तथा घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान कर इसके क्षतिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए है। इसके अलावा, पाटनरोधी उपायों को लगाने से आयात में रुकावट नहीं होती है हालांकि, आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध रहेगा और घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा की भी अनुमति रहेगी।
- (v) जहां तक घरेलू उद्योग के इस तर्क का प्रश्न है कि क्षति अन्य उत्पादों के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति का विश्लेषण संबंधित उत्पाद के लिए किए जाने की आवश्यकता है, न कि समग्र रूप से क्षेत्र के लिए अथवा गैर-विचाराधीन उत्पाद के कारण। एक बहु उत्पाद समूह होने के कारण, आंकड़े/ सूचना को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से पाटन के कारण उनकी क्षति, यदि कोई हो, की जांच करने के उद्देश्य से संबंधित उत्पाद के लिए अलग अलग की गई है।
- (vi) जहां तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एम सी ए) में वित्तीय विवरणों को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों व्यक्त की गई चिंताओं का प्रश्न है, प्राधिकारी ने उक्त अनुरोधों की जांच की है और यह नोट किया गया है कि एम सी ए को यथा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों में उल्लिखित कारोबार डी ओ पी का उन कारोबार के लिए है। मौखिक सुनवाई के बाद, इस मुद्दे के बारे में विशिष्ट रूप से घरेलू उद्योग से पूछा गया था और घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि इस विवरण को प्रस्तुत करते समय कंपनी को कुछ तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस कारण से एम सी ए को यह सूचना प्रस्तुत करने में त्रुटि हुई है। हालांकि, अपनी की गई गलतियों के प्रभाव को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि लागत लेखा रिपोर्ट (सी ए आर) इन तथ्यों को सिद्ध करता है कि कंपनी की 1158 करोड़ रुपये की कुल कारोबार कारपोरेट कार्य मंत्रालय को दी गई सूचना के आंकड़ों के अनुरूप है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह स्पष्ट किया कि जांच की अवधि के लिए लागत लेखा रिपोर्ट यह सिद्ध करता है कि संगत अवधि के दौरान उत्पादन किए गए उत्पादों की संख्या और कंपनी द्वारा बेची गई उत्पादों की संख्या कंपनी की लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि लेखा आंकड़ों के अनुरूप है। इसका विधिवत सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया

गया था। एमसीए के समक्ष वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के उत्तर में याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि पूर्ण क्षति की अवधि के लिए सूचना दायर करने हेतु गलती से त्रुटि हुई है। हालांकि, प्राधिकारी का यह मत है कि 'त्रुटिवश हुई भूल' इस प्रकार के दावे इन्कार किए जाने के योग्य नहीं हैं क्योंकि इस प्रकार से ठीक न की गई गलतियां नियामक प्राधिकारी के समक्ष सूचना की सांविधिक फाइलिंग में है और यह समझ से परे है।

- (vii) अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयातों को बाहर किये जाने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि आयातों पर इस पाटनरोधी जांच में मात्रा संबंधी प्रभाव की जांच करने के उद्देश्य से कुल आयात, मांग और मात्रा का आकलन निर्धारित करने के प्रयोजन से विचार किया गया है।
- (viii) जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद और भारत में आयात किए गए उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में तर्क दिया गया है, यह नोट किया जाता है कि चूंकि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना गया है और इन दोनों का उपयोग प्रयोक्ताओं/ आयातकों द्वारा एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये इस प्रकार के मुद्दे उसे सिद्ध करने के लिए बिना साक्ष्य के हैं।
- (ix) जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का प्रश्न है की अनेक पक्षकारों ने पहली बार मौखिक सुनवाई में अपनी उपस्थिति दर्ज की है और विलंब से अनुरोध प्रस्तुत किया है। यह नोट किया जाता है कि इन पक्षकारों ने अपने अनुरोधों/ सूचना को प्रस्तुत करने के लिए समयबद्ध रूप में उन्हें दिए गए अवसर का उपयोग नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क संबंधी जांच समयबद्ध होने के कारण यह अपेक्षित है कि पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे अनुरोधों का आदान प्रदान हो और प्राधिकारी को उचित निर्धारण पर पहुंचने में सहायता करने के उद्देश्य से टिप्पणियां प्रस्तुत की जायें। निर्यातक, उत्पादक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को न तो प्रत्युत्तर दिया है और न ही इस जांच के संगत सूचना की आपूर्ति की है, को गैर सहयोगी के रूप में माना गया है। हालांकि, प्राधिकारी ने व्यवहारिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके अनुरोधों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है और उसकी जांच की है तथा उपयुक्त स्थानों पर उनके द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों का समाधान किया है।
- (x) जहां तक इस उत्पाद के लिए क्षति रहित कीमत के निर्धारण का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि कुल संयंत्र उत्पादन पर विचार एन आई पी के निर्धारण के लिए उत्पादन की आदर्शतम स्थिति के उद्देश्य से किया गया है चूंकि घरेलू उद्योग का यह दावा है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित अन्य उत्पाद प्लास्टिसाइजर के अलग रूप हैं। अतः प्राधिकारी ने एन आई पी के सामान्यीकरण और निर्धारण के लिए कुल संयंत्र उत्पादन पर विचार करने के लिए इसे उपयुक्त पाया।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

25. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च. 1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

26. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- (i) किसी भी निर्यातक ने कच्चे माल अर्थात् पीए और 2ईएच के मूल्यांकन के संबंध में इस प्रश्न का पूर्ण रूप से उत्तर नहीं दिया है। उसके अलावा, कुछ निर्यातकों ने कच्चे माल के मूल्यांकन के संबंध में कोई सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई है जिसका गुप्त रूप से उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है अथवा ऐसा दावा किया जाता है कि उन्होंने कीमतों के संबंध में समझौता किया है जबकि प्रतिउत्तर देने वाले अधिकांश निर्यातकों की वेबसाइट सूचना गुप्त रूप से कच्चे माल की खरीद कर रही है। निर्यातकों द्वारा यह सिद्ध किए जाने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के कच्चे मालों की कीमतें उत्पादन के साथ जुड़ी हुई लागतों और डी ओ पी की बिक्री को उचित रूप से दर्शाता है।
- (ii) वर्तमान जांच में प्रश्नावली का उत्तर अपनाए गए बिक्री चैनलों के संबंध में स्पष्ट नहीं है तथा इस संबंध में भी स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया प्रतिउत्तर इन उत्पादकों द्वारा अपनाए गए व्यापक बिक्री चैनलों को प्रस्तुत करता है। प्रश्नावली के उत्तर की पूर्णता अलग अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। इस परिदृश्य में, उत्तर देने वाले निर्यातकों/ उत्पादकों की लागत और कीमत पर तब तक सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता है जब तक की यह सिद्ध न हो जाये कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रश्नावली का उत्तर पूर्ण है और सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह इस मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि क्यों इसमें निहित मूल्य श्रृंखला का एक जटिल जाल है और उत्पादक या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा संबंधित कंपनी के माध्यम से बैकवर्ड – फॉरवर्ड रूप से एकीकृत हैं। इन निर्यातों की पूर्ण मूल्य श्रृंखला के न होने के कारण, प्राधिकारी को अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए।
- (iii) वर्तमान जांच में प्रश्नावली का उत्तर अपनाए गए बिक्री चैनलों के संबंध में स्पष्ट नहीं है तथा इस संबंध में भी स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया प्रत्युत्तर इन उत्पादकों द्वारा अपनाए गए व्यापक बिक्री चैनलों को प्रस्तुत करता है। प्रश्नावली के उत्तर की पूर्णता अलग अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। इन निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावलियों के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि एवरलाइट कोरिया कं. लिमि., हानवा केमिकल्स जो कोरिया में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों में से एक उत्पादक है, द्वारा किए गए उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है। हानवा केमिकल्स ने वर्तमान जांच में कोई उत्तर नहीं दिया है। इसके अलावा, नान या प्लास्टिक्स (ताइवान) और ओ सी आई कं. लिमि. ने यह उल्लेख किया है कि वे विचाराधीन उत्पाद का निर्यात व्यापारियों के माध्यम से कर रहे हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन सभी व्यापारियों ने इस प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।
- (iv) वर्तमान जांच में, एक उत्पादक ने अनेक निर्यातकों के माध्यम से इस उत्पाद का निर्यात किया है और एक निर्यातक ने अनेक उत्पादकों द्वारा उत्पादन किए गए वस्तुओं का निर्यात किया है। प्रश्नावली में ऐसी किसी बातों का उल्लेख नहीं किया गया है जो इन उत्पादकों, व्यापारियों, निर्यातकों और शिपर द्वारा किए जा रहे कार्यों को चित्रित करता हो। चूंकि एकयंग पेट्रोकेमिकल्स क. लिमि. (कोरिया) एक उत्पादक है जिसने ह्यूमडे कारपोरेशन (कोरिया), यूबेस्को कोरपोरेशन (कोरिया) और एवरलाइट कोरिया क. लिमि. (कोरिया) के माध्यम से इस उत्पाद का निर्यात किया है। ह्यूमडे कारपोरेशन और यूबेस्को कोरपोरेशन संबंधित कंपनियां हैं। इसके अलावा, नॉन या प्लास्टिक (ताइवान) एक उत्पादक हैं जिसमें जे सी पेट्रोकेम लिमि. (हांगकांग) सहित अलग अलग व्यापारियों के माध्यम से इस उत्पाद का निर्यात किया है।
- (v) उसी प्रकार से ओ सी आई क. लिमि. एक उत्पादक है जिसने इस उत्पाद का निर्यात एवरलाइट कोरिया क. लिमि. सहित अलग अलग व्यापारियों/ वितरकों के माध्यम से निर्यात किया है। एवरलाइट कोरिया क. लिमि. (कोरिया) एक व्यापारी है जिसने भारत में ओ सी आई कं. लिमि. (कोरिया), हानवा केमिकल्स (कोरिया) और आकयुंग पेट्रोकेमिकल्स क. लिमि. (कोरिया) द्वारा निर्मित इस उत्पाद का निर्यात किया है। हानवा केमिकल्स में संबद्ध जांच में सहयोग नहीं किया है। इस प्रकार की जटिल वेब व्यापार चैनल के संबंध में, निर्यातक किसी विशिष्ट बिक्री चैनल को सौंपे गए अलग अलग कर्तव्यों का लाभ उठायेगा।

च. 2 निर्यातकों आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

27. निर्यातकों आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों का सारांश नीचे दिया गया है :

- (i) चीन अथवा ताइवान अथवा कोरिया से निर्यात की कीमतें समुद्री धारा को छोड़कर वही है जो भारत में क्रेताओं को उसी कीमत को सुनिश्चित करने के लिए समान हैं। स्थानीय उत्पादक मांग और आपूर्ति की योग्यता के आधार पर प्रत्येक माह अथवा पाक्षिक रूप से कीमतों को ठीक कर रहे हैं।
- (ii) ओ सी आई के व्यापारियों ने इस जांच में भाग लिया है और मूल्य श्रृंखला पूरी है। एवरलाइट के संबंध में, प्रतिवादी निर्यात/ व्यापार श्रृंखला के संबंध में अलग अलग शुल्क मार्जिन की मांग कर रहे हैं। भारत में प्राधिकारी अलग अलग मार्जिन और न कि किसी विशिष्ट निर्यातक को स्वीकृत करते हैं बल्कि भाग लेने वाले व्यापार/ निर्यात श्रृंखला को

- स्वीकृत करते हैं। हानवा केमिकल्स के भाग न लेने का प्रभाव ओ सी आई-एवरलाइट व्यापार/ निर्यात श्रृंखला को शुल्क पर नहीं डालेगा।
- (iii) प्राधिकारी को यह अवश्य नोट करना चाहिए याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत की गई वाद कानून उन स्थितियों के संदर्भ में जहां विचाराधीन उत्पाद के निर्यात को उन स्थितियों को छोड़कर नहीं देखा जा सकता है जहां निर्यातक का उत्तर एक अन्य व्यापार श्रृंखला के उत्पादक की गैर भागीदारी के कारण एक व्यापार श्रृंखला के लिए अस्वीकार की गई है।
- (iv) व्यापार चैनल और पाटन मार्जिन की जटिल वेब के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क मार्जिन या तो एक को अलग करने के बजाय एक उत्पादक और निर्यातक सहित व्यापार चैनल के आधार पर है। इस प्रकार की परंपरा का पालन वैश्विक स्तर पर किया जाता है जहां अलग अलग उत्पादकों को अलग अलग शुल्क दर सौंपे जाते हैं।
- (v) प्राधिकारी के एक ही निर्यातक के लिए अलग अलग उत्पादकों के सामानों की आपूर्ति करते समय अलग अलग शुल्क मार्जिन लगाने के लिए स्थापित परंपरा के अनुसार, इस प्रकार के उत्पादकों का अनुपम सामान्य मूल्य होता है और एक अनुपम कारखानागत निर्यात कीमत होती है और इस कारण से विभिन्न उत्पादकों के सामानों की आपूर्ति करने के लिए एक ही निर्यातक के लिए अलग अलग शुल्कों का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उचित आकलन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। "चीन से ओ-एसिड" का संदर्भ लिया गया है जिसमें प्राधिकारी ने अलग अलग शुल्क मार्जिन का निर्धारण किया है।
- (vi) भारत में प्राधिकारी अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं करता है बल्कि भारत में उत्पादक और निर्यातक के बीच व्यापार के चैनल पर आधारित शुल्कों की पहचान करता है। इस प्रकार का विभेद यह सुनिश्चित करता है कि एक उचित व्यापार चैनल को प्रोत्साहित किया जा सके।

च. 4 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

29. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को उन्हें यह सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजी कि वे निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध करायें। हालांकि, निम्नलिखित उत्पादक और निर्यातकों को छोड़कर, संबद्ध देशों से अन्य उत्पादकों/ निर्यातकों में से किसी ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर दायर करने के बाद इस जांच में सहयोग नहीं किया।

- क) ओ सी आई कंपनी लिमिटेड, कोरिया जन. गण.
- ख) नान या प्लास्टिक्स कोरपोरेशन, चाईनीज ताईपेई
- ग) एवरलाइट कोरिया कं. लिमि., कोरिया जन. गण.
- घ) जे सी पेट्रोकेम लिमिटेड, हांगकांग
- ङ) एकयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमि. कोरिया जन. गण.
- च) कनको मार्केटिंग इंक, कोरिया जन. गण.
- छ) केमटाउन कं. लिमि., कोरिया जन. गण.
- ज) हमडे कोरपोरेशन, कोरिया जन. गण.
- झ) ह्यूनडेई कोरपोरेशन, कोरिया जन. गण.
- ञ) यूबेस्को कोरपोरेशन, कोरिया जन. गण.
- ट) बूरी पी एवं सी कोरपोरेशन, कोरिया जन. गण.

30. चूंकि उपरोक्त उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, इसलिए प्राधिकारी इन कंपनियों के संबंध में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। इन निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली

सामान्य पद्धति पहले यह जांच करने की रही है कि क्या प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा अपने घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्रतिनिधि और व्यवहार्य है और क्या बिक्री मूल्यों और प्रतिवादियों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार व्यापार की सामान्य प्रक्रिया का परीक्षण उचित रहा था।

31. संबद्ध देशों में असहयोगी निर्यातकों के मामले में, प्राधिकारी, करार के अनुच्छेद 6.8 के साथ पठित नियमावली के नियम 6 (8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं।

एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं, लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

32. पीओआई के दौरान मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं, लिमिटेड ने घरेलू बाजार में 13,801.00 एमटी संबद्ध वस्तु को बीजक मूल्य *** के आरडब्ल्यू पर बेचा है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन 80% से अधिक हैं तो प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में सभी लेनदेन पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया है और ऐसे मामलों में, जहां लाभकारी लेनदेन 80% से कम है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण हेतु केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा गया है। इस मामले में, व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण के आधार पर, सभी घरेलू बिक्री सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ली गई हैं, क्योंकि लाभदायक बिक्री 80% से अधिक थीं।

33. मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं, लिमिटेड ने माल दुलाई के खर्च, बैंक प्रभार, कमीशन, क्रेडिट व्यय और पैकिंग व्ययों के कारण समायोजन का दावा किया है जो प्राधिकारी द्वारा कमीशन को छोड़कर विधिवत रूप से सत्यापित किया गया है और उस पर विचार किया गया है क्योंकि कमीशन प्रामाणिक नहीं था। तदनुसार, मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं, लिमिटेड के लिए भारत औसत सामान्य मूल्य, *** अमेरिकी डॉलर/एमटी के रूप में निर्धारित किया गया है।

मैसर्स ओसीआई कंपनी लिमिटेड, कोरिया के लिए सामान्य मूल्य

34. मैसर्स ओसीआई कं. लिमिटेड ने, पीओआई के दौरान, घरेलू बाजार में 16,705.51 एमटी संबद्ध वस्तु को *** के आरडब्ल्यू बीजक मूल्य पर बेचा है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन 80% से अधिक हैं तो प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में सभी लेनदेन पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया है और ऐसे मामलों में, जहां लाभकारी लेनदेन 80% से कम है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण हेतु केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा गया है। इस मामले में, व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण के आधार पर, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ली गई हैं, क्योंकि लाभदायक बिक्री 80% से कम थीं।

35. ओसीआई ने पैकिंग लागत, अंतर्देशीय मालभाड़ा, वेयरहाउस प्रभार और ऋण व्यय के कारण समायोजन का दावा किया है जिसे प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और विचार किया गया है। तदनुसार, मैसर्स ओसीआई कं. लिमिटेड के लिए भारत औसत सामान्य मूल्य, *** अमेरिकी डॉलर / मीट्रिक टन के रूप में निर्धारित किया गया है।

कोरिया गणराज्य से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य से अन्य किसी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी को वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है। कोरिया गणराज्य में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के अनुसार *** अमडा./एमटी के रूप में निर्धारित किया है।

निर्यात कीमत

मैसर्स केंको मार्केटिंग, इंक., मैसर्स ह्यूमेड कॉरपोरेशन, मैसर्स उबेस्को कॉरपोरेशन, मैसर्स कैमटाउन कं, लिमिटेड, मै. हुंडई कॉरपोरेशन और मैसर्स वूरी पी एंड सी कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य के साथ मै. एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं, लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात कीमत

37. मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड ने अपनी असंबंधित व्यापारिक कंपनियों अर्थात् मैसर्स केंको मार्केटिंग, इंक., मैसर्स ह्यूमेड कॉर्पोरेशन, मैसर्स उबेस्को कॉर्पोरेशन, मै. कैमटाउन कं. लिमिटेड, मैसर्स हुंडई कॉरपोरेशन और मैसर्स वूरी पी एंड सी कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य के साथ प्रशावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। इन कंपनियों ने पीओआई के दौरान मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु का निर्यात किया।

38. मैसर्स केंको मार्केटिंग, इंक. ने भारत को मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित *** अम.डा. बीजक मूल्य की 15387 एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। मैसर्स केंको मार्केटिंग, इंक. द्वारा भारत को किए गए कुल निर्यात में से *** अम.डा. बीजक मूल्य वाली 12874.00 एमटी संबद्ध वस्तु को मैसर्स केंको मार्केटिंग, इंक. द्वारा सीधे भारत में बेचा गया है, और शेष *** अमरीकी डॉलर बीजक मूल्य की 2017.00 एमटी संबद्ध वस्तु को और *** अमरीकी डॉलर बीजक मूल्य की 496.00 एमटी संबद्ध वस्तु के भारत के लिए निर्यात को क्रमशः दो व्यापारियों अर्थात् मैसर्स इनोवस्को, सिंगापुर और यूनाइटेड रॉ मैटेरियल, सिंगापुर के माध्यम से भारत में बेचा गया

है।, चूंकि इन दो व्यापारियों ने अपने ईक्यूआर प्रस्तुत नहीं किए हैं इसलिए प्राधिकारी निर्धारण के लिए इन पर विचार नहीं किया है। मैसर्स केंको मार्केटिंग, इंक. ने बीमा, बैंक प्रभार, कमीशन, मूलता प्रमाणपत्र व्ययों, मालभाड़ा शुल्क, एल/सी खर्च पर समायोजन का दावा किया है। मैसर्स केंको मार्केटिंग, इंक. के संबंध में मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा दावा किए गए समायोजनों पर आवश्यक सत्यापन के बाद विचार किया गया है। तदनुसार, मैसर्स केंको मार्केटिंग, इंक. के लिए भारत औसत निर्यात कीमत *** अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

39. मैसर्स कैमटाउन कं. लिमिटेड ने भारत को मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड द्वारा निर्मित *** अमरीकी डॉलर बीजक मूल्य की 480 मी. टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है और समुद्री भाड़ा, सार-संभाल व्यय, कमीशन, बैंक प्रभार, बीमा, एल/सी व्यय और ऋण व्यय के लिए समायोजन का दावा किया है। मैसर्स कैमटाउन कं. लिमिटेड के संबंध में मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड द्वारा दावा किए गए समायोजनों पर आवश्यक सत्यापन के बाद विचार किया गया है। तदनुसार, मैसर्स कैमटाउन कं. लिमिटेड के लिए भारत औसत निर्यात कीमत *** अम.डा./एमटी के रूप में निर्धारित किया गया है।

40. मैसर्स ह्यूमेड कॉरपोरेशन ने भारत को मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड द्वारा निर्मित *** अमरीकी डॉलर बीजक मूल्य की 15581 मी. टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है और एल/सी व्यय, बैंक प्रभारों, मालभाड़ा व्यय, बीमा, कमीशन और ऋण व्यय के संबंध में समायोजन का दावा किया है। मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड द्वारा मैसर्स ह्यूमेड कॉरपोरेशन के संबंध में दावा किए गए समायोजनों पर आवश्यक सत्यापन के बाद विचार किया गया है। तदनुसार, मैसर्स ह्यूमेड कॉरपोरेशन के लिए भारत औसत निर्यात कीमत *** अम.डा./एमटी निर्धारित की गई है।

41. मैसर्स हुंडई कॉरपोरेशन ने भारत को मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड द्वारा निर्मित *** अमरीकी डॉलर बीजक मूल्य की 630 मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है और बीमा, बैंक प्रभार, एल/सी व्यय, दस्तावेज शुल्क और ऋण व्यय के संबंध में समायोजन का दावा किया है। मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड द्वारा मैसर्स हुंडई कॉरपोरेशन के संबंध में दावा किए गए समायोजनों पर आवश्यक सत्यापन के बाद विचार किया गया है। तदनुसार, मैसर्स हुंडई कॉरपोरेशन के लिए भारत औसत निर्यात कीमत *** अम.डा./एमटी निर्धारित की गई है।

42. मैसर्स उबेस्को कार्पोरेशन ने भारत को मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड द्वारा निर्मित *** अमरीकी डॉलर बीजक मूल्य की 1617 मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है और एल/सी व्यय, बैंक प्रभार, बीमा और ऋण व्यय के संबंध में समायोजन का दावा किया है। इसके अलावा, मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड द्वारा मैसर्स उबेस्को कार्पोरेशन के संबंध में दावा किए गए समायोजनों पर आवश्यक सत्यापन के बाद विचार किया गया है। तदनुसार, मैसर्स उबेस्को कार्पोरेशन के लिए भारत औसत निर्यात कीमत *** अम.डा./एमटी निर्धारित की गई है।

43. मैसर्स बूरी पी एंड सी कॉर्पोरेशन ने भारत को मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित *** अमरीकी डॉलर बीजक मूल्य की 16 एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, जिन्होंने आगे एक अन्य व्यापारी अर्थात् मैसर्स ऑक्साइड केमिकल्स चाइना लिमिटेड, हांगकांग के जरिए भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। चूंकि व्यापारी अर्थात् मै. ऑक्साइड केमिकल्स चाइना लिमिटेड, हांगकांग ने ईक्यूआर प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए प्राधिकारी ने मैसर्स बूरी पी एंड सी कॉर्पोरेशन के संबंध में निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए इन निर्यातों पर विचार नहीं किया।

44. तदनुसार, मैसर्स केंको मार्केटिंग, इंक. मैसर्स ह्यूमेड कॉर्पोरेशन, मैसर्स उबेस्को कार्पोरेशन, मै. कैमटाउन कं. लि. और मै. हुंडई कार्पोरेशन कोरिया आरपी के माध्यम से मैसर्स एकेयंग पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए निर्यातों के लिए भारत औसत निर्यात कीमत *** अम.डा./एमटी निर्धारित की गई है।

मैसर्स एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड, कोरिया आरपी के साथ मैसर्स ओसीआई कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

45. मैसर्स ओसीआई ने अपनी असंबंधित ट्रेडिंग कंपनी अर्थात् मैसर्स एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के साथ प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। पीओआई के दौरान, ओसीआई ने केवल एवरलाइट के जरिए भारत में 500 मिलियन टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। मैसर्स ओसीआई ने एफओबी शर्तों पर एवरलाइट को संबद्ध वस्तु बेची है। मैसर्स ओसीआई ने अंतर्देशीय भाड़े, पत्तन हैंडलिंग व्ययों, फ्लेक्सी टैंक फीस, क्रेडिट व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है। आवश्यक सत्यापन के बाद उसकी अनुमति दी गई है। एवरलाइट द्वारा दायर किए गए उत्तर से, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एवरलाइट ने हनवा केमिकल, जिन्होंने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तु के 3 निर्यात सौदों का निर्यात किया है। इसके अलावा, एवरलाइट ने एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तु के 4 निर्यात सौदों का निर्यात किया। तथापि, एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड ने एवरलाइट को पीओआई से पहले संबद्ध वस्तु बेची है। इसलिए, प्राधिकारी ने अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए एकेयंग पेट्रोकेमिकल कं. लिमिटेड कं. और हानवा केमिकल के लेन-देनों पर विचार नहीं किया है।

46. तदनुसार, एवरलाइट के माध्यम से ओसीआई के लिए भारत औसत निर्यात कीमत *** अम.डा./एमटी निर्धारित की गई है।

कोरिया गणराज्य से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य ने किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी को वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है। कोरिया में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के रूप में भारत औसत निर्यात कीमत *** अम.डा./एमटी निर्धारित की है।

चीनी ताइपेई**मैसर्स नेन या प्लास्टिक कापॉरेशन, चीनी ताइपेई के लिए सामान्य मूल्य**

48. पीओआई के दौरान मैसर्स नेन या प्लास्टिक कापॉरेशन ने घरेलू बाजार में *** एनटीडी बीजक मूल्य की 6987.59 एमटी संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन 80% से अधिक हैं तो प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में सभी लेनदेन पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया है और ऐसे मामलों में, जहां लाभकारी लेनदेन 80% से कम है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण हेतु केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ध्यान में रखा गया है। इस मामले में, व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण के आधार पर, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ली गई हैं, क्योंकि लाभदायक बिक्री 80% से कम थीं।

49. नान या प्लास्टिक कापॉरेशन ने मालभाड़ा व्यय, पैकिंग व्यय और ऋण व्यय के संबंध में समायोजन का दावा किया है जिन्हें प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और उन पर विचार किया गया है। तदनुसार, नेन या प्लास्टिक कापॉरेशन के लिए भारत औसत सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डॉलर / मीट्रिक टन के रूप में निर्धारित किया गया है।

चीनी ताइपेई से गैर-सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी ताइपेई से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। चीनी ताइपेई में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य *** अम.डा./एमटी निर्धारित किया है।

मैसर्स जेसी पेट्रोकेम लिमिटेड, हांगकांग के साथ मैसर्स नेन या प्लास्टिक कापॉरेशन, चीनी ताइपेई के लिए निर्यात कीमत

51. मैसर्स नेन या प्लास्टिक कापॉरेशन ने अपनी असंबंधित ट्रेडिंग कंपनी, अर्थात् मैसर्स जेसी पेट्रोकेम लिमिटेड, हांगकांग के साथ प्रशावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और उन्होंने पीओआई के दौरान मैसर्स नेन या प्लास्टिक कापॉरेशन द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

52. मैसर्स नेन या प्लास्टिक कापॉरेशन ने सीधे 278.34 एमटी पीयूसी का निर्यात किया है और मैसर्स जेसी पेट्रोकेम लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से 12985.13 एमटी का निर्यात किया है, चूंकि मैसर्स जेसी पेट्रोकेम लिमिटेड, हांगकांग ने ईक्यूआर प्रस्तुत किया था, इसलिए, प्राधिकारी ने भारत में निर्यात की गई कुल मात्रा के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है।

53. उन्होंने कमीशन, समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पैकिंग, बैंक प्रभार, व्यापार संवर्धन सेवा शुल्क, सीमा शुल्क निकासी शुल्क, बंदरगाह सेवा शुल्क, बंदरगाह सुविधा प्रभार, गोदी शुल्क, स्लॉट शुल्क और ऋण व्यय के लिए समायोजन का दावा किया है और कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए उचित सत्यापन के बाद भी इन पर विचार किया गया है। तदनुसार, भारत औसत निर्यात कीमत को *** अम.डा./एमटी के रूप में निर्धारित किया गया है।

चीनी ताइपेई के असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी ताइपेई से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। चीनी ताइपेई में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने भारत औसत निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर *** अम.डा./एमटी के रूप में निर्धारित की है।

पाटन मार्जिन तालिका

55. पीओआई के दौरान संबंधित संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन निम्न तालिका में दिए गए अनुसार निर्धारित किया गया है:

क्र.सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %	रेंज
1	कोरिया गणराज्य	मै. ऐकयंग पेट्रोकेमिकल कं. लि.	(क) मै. कैको मार्केटिंग इंक., (ख) मै. ह्यूमेड कापॉरेशन (ग) मै. यूबेस्को कापॉरेशन,	***	***	***	***	0-10

			(ग) मै. कैमटाउन कं. लि. (घ) मै. हुंडई कार्पोरेशन					
2	कोरिया गणराज्य	मै. ओसीआई कं. लि.	मै. एवरलाइट कोरिया कं. लि.	***	***	***	***	0-10
3	कोरिया गणराज्य	सभी अन्य	सभी अन्य	***	***	***	***	15-25
4	चीनी ताइपेई	मै. नान या प्लास्टिक कार्पोरेशन	(क) मै. नान या प्लास्टिक कार्पोरेशन (ख) मै. जेसी पेट्रोकेम लि., हांगकांग	***	***	***	***	20-30
5	चीनी ताइपेई	सभी अन्य	सभी अन्य	***	***	***	***	35-45

छ. क्षति निर्धारण

छ. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

56. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) आयात की मात्रा घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है क्योंकि आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम है।

(ii) पाटनरोधी नियमावली के तहत कम कीमत पर बिक्री विहित मापदंड नहीं है, इसलिए घरेलू उद्योग ने इस संबंध में जानकारी प्रदान नहीं की। क्षति मार्जिन और कम कीमत पर बिक्री प्राधिकारी की पिछली परिपाटी के अनुसार समान है। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से काफी कम थी। इस प्रकार, संबद्ध आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं।

(iii) घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान क्षति का दावा किया है और इसे विरोधी पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग घट गया है जो संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण है। 2014-15 में गिरावट बढ़ी हुई क्षमता में उत्पादन शुरू होने की वजह से है, दो साल के बाद भी क्षमता उपयोग का स्तर 2013-14 में हासिल किए गए स्तर से काफी कम है।

(iv) घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग एक अवधि में 39% से घटकर 26% हो गया है, जिसे स्थिर के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(v) आयातों में काफी वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग को मात्रात्मक क्षति हुई है। आयात में इस तरह की बढ़ोतरी के साथ, जांच के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन मात्रा और कीमत दोनों के संबंध में खराब हो गया है। घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन से यह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

(vi) याचिकाकर्ता का कच्ची सामग्री की कीमत में होने वाले बदलावों के कारण कीमत वृद्धि या कटौती को छोड़कर किसी भी तरह से कीमतों में वृद्धि करने का कोई इरादा नहीं है। उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित शुल्क का कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा।

(vii) घरेलू उद्योग बाजार पर कब्जा करने के लिए डीओपी के किसी भी स्थानापन्न को नहीं बेच रहा है क्योंकि डीओपी का कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं है। डीओपी की कीमतों के संबंध में, वे घरेलू उद्योग द्वारा बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों की तुलना में काफी अधिक हैं।

(viii) मात्रात्मक मापदंड के आधार पर क्षति का दावा किया गया है। घरेलू उद्योग ने कीमतों को समान रखा है, जिससे उसके मात्रा के संबंध में नुकसान हुआ है। उद्योग के पास केवल दो विकल्प हैं, या तो मात्रा को बनाए रखने के लिए कीमत पर समझौता करे और हानि उठाए, या कीमत को बनाए रखे और मात्रा में गिरावट का सामना करे। पाटित आयात के परिणामस्वरूप न केवल याचिकाकर्ता को बढ़ता हुआ नुकसान हुआ है, बल्कि भारत में पूरी तरह से डीओपी उद्योग को संचालन अक्षम हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन को निलंबित किया और आयात करने का सहारा लिया गया है। भारत में पहले लगभग 70 कंपनियों में डीओपी का उत्पादन होता था, लेकिन वर्तमान में 70 में से केवल 5 कंपनियों ने अपना उत्पादन जारी रखा है।

(ix) घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को थोक और पैक दोनों के लिए आकड़े प्रदान किये हैं। यहां तक कि थोक और पैक किए गए डीओपी की तुलना करने पर यह देखा जाएगा कि आयात घरेलू उत्पाद की कीमतों में इन अलग-अलग रूपों में भी कटौती कर रहे हैं।

(x) स्वीकार करने और स्वीकार नहीं करने पर, मूल्य दमन की कमी का मतलब यह नहीं है कि घरेलू उद्योग में कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण कीमत प्रभाव स्थापित करने के लिए सकारात्मक कीमत कटौती पर्याप्त है। नियमावली में जैसा कि कानून के तहत "या" के उपयोग द्वारा सिद्ध किया गया है कीमतों में कटौती और ह्रास/कमी को विकल्प के रूप में रखा है।

(xi) घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग दोनों में एक अवधि में गिरावट आई है।

(xii) विचाराधीन उत्पाद के लिए बिक्री के आंकड़े पहले ही प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए हैं और इसमें स्थिर सॉफ्टनर की बिक्री शामिल है घरेलू उद्योग की कुल बिक्री में एक अवधि में गिरावट आई है।

(xiii) घरेलू उद्योग द्वारा लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय या मालसूची में बढ़ोतरी के संबंध में क्षति का दावा नहीं किया गया है। पाटनरोधी शुल्क के लगने से सकारात्मक परिणाम होगा क्योंकि याचिकाकर्ता जो गंवाई गई मात्रा को हासिल करने में सक्षम होगा और बाजार में अपने हिस्से को बनाए रखेगा।

(xiv) रोजगार के स्तर के संबंध में, घरेलू उद्योग ने इस आधार पर क्षति का दावा नहीं किया है। ये देश में कई विधायी आवश्यकताओं और घरेलू उद्योग के साथ विभिन्न व्यावसायिक अनिवार्यता द्वारा शासित होते हैं। रोजगार और मजदूरी घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रतिकूल प्रभावों को नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि ये कारक कंपनी और अर्थव्यवस्था के समग्र संचालन से शासित होते हैं।

(xv) याचिकाकर्ता का विचाराधीन उत्पाद को निर्यात करने का कोई इरादा नहीं है। कंपनी द्वारा स्थापित क्षमता भारतीय बाजार के लिए है। अगर निर्यात का इरादा होता तो याचिकाकर्ता ने ऐसे निर्यात के लिए लाभ लेने के लिए ईओयू या एसईजेड में क्षमता स्थापित की होती।

(xvi) आयात की पहुंच कीमत एनआईपी से नीचे है और क्षति मार्जिन सकारात्मक है।

(xvii) घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन पर पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन संचयी आधार पर होना चाहिए, न कि देश के अनुसार। किसी भी मामले में, ताइवान से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

(xviii) कीमत मापदंडों के संबंध में वृद्धि दिख रही है। घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच अवधि के दौरान मूल्य की क्षति का दावा नहीं किया है लेकिन जांच अवधि में मात्रात्मक क्षति और जांच की अवधि के बाद कीमत और मात्रा संबंधी क्षति के बारे में दावा किया है।

(xix) वर्तमान मामले में, अग्रिम लाइसेंस के तहत आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि घरेलू उद्योग के साथ क्षमताएं अप्रयुक्त रह जा रही हैं। यदि निर्यातकों अपाटित कीमत पर बिक्री करते हैं, तो घरेलू उद्योग उपभोक्ताओं की इस आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा।

(xx) आयात भारतीय बाजार में बिक्री लागत और बिक्री कीमत की तुलना में भी कम कीमत पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे हैं। इसके अलावा, फिलैलिक एनहाइडाइड पाटनरोधी शुल्क जांच में घरेलू उद्योग की भागीदारी की वर्तमान मामले में कोई भी प्रासंगिकता की नहीं है। कच्चे माल पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का विरोध करना अपने उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की मांग करने को नहीं रोकता है।

(xxi) विरोधी हितबद्ध पक्ष ने स्वीकार किया है कि आयात में वृद्धि हुई है। पाटन के संबंध में, याचिकाकर्ता ने पहले ही याचिका में संबंधित उत्पाद के पाटन की मौजूदगी को सिद्ध किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

(xxii) विचाराधीन उत्पाद का आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहा है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आयात की कीमत विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत से कम है। इसके अलावा, यह तथ्य कि पायल पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड के पास अपनी विनिर्माण सुविधाएं हैं और इसे अपने उत्पादन को निलंबित रखने के लिए मजबूर होना जरूरी है और इसके बजाए अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए आयात करना यह सिद्ध करने को पर्याप्त है कि डीओपी उद्योग को हानिकारक आयात का सामना करना पड़ रहा है। पायल पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने सार्वजनिक सुनवाई में स्वयं यह बात कही है।

छ.2 निर्यातकों, आयातकों, उपयोगकर्ता और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

57. निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) घरेलू उद्योग पीयूसी के पाटित आयात के कारण वास्तविक क्षति के लिए कोई साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा है।

(ii) आवेदक वास्तविक क्षति क्या किसी भी क्षति का मामला नहीं बना पाए हैं। लगभग सभी क्षति मानदंडों में आधार वर्ष से और पूर्ववर्ती वर्षों से सुधार प्रदर्शित होता है, जो क्षति क्या वास्तविक क्षति भी नहीं दर्शाता है।

(iii) बिक्री लागत और बिक्री कीमत में काफी गिरावट आई है। कच्चे माल की कीमतों में भारी गिरावट आई है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा कीमत कटौती का दावा गलत है क्योंकि आयातित वस्तुओं की कीमतों में गिरावट वास्तव में कच्चे माल की कीमतों में गिरावट और बिक्री की कीमतों और घरेलू उद्योग की कीमतों की बिक्री के अनुपात में है। कीमत कटौती क्षति का एक कारक नहीं है। कम कीमत पर बिक्री के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हम यह अनुमान लगाने के हकदार हैं कि कम कीमत पर बिक्री का कोई भी मुद्दा नहीं है।

(iv) पीओआई को छोड़कर घरेलू उद्योग का उत्पादन बढ़ा है। संयंत्र की क्षमता का उपयोग एक समान रहा है। बाजार हिस्सेदारी में गिरावट पीयूसी से अन्य उत्पादों के लिए फोकस के कारण है, जो उनके लिए अधिक लाभदायक उत्पाद हो सकते हैं।

(v) आधार वर्ष से प्रति यूनिट लाभ और नकद लाभ में वृद्धि हुई है। आरओसीई 15-25% की के बीच है, जो कि काफी अधिक है लेकिन यह किसी भी क्षति की संभावना से इनकार करता है। तालिका से, यह देखा जा सकता है कि बिक्री की लागत में 34% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि बिक्री कीमत में केवल 31% की गिरावट आई, लाभ में प्रति यूनिट 71% की वृद्धि हुई, नकद लाभ में 58% की वृद्धि हुई, ब्याज और कर पूर्व लाभ में 42% की वृद्धि, रोजगार में 14% मजदूरी में 21% की वृद्धि, कार्यशील पूंजी में 21% की वृद्धि हुई, नियोजित पूंजी पर आय में 15-25% की वृद्धि हुई।

(vi) घरेलू उद्योग द्वारा क्षति का दावा आधारहीन, गलत तरीके से, कानूनी रूप से कमजोर है और पाटनरोधी नियमावली की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता है। मात्रा या मूल्य की क्षति का दावा करने का कोई अवसर नहीं है।

(vii) घरेलू उद्योग ने क्षति की गणना करते समय संबद्ध देशों से स्वयं-आयात शामिल किए हैं और मांग और उसके रुझान, आयात में संबद्ध देशों से आयात के बाजार हिस्से, मांग में संबद्ध देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी और उत्पादन में संबद्ध देशों से आयात के बाजार हिस्से की गणना के आधार दोषपूर्ण हैं।

(viii) आयात के रुझान में क्षति के मापदंडों के रुझान के साथ कोई सह-संबंध नहीं है। आयात और क्षति के मापदंड (बिक्री, नकद लाभ और लाभ) के बीच विपरीत संबंध है।

(ix) याचिकाकर्ता पर्याप्त लाभ और नियोजित पूंजी पर आय का आनंद ले रहे हैं, जबकि आयातक कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं और कच्चे माल की कीमतों में बदलाव के संबंध में बेहद संवेदनशील हैं।

(x) घरेलू उद्योग डीओपी के इन स्थानापन्नों को कम कीमत पर बेच रहा है, ताकि यह दावा करते हुए बाजार हासिल किया जा सके कि ये बेहतर प्रदर्शन करने वाले उत्पाद हैं। आयात के कारण क्षति का दावा निराधार है। यदि शुल्क लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग विकल्पों की कीमतें भी बढ़ाएगा।

(xi) प्रपत्र IV-ए में, पूरे संयंत्र के उत्पादन में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है, जबकि उत्पादन और क्षमता उपयोग पीयूसी में स्थिर रहा है।

(xii) घरेलू उद्योग, पीओआई के दौरान लाभकारी कीमतों पर डीओपी का निर्माण और बिक्री कर रहा है, इसलिए यह तर्क कि अन्य उत्पादकों को आयात करने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि भारत में डीओपी का उत्पादन अव्यवहार्य हैं, हास्यास्पद है। पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग पीओआई में अपने लाभ को दोगुना करने में सक्षम रहा है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि क्यों अन्य उत्पादकों को आयात करने के पक्ष में उत्पादक गतिविधियों को छोड़ना पड़ा। यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है।

(xiii) यह दावा किया गया है कि 5% से 15% की भारी कीमत कटौती हुई है, यह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ आयात के पंधुच मूल्य के साथ अनुचित तुलना का परिणाम है। कीमत कटौती केवल इसलिए होती है क्योंकि थोक आयातों की तुलना ड्रम में बिक्री से की गई है। थोक और पैक की गई स्थिति में उत्पाद के लिए अलग-अलग कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत हास निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(xiv) कीमत हास का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि बिक्री लागत बिक्री कीमत से अधिक घट गई है जिसके परिणामस्वरूप पिछले साल की तुलना में लाभ में वृद्धि हुई है और पीओआई में लाभ दोगुना हो गया है।

(xv) क्षति की अवधि के दौरान संयंत्र की क्षमता का उपयोग कमोवेश सुसंगत रहा है। अन्य उत्पादों (प्रतिस्थापन) और विस्तार के कारण क्षमता के विचलन के कारण यह घट गया है। जबकि लाभप्रदता, निवेश पर लाभ, नकदी प्रवाह आदि सकारात्मक रुझान दिखाते हैं।

(xvi) क्षमता उपयोग के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा 26% का दावा बिल्कुल गलत है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उत्पादित सभी उत्पादों के लिए कुल स्थापित क्षमता 1,80,000 मीट्रिक टन है और उत्पाद की कोई समर्पित क्षमता नहीं है। इसलिए क्षमता उपयोग का विश्लेषण भ्रामक है।

(xvii) मांग में वृद्धि के कारण आयात में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग ने अपने संबंधित पक्षों के जरिए पीयूसी का आयात किया है और इसलिए क्षति स्वयं-आरोपित प्रतीत होती है।

(xviii) बिक्री की मात्रा कम हो गई है और घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई उत्पादित सॉफ्टनर उत्पाद की बिक्री मात्रा के साथ इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। जांच तब की जा सकती है जब दोनों उत्पादों की बिक्री जोड़ी जाए क्योंकि ये दोनों परस्पर प्रतिस्थापन योग्य और समान वस्तु हैं।

(xix) घरेलू उद्योग के लाभ में वृद्धि हुई है और घरेलू बाजार में उनकी कीमतों को प्रभावित करने या उनके कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने में आयात की कोई भूमिका नहीं है। अपने खरीदारों के लिए लागत में कमी को पूरी तरह से आगे नहीं करने के कारण क्षति जांच अवधि के दौरान नकद लाभ में भी वृद्धि हुई है। क्षति की अवधि में आरओसीई बढ़ गया है, कोई क्षति नहीं हुई है।

(xx) याचिकाकर्ता की क्षमता और क्षमता उपयोग के लिए, 2014-15 को आधार वर्ष माना जाना चाहिए, क्योंकि डीआई ने इस वर्ष में अपनी क्षमता में वृद्धि की है। क्षमताओं में अनुचित वृद्धि के कारण क्षति हुई है।

(xxi) लाभ, नकद लाभ और ब्याज और कर पूर्व लाभ में वृद्धि हुई है। आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं।

(xxii) नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में, डीआई को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है क्योंकि याचिकाकर्ता अपना उत्पाद एनआईपी से उच्च कीमत पर बेच रहा है।

(xxiii) कीमत कटौती छिटपुट है और सार्थक कीमत प्रभाव नहीं दर्शाती है।

(xxiv) कोई नकारात्मक प्रवृत्तियां नहीं हैं क्योंकि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(xxv) याचिकाकर्ता अच्छा काम कर रहा है और नियोजित पूंजी पर 22% आय प्राप्त कर रहा है और वर्ष-दर-वर्ष अपनी लाभप्रदता बढ़ा रहा है, घरेलू उद्योगों को संबद्ध देशों से आयात द्वारा कोई क्षति नहीं हुई है।

(xxvi) कुल मांग में ताइवान का हिस्सा पीओआई के दौरान केवल 5% है इसलिए कोई भी मात्रा प्रभाव या कीमत प्रभाव ऐसे नगण्य आयात से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(xxvii) घरेलू उद्योग का मुनाफा पीओआई में सबसे अधिक था जब आयात सबसे अधिक था इसलिए कोई क्षति नहीं हुई है और कोई कीमत कटौती नहीं है। इस मामले को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि आकड़ों में कथित रूप से आयातित वस्तुओं के मुकाबले भारी लाभ का पता चलता है। याचिकाकर्ता एक लाभकारी उद्योग है और लगातार स्पष्ट रूप से विस्तार करते हुए बढ़ रहा है।

(xxviii) इस मामले में पाटनरोधी शुल्क भारतीय घरेलू उद्योग के दीर्घकालिक और हितों और उसके डाउनस्ट्रीम उद्योगों के साथ असंगत होगा। यह एक अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का कारण बनेगा और उनके संबंधित मौलिक हितों को नुकसान पहुंचाएगा।

(xxix) आयात ऐसी कीमतों पर हैं, जो डीओपी के उपयोगकर्ताओं के मुकाबले कम हैं। घरेलू उद्योग द्वारा सुनवाई के दौरान झूठा वक्तव्य दिया गया है क्योंकि भारतीय उत्पादकों ने भारतीय डीओपी बाजार पर मजबूत पकड़ कायम रखी है। पीओआई में स्थिति समान है, जबकि कुछ उत्पादकों ने आयात के विकल्प चुना है, जबकि अन्य ने विनिर्माण कार्यों को जारी रखा है। उपयोगकर्ता भारतीय उत्पादकों की दया पर आश्रित हैं।

(xxx) कच्चे माल की कीमतों में कमी के कारण आयात की कीमत में कमी आई है, घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने फथेलिक एनहाइड्राइड पर शुल्क का विरोध किया है, जो पीयूसी के लिए मुख्य कच्चा माल है।

(xxxi) आपूर्ति में कमी का कारण कच्चे माल अर्थात् अक्टोनॉल की भारी कमी है और उसके लिए केवल एक ही उत्पादक का होना है। इस प्रकार मांग आपूर्ति अंतर को पाटने के लिए भी ऑक्टोनल का आयात किया जाता है।

(xxxii) पाटनरोधी के माध्यम से याचिकाकर्ताओं द्वारा कोटा को फिर से बहाल करना, कमी पैदा करना और पाटनरोधी शुल्क के बाद पहुंच कीमतों पर आधारित उनकी कीमतों का समायोजन करके अपने लाभ को और अधिक बढ़ाया जाएगा। पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव से आयात होना बंद हो जाएगा जिससे डीओपी के उपभोक्ता उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा।

(xxxiii) आयात में वृद्धि पाटन की वजह से नहीं है बल्कि भारत और कोरिया के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के कारण हुई है जिसके परिणामस्वरूप अधिसूचना सं. 152/2009 द्वारा कोरिया से डीओपी के आयात पर सीमाशुल्क में कमी आई है। आयात में वृद्धि लागू टैरिफ और शुल्कों में बदलाव का परिणाम है।

(xxxiv) क्षति, वास्तविक या अन्यथा का दावा संदिग्ध है क्योंकि याचिकाकर्ता ने क्षति की अवधि में और यहां तक कि पीओआई में भी उच्च लाभ कमाया है।

(xxxv) मापदंडों की जांच करते समय प्राधिकारी को पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू कीमतों पर इसके प्रभाव की जांच एक साथ करना अपेक्षित है। वर्तमान जांच में यह स्पष्ट है कि आयात की बढ़ती मात्रा का घरेलू कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रभाव की यह कमी कीमत ह्रास/मंदी की कमी से सिद्ध होती है। इसके अलावा, बड़े हुए आयात और कीमतों में कटौती के बावजूद लाभप्रदता उच्च रही है।

(xxxvi) घरेलू उद्योग द्वारा आयात में वृद्धि (367%) और मांग में वृद्धि (47%) की तुलना करते हुए आंकड़े भ्रामक और पृथक हैं। इसके बजाय, पाटित आयातों में इस तरह की वृद्धि मांग का 47% है, विवादास्पद है। इसके अलावा, इस तरह की पर्याप्त वृद्धि के साथ याचिकाकर्ता के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राधिकारी केवल आयात की मात्रा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर आयात के प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए।

(xxxvii) याचिकाकर्ता का यह दावा कि आयात की पहुंच कीमत याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत में भारी कटौती कर रही थी और वह क्षतिरहित कीमत के कम थी, तथ्य के विना है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की बिक्री कीमतों में कटौती सभी निर्यातकों के लिए औसत पर आधारित है, विशेषकर ओसीआई और एवरलाइट के लिए नहीं। कटौती की सीमा 15-25% के भीतर है। यह भी देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को क्षति की अवधि में उच्च लाभ हो रहा है जहां सकारात्मक कटौती हुई है।

(xxxviii), यूरोपीय संघ से एक्सरे बैगज इंस्पेक्शन मल्टी एनर्जी सिस्टम (एक्सबीआईएस) के आयात और रूस और ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अमोनियम नाइट्रेट के आयात के संबंध में डीजीएटी के निष्कर्षों पर भरोसा किया गया है, जिसमें निवल बिक्री प्राप्ति निर्धारित एनआईपी से अधिक थी, संभवतः याचिकाकर्ता के इस दावे के तहत कोई भी क्षति नहीं हुई हो कि पहुंच कीमत क्षतिरहित कीमत से कम है।

(xxxix) 2014-15 में याचिकाकर्ता द्वारा बड़ी हुई क्षमता के दावे और पीयूसी के प्लांट में अन्य उत्पादों के साथ में निर्माण के विरुद्ध कोई भी अनुरोध नहीं किया गया है। इसके अलावा, 2014-15 में हुए नुकसान का कारण डीओपी के उत्पादन की क्षमता में विस्तार के कारण स्थिर लागत और/या ओवरहेड लागत का होना है। इसके अलावा, 2014-15 में ऋणात्मक कीमत कटौती दर्ज की गई जिसके दौरान नुकसान हुआ था।

(xl) क्षति का दावा इस आधार पर है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है। इस संबंध में, मामूली गिरावट आई है और अगर हम केवल एक वर्ष को छोड़ देते हैं तो आयात में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री बढ़ी है। इसलिए, आयात में वृद्धि और उत्पादकता और/या याचिकाकर्ता की बिक्री में वृद्धि या कमी के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

(xli) नियंत्रित उत्पादन और कम क्षमता उपयोग की स्थिति डीओपी के लिए कच्चे माल पर पाटनरोधी शुल्क के कारण हुई है और भारत में पाटित आयात के कारण नहीं हुई है। याचिकाकर्ता क्षति के एक घटक के रूप में आयात में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो वास्तव में डीओपी के कच्चे माल पर पाटनरोधी शुल्क के कारण हुई है और क्षमता उपयोग में गिरावट के कारण भी हुई है।

(xlii) वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और उनके द्वारा उच्च लाभ अर्जित किए गए हैं। चीन जन. गण. और वियतनाम के मूल की अथवा वहां से निर्यातित एए ड्राय सेल बैटरियों पर भरोसा किया गया है, जिसमें इसी तरह के तथ्य मौजूद थे और प्राधिकारी ने जांच को समाप्त कर दिया था।

(xliii) वर्तमान जांच में कीमत कटौती की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि लाभ और आरओसीई दोनों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कीमतों की कमी क्षति का एक कारक नहीं है, रेडियल टायर के मामले में माननीय सेस्टेट के फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसमें यही माना गया था। इसके अलावा कीमत ह्रास या मंदी के संबंध में, कच्चे माल की कीमत में गिरावट के कारण लागत में कमी की तुलना में बिक्री कीमत में कमी आई है।

(xliv) स्थापित क्षमता के उपयोग के संबंध में क्षति मापदंडों की जांच गलत और भ्रामक है। प्राधिकारी को निष्कर्ष निकालने के द्वारा क्षमता उपयोग की जांच करनी चाहिए कि यह मापदंड घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कोई संकेत नहीं देता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि, क्षति की अवधि में संयंत्र के उत्पादन में 35% की वृद्धि हुई है और क्षमता उपयोग के संदर्भ में कोई क्षति नहीं हुई है।

(xlv) घरेलू उद्योग द्वारा अपनी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के लिए तर्क के संबंध में, पीयूसी और अन्य उत्पादों दोनों की बाजार हिस्सेदारी का विश्लेषण एक साथ किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों परस्पर प्रतिस्थापन योग्य हैं और बाजार हिस्से की सार्थक जांच के लिए समान वस्तु हैं।

(xlvi) घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कथित रूप से पाटित आयात से कोई क्षति नहीं हुई है उनकी याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सामग्री और आकड़े कंपनी द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में तथ्यों, बयान और प्रतिज्ञान के साथ विरोधाभासी है।

(xlvii) कुल आयात का 70% डीओपी के निर्माताओं द्वारा ऐसी कीमतों पर किया जा रहा है, जो डीओपी के उपयोगकर्ताओं के मुकाबले कम है। हालांकि, यह इस बात का समर्थन करता है कि क्षति, यदि कोई हो, तो स्व-आरोपित है।

(xlviii) सभी प्रकार की डीओपी को क्षति के मानकों जैसे कि घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री के लिए शामिल किया गया है। सभी प्रकार के डीओपी के विवरण, ब्रांड नाम, को सार्वजनिक करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है जिन्हें क्षति विश्लेषण के उद्देश्यों के लिए शामिल या शामिल नहीं किया गया है। कुछ भारतीय उत्पादकों द्वारा 3904 22 90 के शीर्ष या 2917 3400 के शीर्ष के तहत डीओपी की बिक्री के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने कनॉटोल 800 को पीओआई के दौरान 2917 3400 के शीर्ष के तहत स्वीकृति दी है।

(xlix) याचिकाकर्ता को हुई क्षति पाटन के कारण नहीं हुई है बल्कि कोरिया और भारत के बीच टैरिफ और शुल्कों में बदलाव के कारण हुई है। 8,500 एमटी का आयात शुल्क मुक्त है और संबद्ध देशों से आयात की मात्रा के सही आंकड़े ज्ञात करने के लिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत किए गए आयात पर कोई भी पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

(i) डीओपी के निर्माताओं द्वारा किए गए आयात डीओपी के उपयोगकर्ताओं की तुलना में कम कीमत पर हैं। इसलिए, कटौती उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए आयात द्वारा नहीं की गई है, बल्कि भारतीय निर्माता द्वारा किए गए आयातों के कारण है।

(ii) क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, निवेश पर लाभ, नकदी प्रवाह इत्यादि पर पाटित आयात के प्रभाव के संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्षति की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग सुसंगत है। विकल्प और विस्तार के लिए क्षमताओं के विपथन के कारण पीयूसी के लिए क्षमता उपयोग में कमी आई है। जबकि लाभप्रदता, निवेश पर लाभ, नकदी प्रवाह आदि सकारात्मक रुझान दर्शाते हैं।

(iii) प्राप्ति योग्य उत्पादन के आधार पर उत्पादन के भारी नुकसान के लिए याचिकाकर्ता का दावा खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है, जो किसी कोई भी गिरावट नहीं दर्शाता है।

(liii) याचिकाकर्ता कारणात्मक संबंधी सिद्ध करने में असमर्थ है क्योंकि आयात में वृद्धि, निरंतर कीमत कटौती और आर्थिक मापदंडों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।

(liv) याचिकाकर्ता ने अनजाने में स्वीकार किया है कि डीओपी उद्योग लागत पर आधारित है और अनुरोध के पैरा 5 में इसे 90% के बराबर बताया है। प्राधिकारी को नोट करना चाहिए कि कच्चे माल पर पाटनरोधी शुल्क से लागत उच्च हो गई है। यह संबद्ध वस्तु के लघु उत्पादकों के लिए सच है।

(lv) यह तथ्य कि अन्य भारतीय उत्पादकों को आयात करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि भारत में डीओपी का उत्पादन अव्यवहार्य है, तर्कहीन है। याचिकाकर्ता पीओआई के दौरान लाभ कमाने में सफल रहा है। इसके अलावा, भारतीय उत्पादकों द्वारा किए गए आयात के लिए कोई औचित्य नहीं है।

(lvi) 2016-17 की जिला औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यथा साक्ष्य प्रदत्त, जिसमें याचिकाकर्ता का उल्लेख शीर्ष 50 बड़े पैमाने पर और मध्यम स्तरीय इकाइयों में से एक के रूप में किया गया है और टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये से अधिक का होने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में यह तर्क कि वे लघु उत्पादक हैं पूरी तरह अतार्किक है।

(lvii) पीओआई के बाद के आकड़ों के संबंध में, प्राधिकारी पाटनरोधी जांच में निर्धारण करने के दौरान उसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।

(lviii) वर्तमान आवेदन घरेलू बाजार में एकाधिकार रखने और पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद लाभ बढ़ाने का एक प्रयास है।

(lix) घरेलू उद्योग में होने वाली क्षति कच्ची सामग्रियों की उच्च लागत के कारण हुई है क्योंकि उनपर पाटन शुल्क लगाए गए हैं। यह घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन के कारण भी हुई है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

58. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई है और नीचे समाधान किया गया है :

59. अन्य हितबद्ध पक्षों की इस दलील के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित अन्य उत्पादों के कारण हुई है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क संबंधित उत्पाद से हुई क्षति के कारण अनुशंसित किया जाता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पीयूसी के संबंध में सत्यापित सूचना घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो, की जांच पर विचार किया गया है।

ज. संचयी मूल्यांकन

60. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iii) में यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-

- (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत (या अधिक) से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक बनता है; तथा
- (ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

क. संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तु पाटित की जा रही है। संबद्ध देशों में से प्रत्येक से पाटन का मार्जिन नियमावली के अधीन विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. संबद्ध देशों में से प्रत्येक से आयात की मात्रा अलग-अलग आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा बेची जाने वाली समान वस्तु से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

62. उक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह समझते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यातों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करना उचित है।

63. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

झ. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**i. आयातों की मांग और मात्रा**

64. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे सारणी में दी गई है। यह देखा जा सकता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.ट.	46,220	50,456	53,858	45,319
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	117	98
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	मी.ट.	27,329	26,451	26,622	16,951
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	97	62
संबद्ध देश	मी.ट.	11,235	9,007	36,291	56,527
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	323	503
अन्य देश	मी.ट.	904	305	344	813
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	34	38	90
मांग/खपत	मी.ट.	85,687	86,218	1,17,115	1,19,610
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	137	140

ii. आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

65. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में पाटित आयातों में कुल रूप में अथवा उत्पादन या खपत के सापेक्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:

आयातों की मात्रा	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई
संबद्ध देश	मी.ट.	11,235	9,007	36,291	56,527
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	323	503
अन्य देश	मी.ट.	904	305	344	813
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	34	38	90
कुल आयात	मी.ट.	12,139	9,312	36,636	57,340
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	302	472
आयातों में बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश	%	93	97	99	99
अन्य देश	%	7	3	1	1
कुल	%	100	100	100	100
के संबंध में आयात					
- आयात	%	92.55	96.72	99.06	98.58
- उत्पादन	%	15.54	11.89	45.36	89.87
- मांग	%	13.11	10.45	30.99	47.27

66. यह नोट किया गया है कि-

- क्षति अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में कुल रूप में वृद्धि हुई है।
- भारत में विचाराधीन उत्पादन के कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।
- क्षति अवधि में भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।

ट. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव:**(i) कीमत में कटौती**

67. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना अपेक्षित है कि भारत में समान उत्पाद की कीमतों के साथ तुलना किए जाने पर क्या पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से कीमत कटौती की गई है अथवा ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण स्तर तक कीमतों में ह्रास किया है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक घटित हुआ होता।

68. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के साथ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना की है, इस संबंध में, उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच व्यापार के समान स्तर पर सभी छूटों और करों को घटाकर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों को कारखानागत स्तर पर निर्धारित किया गया था। यह तुलना दर्शाती है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों के मूल की संबद्ध वस्तुएं भारतीय बाजार में उन कीमतों पर आयातित की गई थीं जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से निम्न थीं। इस प्रकार यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे थे और कटौती मार्जिन नीचे दी गई सारणी में दर्शाए गए अनुसार हैं: आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं:

विवरण	यूनिट	कोरिया जन गण.	ताइवान	संबद्ध देश
आयातों की पहुंच कीमत	रु./मी.ट.	62,940	62,371	62,876
निवल बिक्री कीमत	रु./मी.ट.	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी.ट.	***	***	***
कीमत कटौती (%)	%	***	***	***
कीमत कटौती	(रेंज %)	10-20%	15-25%	10-20%

क्र.सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	पहुंच मूल्य	बिक्री कीमत	कीमत कटौती	कीमत कटौती %	रेंज
1	कोरिया जन गण.	मै. एकयुंग पैट्रोकेमिकल कं. लि.,	क) मै. कान्को मार्केटिंग इंक (ख) मै. हुमाडे कॉरपोरेशन (ग) मै. उबेस्को कॉरपोरेशन (घ) मै. कैमटाउन कं. लि. (ड.)मै. हुंडई कॉरपोरेशन	***	***	***	***	10-20
2	कोरिया जन गण.	मै. ओसीआई कं. लि.,	मै. एवरलाइट कोरिया कं. लि.	***	***	***	***	0-10
3	चाइनीज ताइपेई	मै. नान या प्लास्टिक कॉरपोरेशन	(क) मै. नान या प्लास्टिक कॉरपोरेशन (ख) मै. जेसी पैट्रोकेम लि. हांगकांग	***	***	***	***	0-10

संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक है।

(ii) कीमत से कम कीमत पर बिक्री

69. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही कीमत से कम कीमत पर बिक्री की भी जांच की है। इस प्रयोजन हेतु, घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी की आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की भारांशित औसत एनआईपी की आयातों की भारांशित पहुंच कीमत के साथ तुलना निम्नानुसार दर्शाती है:

क्र.सं.	देश	उत्पादन	निर्यातक	पहुंच मूल्य	एनआईपी	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %	रेंज
1	कोरिया जन गण.	मै. एकयुंग पैट्रोकेमिकल कं. लि.,	(क) मै. कान्को मार्केटिंग इंक (ख) मै. हुमाडे कॉरपोरेशन (ग) मै. उबेस्को कॉरपोरेशन (घ) मै. कैमटाउन कं. लि. (ड.)मै. हुंडई कॉरपोरेशन	***	***	***	***	5-10
2	कोरिया जन गण.	मै. ओसीआई कं. लि.,	मै. एवरलाइट कोरिया कं. लि.	***	***	***	***	0-(5)
3	कोरिया जन गण.	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	25-30
4	चाइनीज ताइपेई	मै. नान या प्लास्टिक कॉरपोरेशन	(क) मै. नान या प्लास्टिक कॉरपोरेशन (ख) मै. जेसी पैट्रोकेम लि. हांगकांग	***	***	***	***	(5)- (10)
5	चाइनीज ताइपेई	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	10-15

70. सत्यापित आंकड़े/सूचनाके आधार पर, यह नोट किया गया है कि कोरिया जन.गण से ओसीआई और चीनी ताइपेई से नान या प्लास्टिक के मामले में कीमत से कम कीमत पर बिक्री ऋणात्मक है।

(iii) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

71. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव का प्रयोजन कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक कम करना या कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण सीमा तक घटित हुआ होता, प्राधिकारी ने क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया है। स्थिति नीचे सारणी में दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई
आयातों की पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	1,10,916	1,04,054	67,487	62,876
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	61	60
बिक्रियों की लागत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	70	67
बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	70	69

72. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में क्षति की अवधि में गिरावट आई है, लेकिन जांच की अवधि के दौरान बिक्री कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत काफी अधिक है। अतः गिरती हुई लागतों की स्थिति में घरेलू उद्योग वह कीमत वसूल करने में सक्षम रहा है, जिसने उसके लाभ के मार्जिन में सुधार किया है। चूंकि, बिक्री कीमत उत्पादन लागत से कम गिरी है, अतः यह सिद्ध है कि आयातों के कारण न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं हुआ है।

ट. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

73. ए डी नियमावली के अनुबंध II के अनुसार यह जरूरी है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपूर्ण जांच शामिल हो। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, ए डी नियमावली में आगे व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और आंकड़ों का उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिसमें बिक्रियों में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, उत्पाद, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर वापसी या क्षमता का उपयोग घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल सूची, रोजगार, वेतन, संवृद्धि, पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता शामिल होंगे।

74. घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदंडों का, तदनुसार, यहां नीचे विश्लेषण किया गया है।

ठ. बिक्रियां, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग

75. उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था :

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई
क्षमता	मी.ट.	120,000	180,000	180,000	180,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	150	150
पीयूसी उत्पादन	मी.ट.	46,262	50,533	54,594	45,945
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	118	99
संयंत्र उत्पादन	मी.ट.	115,378	135,200	155,139	155,252
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	132	135
पीयूसी क्षमता उपयोग	%	38.55	28.07	30.33	25.52
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	79	66
क्षमता उपयोग संयंत्र	%	96.15	75.11	86.19	86.25
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	90	90
घरेलू बिक्रियां	मी.ट.	46,220	50,456	53,858	45,319
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	117	98
मांग	मी.ट.	84,391	84,983	115,914	119,610
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	128	142

76. प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि घरेलू उद्योग ने 2014-15 में अपनी क्षमता को बढ़ाया है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में 2015-16 तक वृद्धि हुई है किंतु जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। विचाराधीन उत्पाद की मांग में 42% तक की वृद्धि हुई है किंतु घरेलू उद्योग ने डीओपी के उत्पादन के लिए संयंत्र का उपयोग करने के स्थान पर, इस सुविधा का उपयोग थालेट्स का उत्पादन करने के लिए किया है जैसे कि संयंत्र उत्पादन में गिरावट नहीं आई हो। यह भी नोट किया गया है कि डीओपी के लिए कोई समर्पित संयंत्र क्षमता नहीं है और चूंकि डीओपी सहित सभी थालेट्स के उत्पादन के लिए समान पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए डीओपी के लिए संयंत्र का उपयोग न किए जाने के कारण मात्रा संबंधी क्षति के घरेलू उद्योग के दावे की पुष्टि नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, संयंत्र का उपयोग अन्य प्लास्टिसाइजर्स के उत्पादन के लिए किया गया है और इस प्रकार गिरावट का कोई लक्षण नहीं है।

77. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने संयंत्र में अन्य उत्पादों का उत्पादन दिया है और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग ने तर्क किया है कि उन्होंने डीओपी के विनिर्माण के लिए संयंत्र स्थापित किया है और किसी अन्य उत्पादों के लिए नहीं, तथापि पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा है। प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों के तर्कों की जांच की है और रिकार्डों की उचित जांच के बाद, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने संयंत्र क्षमता का उपयोग डीओपी के उत्पादन के लिए प्रयोग करने के स्थान पर प्लास्टीसाइजर समूह के अन्य उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए किया है। संयंत्र उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है।

II. मांग में बाजार हिस्सा

78. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की निम्नानुसार जांच की गई है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	54.77	59.37	46.46	37.89
अन्य उत्पादक	%	30.85	29.67	21.93	14.17
संबद्ध देश-आयात	%	13.31	10.60	31.31	47.26
अन्य देशों से आयात	%	1.07	0.36	0.30	0.68
कुल	%	100	100	100	100

79. यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष, साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। क्षति अवधि के दौरान अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में भी गिरावट आई है। क्षति अवधि में संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि अन्य देशों का बाजार हिस्सा स्थिर बना रहा है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि संबद्ध देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग के डीओपी के बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है इसे ध्यान में रखते हुए कि डीओपी के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने के स्थान पर संयंत्र का प्रयोग अन्य प्लास्टिसाइजर्स के उत्पादन के लिए किया जा रहा है। यह भी नोट किया गया कि समान उत्पादन पद्धति का प्रयोग डीओपी सहित सभी प्रकार के प्लास्टिसाइजर्स को बनाने के लिए किया जा रहा है।

III. लाभ/हानि, नकद प्रवाह, नियोजित पूंजी पर वापसी

80. घरेलू उद्योग के निवेश पर लाभ/हानि, नकद प्रवाह, नियोजित पूंजी पर वापसी का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई
बिक्रियों की लागत	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	70	67
बिक्री कीमत	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	70	69
लाभ/हानि	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(94)	81	171
आरओआई	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(57)	73	117
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(68)	98	158

81. प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग के लाभों, नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर वापसी में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

IV. रोजगार और वेतन

82. रोजगार, वेतन और उत्पादकता से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई
रोजगार	नहीं	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	98	84
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	98	98
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	120	118

83. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के रोजगार स्तरों में जांच की अवधि में गिरावट आई है। जांच की अवधि में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है और वेतन ने गिरावट दर्शाई है।

V. माल सूची

84. संबद्ध वस्तुओं की माल सूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई
प्रारंभिक स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
अंतिम स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
औसत स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	मी.ट.	100	85	70	64

85. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग माल सूची में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

iv. निवल बिक्री कीमत का प्रभाव

86. निवल बिक्री कीमत की पैक और थोक, दोनों रूपों में घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत के साथ तुलना की गई है और यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के एनआईपी की तुलना में थोक और पैक दोनों रूपों में निवल बिक्री वसूली उच्च है और वे अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं।

सूची	एनआईपी	एनएसआर
पैकड	***	***
थोक	***	***

VII. वृद्धि

87. प्राधिकारी ने नोट किया है कि जांच की अवधि के दौरान प्लास्टिसाइजर के रूप में कुल संयंत्र क्षमता को ध्यान में रखते हुए उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग और मांग में बाजार हिस्से के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक है और यह भी नोट किया गया है कि प्लास्टिक और पीवीसी दोनों उत्पादों के लिए विस्तृत होते हुए बाजार के कारण उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। लाभ, आरओआई और नकद लाभ से संबंध में वृद्धि सकारात्मक थी। समग्र रूप में, घरेलू उद्योग की वृद्धि क्षति अवधि में सकारात्मक रही है।

VIII. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

88. प्राधिकारी ने नोट किया है कि उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग, लाभ और आरओआई के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और वृद्धि को देखते हुए नया निवेश करने की उनकी क्षमता दुर्बल हुई प्रतीत नहीं होती है।

IX. पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

89. यह नोट किया गया है कि देश में संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं और यह कि पाटन मार्जिन उल्लेखनीय है।

X. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

90. संबद्ध देशों से आयात कीमतों की जांच, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारक, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से निम्न है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी अधिक है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आयातों के पहुंच मूल्य संभवतः घरेलू कीमतों को संचालित करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं।

XI. क्षति पर निष्कर्ष

91. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कुल रूप में संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने संभवतः उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि इसने कीमत मानदंडों में सुधार दर्शाया है।

ठ. क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

92. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत को निर्धारित किया है। विचाराधीन एनआईपी को जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। एनआईपी को निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यूटिलिटियों के साथ भी समान उपचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग के बारे में विचार किया गया है। पीओआई में उत्पादन के सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए उसे परिकलित किया गया है और प्रति यूनिट निर्धारित कीमत पर पहुंचने के लिए समान उत्पाद पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत में कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को प्रभावित नहीं किया गया हो। विचाराधीन उत्पादों के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति सहित औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित वापसी (पूर्व कर @ 22%) को एनआईपी प्राप्त करने के लिए पूर्व-कर लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी, जैसाकि अनुबंध-III में निर्धारित किया गया है और प्राधिकारी द्वारा अनुसरित किया गया है। क्षति मार्जिन को निर्धारित करने के लिए इस प्रकार निर्धारित क्षतिरहित कीमत की संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमतों के साथ निम्नानुसार तुलना की गई है:

क्र.सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	पहंच कीमत	एनआई पी	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %	रेंज
1	कोरिया जन गण.	मै. एकयुंग पैट्रोकेमिकल कं. लि.,	(क) मै. कान्को मार्केटिंग इंक (ख) मै. हुमाडे कॉरपोरेशन (ग) मै. उवेस्को कॉरपोरेशन (घ) मै. कैमटाउन कं. लि. (ड.) मै. हुंडई कॉरपोरेशन	***	***	***	***	5-10
2	कोरिया जन गण.	मै. ओसीआई कं. लि.,	मै. एवरलाइट कोरिया कं. लि.	***	***	***	***	(0)-(5)
3	कोरिया जन गण.	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	25-30
4	चाइनीज ताइपेई	मै. नान या प्लास्टिक कॉरपोरेशन	(क) मै. नान या प्लास्टिक कॉरपोरेशन (ख) मै. जेसी पैट्रोकेम लि. हांगकांग	***	***	***	***	(5)-(10)
5	चाइनीज ताइपेई	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	10-15

ड कारणात्मक संबंध और अन्य कारण

93. घरेलू उद्योग की कीमतों पर, इस की कीमत से कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रभावों के रूप में, महत्वपूर्ण क्षति की मात्रा और पाटित आयातों के कीमत प्रभाव की उपस्थिति की जांच करने पर पाटनरोधी पर भारतीय नियमों और करार के तहत सूचीबद्ध अन्य सांकेतिक मानदंडों की यह देखने के लिए जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त, कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति में अंशदान कर सकता है। तदनुसार, निम्नलिखित मानदंडों की जांच की गई है:

i. तीसरे देशों से आयात

94. प्राधिकारी ने अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात संबंधी आंकड़ों की जांच की है। यह नोट किया गया है कि तीसरे देशों से आयात नगण्य हैं और घरेलू उद्योग को दावित क्षति का कारण नहीं बन सकते।

ii. मांग में संकुचन

95. क्षति अवधि से संबंधित उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। मांग में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं बन सकती।

iii. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

96. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए, खपत के पैटर्न में परिवर्तन को घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं समझा जा सकता।

iv. विदेशी और घरेलू उत्पादों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और प्रतिस्पर्धा

97. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति में अंशदान कर सकती हों।

v. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

98. संबंधित उत्पाद के उत्पादन से संबंधित प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को घरेलू क्षति को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता।

vi. निर्यात निष्पादन

99. घरेलू उद्योग के निष्पादन और क्षति की यथा संभव सीमा तक घरेलू निष्पादन के संबंध में जांच की गई है। इसलिए, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित ह्रास घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग मुख्य रूप से घरेलू व्यापार में संलग्न है और अच्छी लाभप्रदता प्राप्त कर रहे हैं।

vii. अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

100. प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और विक्रय किए गए जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन ने आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं किया है क्योंकि उन्होंने पीओआई के दौरान अच्छी लाभप्रदता दर्शाई है। तथापि, पीयूसी के संबंध में प्राप्त जानकारी की जांच करने पर, इसने भी सुधार दर्शाया है।

viii. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

101. प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू बाजार की उत्पादकता ने उत्पादन के रूप में समान प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। उत्पादकता में ह्रास घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

102. कारणात्मक संपर्क स्थापित करने वाले कारक:

103. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में अधिकतर मानदंडों के संबंध में सुधार हुआ है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध नहीं किया जाता है:

- क) घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक है।
- ख) घरेलू उद्योग के निष्पादन में मात्रा और कीमत संबंधी मानदंडों, दोनों में सुधार हुआ है। इस दृष्टि से क्षति, यदि कोई है, तो वह संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण नहीं हो सकती।
- ग) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत संबद्ध देशों से आयातों के पहुँच मूल्य से अधिक है।

ण. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोध

104. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हो गए हैं। उनमें उठाए गए अधिकतर मुद्दे का जांच के दौरान पहले ही उठा दिए गए हैं और उनका समुचित रूप से समाधान भी कर दिया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:

ण.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

105. प्रकटन पश्चात विवरण पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने दिनांक 28 मार्च, 2018 के ई-मेल के उत्तर द्वारा यह सिद्ध करने के लिए संगत दस्तावेज दायर किए कि कनाटोल-800 और कनाटोल-800-एफजी, स्टेबलाइज्ड सॉफ्टनर कनाटोल-800 और स्टेबलाइज्ड सॉफ्टनर कनाटोल-800-एफजी के अलावा अन्य सभी कनाटोल विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं। तथापि, प्राधिकारी ने केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के विचार प्राप्त किए और अपनी सिफारिश की उपेक्षा की और उसकी बजाए यह माना कि "घरेलू उद्योग हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सिद्ध करने अथवा नकारने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पाया कि कनाटोल के रूप में बेचे जा रहे अन्य स्टेबलाइज्ड सॉफ्टनर डीओपी नहीं हैं।"

- ii. भारत सरकार ने केंद्रीय बजट के माध्यम से डाइकटिल फिथालेट शब्दों को प्रतिस्थापित किया है और "डाइकटिल आइसोफिथालेट" तथा "डाइकटिल टेट्राफिथालेट" को संगत विवरण के रूप में तथा 29173920 को संगत एचएस कोड के रूप में विनिर्दिष्ट किया। इस प्रकार, यह सिद्ध है कि जब सभी पक्षकार (सीमा शुल्क प्राधिकारी, आयातक, प्रयोक्ता और घरेलू उत्पादक) 29173400 अथवा 29173920 को उसके किसी भी रूप में डीओपी के लिए वर्गीकरण के रूप में मान रहे थे तो भारत सरकार ने अब विनिर्दिष्ट किया है कि केवल 29173200 का प्रयोग ही सही वर्गीकरण के रूप में किया जाएगा। अतः, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उत्पाद विवरण में तदनुसार संशोधन करें।
- iii. घरेलू उद्योग ने निर्यातक की सत्यापन रिपोर्ट, उनके द्वारा किए गए पत्राचार और उनके द्वारा दायर की गई सूचना के अगोपनीय रूपांतर को प्रकट करने की मांग की है। उन्होंने दिनांक 12 अप्रैल, 2018 तथा 16 अप्रैल, 2018 के ई-मेल द्वारा सूचना को अतिरिक्त रूप से प्रकट करने की मांग की है, परंतु कोई प्रकटन प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार, तथ्यों का वर्तमान अपर्याप्त प्रकटन केवल पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 के विपरीत ही नहीं है बल्कि घरेलू उद्योग को उसके हितों की रक्षा करने के अधिकार को भी रोकता है।
- iv. घरेलू उद्योग ने उन दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की है जिनके आधार पर उसने यह माना है कि कमीशन बिक्री से जुड़ा हुआ है। प्रकटन विवरण में दिया गया विवरण यह सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध तथा सूचना संबंधी दस्तावेजों की उपेक्षा की गई है और कुछ अन्य सूचना, दस्तावेज और अनुरोध घरेलू उद्योग को प्रकट नहीं किए गए हैं, यह मानकर विश्वास किया गया है कि खर्चे बिक्री पर कमीशन की प्रकृति में हैं, जो प्रचालनात्मक खर्चे नहीं हैं।
- v. प्रकटन विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है, अतः निर्यातक वार कीमत कटौती निरर्थक है, जबकि समग्र कीमत कटौती सकारात्मक है। कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन एनआईपी और आयातों के पहुँच मूल्य की तुलना है, समग्र रूप से कम कीमत पर बिक्री वर्तमान मामले में सकारात्मक है, तथापि, प्राधिकारी ने केवल नकारात्मक कम कीमत पर बिक्री के संबंध में विवरण दिया है जो प्रकृति में वस्तुपरक नहीं है।
- vi. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्वयं ही माना है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं का 86 प्रतिशत की सीमा तक कम उपयोग किया है, जबकि वह 96 प्रतिशत तक उसका उपयोग कर सकता था और उसके बावजूद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने माना है कि याचिकाकर्ताओं को उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। 10 प्रतिशत तक उत्पादन क्षमताओं के कम उपयोग का अभिप्राय है कि 18000 तक उत्पादन की हानि हुई जो 15 प्रतिशत मांग तथा वास्तविक डीओपी उत्पादन के 39 प्रतिशत तक बनता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाया कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 8 प्रतिशत तक की गिरावट आई जो 8500 मी. टन तक की बिक्री की हानि दर्शाता है। यह सिद्ध है कि पाटन के अभाव में घरेलू उद्योग अधिक मात्रा में उत्पादन और बिक्री कर सकता था। यह स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- vii. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष तथा पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है। अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में भी गिरावट आई है और आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। तथापि, प्रकटन विवरण में उसके बाद उल्लेख है कि याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में गिरावट आई है क्योंकि संयंत्र का प्रयोग अन्य प्लास्टिसाइजर्स के उत्पादन के लिए किया गया था न कि डीओपी के लिए। उत्पादन क्षमताओं के 10 प्रतिशत तक कम उपयोग का अभिप्राय 18000 तक उत्पादन हानि है जो 15 प्रतिशत मांग तथा वास्तविक डीओपी उत्पादन का 39 प्रतिशत होता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाया कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 8 प्रतिशत तक की गिरावट आई जो 8500 मी. टन तक की बिक्री की हानि बनती है। यह सिद्ध है कि पाटन के अभाव में घरेलू उद्योग काफी अधिक मात्रा में उत्पादन और बिक्री कर सकता था।
- viii. जबकि, पैरा 75, 76 और 78 में यह उल्लिखित है कि घरेलू उद्योग डीओपी का अधिक उत्पादन नहीं कर पाया तथा कंपनी ने अन्य किस्म के प्लास्टिसाइजर्स का उत्पादन करना बेहतर माना, परंतु एनआईपी प्रकटन में यह पाया गया था कि संयंत्र का 10 प्रतिशत से अधिक तक कम उपयोग किया गया और जिसके परिणामस्वरूप डीओपी का कम उत्पादन हुआ। प्राधिकारी ने एनआईपी का निर्धारण गलत किया है और बिना किसी कानूनी अथवा वास्तविक आधार के अथवा अपनी परिपाटियों की उपेक्षा करते हुए एनआईपी कम करने का दृष्टिकोण अपनाया है।

- ix. कोरिया से सभी आयात एफटीए के तहत हैं और उन पर 31 दिसंबर, 2016 तक 1.5 प्रतिशत शुल्क लग रहा था तथा उसके बाद शून्य शुल्क था। इसे आयातकों के उत्तर से तथा केएलजे के संबंधित पक्षकारों द्वारा आयातों, पायल और रिट्जी द्वारा आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए अन्य आयात दस्तावेजों से सत्यापित किया जा सकता है। तथापि, यह माना जाता है कि प्राधिकारी ने आयातों की पहुँच कीमत का परिकलन करते समय कोरिया के लिए 7.5 प्रतिशत सीमा शुल्क माना है। उसे तदनुसार संशोधित किया जाए।
- x. अनुरोध है कि आयातित उत्पाद की घरेलू उत्पाद से तुलना करते समय पैकिंग लागत (भारी, पैकड और फ्लेक्सी बैग) का समुचित समायोजन किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने केवल दो रूपों पर विचार किया है जिनमें सामग्री का परिवहन अर्थात् पैकड और बल्क का परिवहन किया गया है और फ्लेक्सी बैगों पर विचार नहीं किया है।
- xi. विभिन्न स्थानों पर प्रकटन विवरण में इस आधार पर घरेलू उद्योग को क्षति का अभाव उल्लिखित किया गया है कि निर्धारित एनएसआर एनआईपी से अधिक है। प्रकटन विवरण में यह तर्क निर्दिष्ट प्राधिकारी के विगत जांच परिणामों और सेसटेट के निर्णय के विपरीत है। हम ऑल इंडिया ग्लास मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन बनाम भारत संघ के मामले में सेसटेट के निर्णय का संदर्भ देते हैं और उस पर विश्वास करते हैं जिसमें सेसटेट ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को कीमत प्रभाव निर्धारित करने के लिए एनआईपी की तुलना एनएसआर से करने के लिए अधिदेश देने हेतु कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
- xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों के मद्देनजर तथा घरेलू उद्योग द्वारा पर्याप्त सामग्री प्रदान करने के बावजूद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले सीआईपीईटी से विचार मांगे। वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में स्पष्ट तथ्य में सीआईपीईटी के मानने के बावजूद निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पत्र को पहले प्रकटन विवरण में लाए, उसके बाद उसकी उपेक्षा की और प्रकटन विवरण में तकनीकी रूप से गलत विवरण दिए। यद्यपि यह माना जा सकता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद से संबंधित तकनीकी मामलों के संबंध में एक गैर-तकनीकी निकाय है, तथापि, सीआईपीईटी से मत मांगने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे और वह भी जबकि हमने यह सिद्ध करने के लिए कि डीओपी क्या है और डीओपी क्या नहीं है, महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदान किए हैं। घरेलू उद्योग ने रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीटी) से भी मत मांगे हैं और यह देखा जा सकता है कि आईसीटी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सूची में अन्य कोई फिथालेट उत्पाद नहीं है जो अंतिम उत्पादों में समान विशेषताएं दे सके।
- xiii. एमसीए विवरणी दायर करने में इलैक्ट्रॉनिक विवरणी दायर करने में गलती से त्रुटि हुई है। यह पूर्णतः कम्प्यूटरकृत परिवेश में सूचना भरने में समझ, जानकारी और विशेषज्ञता के अभाव के कारण है। इसके अतिरिक्त, जहां तक वर्तमान जांच का संबंध है, कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं निकलता है। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को स्वीकार किया और माना है कि "गलती से त्रुटि का यह दावा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह शुद्ध न की गई गलती नियामक प्राधिकारी के समझ में न आने योग्य होने से पूर्व सूचना की सांविधिक फाइलिंग है।" यह इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइलिंग विवरण में गलती से और अपरिणामी त्रुटि के लिए अत्यधिक दंड है और इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि इसमें संशोधन की कोई संभावना नहीं है।
- xiv. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा गोपनीयता के अत्यधिक एवं भ्रामक दावों को स्वीकार किया है जिससे याचिकाकर्ता के लिए भारी पूर्वाग्रह हुआ है।
- xv. प्राधिकारी ने इस स्पष्टीकरण के बावजूद कि वास्तविक आयात केवल 420 मी. टन था, याचिकाकर्ता के संबंधित पक्षकार द्वारा 945 मी. टन के रूप में डीओपी के आयात पर विचार किया है।

ण.2 निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

106. निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में आयातकों/वास्तविक प्रयोक्ताओं के कुछ ही नाम उल्लिखित थे। परिणामस्वरूप कई आयातक और प्रयोक्ता जांच से अवगत नहीं थे और उन्होंने प्राधिकारी को कोई सूचना दायर नहीं की। तथापि, जैसे उन्हें इन जांचों के संबंध में मालूम हुआ, उन्होंने शीघ्र ही एक सार्वजनिक सुनवाई के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया। प्राधिकारी ने आयातकों/प्रयोक्ताओं को एक पृथक मौखिक सुनवाई का अवसर दिया जिनके बाद लिखित अनुरोध किए गए थे। उसके बाद, निम्नलिखित पक्षकारों ने आयातक प्रभावली के उत्तर दायर किए:

- i. मैसर्स स्वास्तिक पॉलीविनिलस प्रा. लि.
- ii. मैसर्स सोनार्ग प्लास्टिक्स प्रा. लि.
- iii. मैसर्स कक्लपना इंडस्ट्रीज
- iv. मैसर्स बिहानी मैनुफैक्चरिंग कं. प्रा. लि.
- v. मैसर्स शंकला इंडस्ट्रीज
- vi. मैसर्स बिहानी गुप

आयातकों के नामों पर कृपया विचार किया जाए और प्रकटन विवरण के पैरा 4 में जांच परिणाम को तदनुसार संशोधित किया जाए।

- ii. स्टेबलाइज्ड सॉफ्टनर और कानाटोल 800 कुछ नहीं है बल्कि डीओपी हैं जो विचाराधीन उत्पाद है। शुद्धता के आधार पर किए जाने वाले अंतर की मांग सही नहीं है और यह केवल प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए की गई है। यह मानना कठिन है कि समान उत्पाद कानाटोल 800 भिन्न-भिन्न यूनिटों से भिन्न-भिन्न शीर्षों और भिन्न-भिन्न नामों के तहत मंजूर किया जा रहा है। अतः हम मानते हैं कि सही सूचना अभी भी प्राधिकारी को नहीं दी गई है और डीओपी की कुछ मंजूरीयां प्राधिकारी से छिपाई गई हैं ताकि क्षति का दावा किया जा सके जो कि अन्यथा नहीं है।
- iii. दिए गए तर्क याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सूचना की विश्वसनीयता के संबंध में थे। घरेलू उद्योग प्राधिकारी के समक्ष गलत छाप तैयार करने के पूरे उद्देश्य से भारत में प्रमुख उत्पादक के ब्याँरे देने में विफल रहा। इस पहलू को प्रकटन विवरण में नहीं लिया गया है। अनुरोध है कि जिस पक्षकार ने जांच की शुरुआत के चरण में प्राधिकारी से सूचना जानबूझकर छिपाई है, उसे उसकी अपनी गलती का कोई लाभ लेने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- iv. जहां तक अंतिम प्रयोग से संबंधित मुद्दों का संबंध है, अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता उद्योग पर हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। हम अपना अनुरोध दोहराते हैं कि जांच जारी रखना सार्वजनिक हित में नहीं है। भारत में लगभग 1500-2000 कंपाउंडिंग यूनिट हैं जो संबद्ध सामानों का प्रयोग कर रहे हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से कंपाउंडिंग उद्योग तथा अन्य निचले स्तर के उद्योगों, यथा फुटवियर उद्योग एवं चिकित्सा अनुप्रयोगों पर हानिकारक परिणाम होंगे। समाज के कमजोर वर्गों द्वारा प्रयुक्त फुटवियर में काफी मात्रा में डीओपी हैं जो कुछ मामलों में लगभग 40 प्रतिशत तक है जिसके परिणामस्वरूप करों और शुल्कों के कारण कीमतों में अत्यधिक वृद्धि भी होगी। इस कीमत वृद्धि को खपाना विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए कठिन होगा। यही स्थिति चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त ब्लड बैगों के मामले में उत्पन्न होती है।
- v. डीओपी के अलावा, याचिकाकर्ता कंपाउंडों के विनिर्माण में भी लगा हुआ है। डीओपी पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आयातकों/प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि याचिकाकर्ता बहुत कम लागत पर कंपाउंड का विनिर्माण करने की स्थिति में होगा और इससे प्रयोक्ता उद्योग पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अनुरोध है कि इन गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए, जो शुल्क लगाए जाने की स्थिति में उत्पन्न हो सकते हैं, आयातक प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे याचिकाकर्ता और प्रयोक्ताओं के हितों में संतुलन रखें क्योंकि दोनों भारतीय उद्योग हैं और समान व्यवहार के हकदार हैं। यह सिद्ध होगा कि जब याचिकाकर्ता नियोजित पूंजी पर अच्छा लाभ एवं आय ले रहा है तो आयातक बहुत कम मार्जिन पर प्रचालन कर रहे हैं और कच्ची सामग्री की कीमतों में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं।
- vi. आयातों में वृद्धि लागू प्रशुल्कों और शुल्कों में परिवर्तन का परिणाम है और वह पाटन का परिणाम नहीं है। पाटनरोधी प्रावधान पाटित आयातों के कारण हो रही क्षति का हल निकालने के लिए ही लगाए जा सकते हैं। अतः आयातों में वृद्धि पाटन के परिणामस्वरूप क्षति का संकेतक नहीं है। इसके अतिरिक्त, 8500 मी. टन के आयात शुल्क मुक्त आयात हैं और संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा के सही आंकड़े निकालने के लिए उसकी उपेक्षा किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत किए गए आयातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता।
- vii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों का परिणामी प्रभाव क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, निवेश पर आय, नकद प्रवाह आदि से सिद्ध नहीं है। इस संदर्भ में यह अनुरोध है कि हम प्राधिकारी के विचार से सहमत हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता उपयोग में अन्य उत्पादों के लिए क्षमताओं को कहीं और ले जाने (प्रतिस्थापन) तथा विस्तार के कारण ही गिरावट आई है। साथ ही, यह कि लाभप्रदता, निवेश पर आय, नकद प्रवाह आदि सकारात्मक पूर्ति दर्शाते हैं।

- viii. यह नोट किया जाए कि घरेलू उद्योग की बिक्री क्षति की अवधि में स्थिर रही है। जो अन्य उत्पादक आयातक भी हैं, उनकी बिक्री काफी कम हुई है। यह इस कारण है कि भारी मात्रा में आयात वस्तुतः जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, अन्य उत्पादक द्वारा है, उस पर कोई प्रभाव अथवा मात्रात्मक प्रभाव नहीं है।
- ix. यह अनुरोध है कि भारी पैकिंग और बैगों में विचाराधीन उत्पाद के लिए अलग-अलग तुलना की जाए। यद्यपि, संबद्ध आयातों से कीमत कटौती है, तथापि, घरेलू उद्योग लाभप्रद बिक्री करने में सक्षम रहा है और पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में काफी सुधार हासिल करने में भी सक्षम रहा है।
- x. जहां तक कीमत न्यूनीकरण के मुद्दे का संबंध है, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि बिक्री लागत बिक्री कीमत से अधिक गिरी है जिसके परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में लाभ में वृद्धि हुई है। अतः कीमत न्यूनीकरण का कोई प्रश्न नहीं उठता।
- xi. आयातों का पहुँच मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा निर्माण लागत और भारत में बिक्री में क्षति की अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है। पहुँच मूल्य में सबसे अधिक गिरावट आई है जो आधार वर्ष में 100 सूचकांक से गिरकर जांच की अवधि में 60 हो गई। यह आधार वर्ष की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट है। इसकी तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत 31 प्रतिशत तक कम हुई है, जबकि सामानों की निर्माण लागत और बिक्री लागत 33 प्रतिशत तक कम हुई है। अतः लागतों के गिरने की स्थिति में घरेलू उद्योग उस कीमत को वसूल करने में सक्षम रहा है, जिससे उसके लाभ मार्जिन में सुधार आया है। चूंकि, बिक्री कीमत, उत्पादन लागत से कम गिरी है, अतः यह सिद्ध है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग से पूर्व कोई न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं हुआ है। विशेष रूप से, चूंकि घरेलू उद्योग का लाभ जांच की अवधि के दौरान उनके उच्चतम स्तर पर रहा है, जो पाटित आयातों के परिणामस्वरूप क्षति के किसी दावे को समाप्त करता है।
- xii. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि अन्य उत्पादक आयात करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि डीओपी का उत्पादन भारत में अर्थक्षम नहीं है, यह वैध विवरण नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता जांच की अवधि के दौरान लाभप्रद कीमतों पर डीओपी का विनिर्माण एवं बिक्री खुद ही कर रहा है। वस्तुतः उनके पूर्ण एवं प्रति यूनिट लाभ, दोनों में जांच की अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है, प्रति मीटर लाभ लगभग दोगुना हुआ है अर्थात् पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उसमें 1.7 गुना वृद्धि हुई है। नकद लाभ तथा व्याज एवं कर पूर्व लाभ 2013-14 के आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 1½ गुना बढ़ा है और पिछले वर्ष अर्थात् 2015-16 से तुलना करने पर और भी अधिक बढ़ा है। नियोजित पूंजी पर आय पहले ही 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की रेंज में है। फिर भी जांच की अवधि के दौरान क्षमता का विस्तार हुआ है। यह अनुरोध है कि यदि याचिकाकर्ता पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में अपना लाभ दोगुना करने में सक्षम हैं तो यह अकल्पनीय है कि अन्य उत्पादकों को आयात करने के पक्ष में अपने उत्पादन क्रियाकलाप क्यों छोड़ने पड़े थे।
- xiii. यह भी इस तथ्य के मद्देनजर और अधिक अतार्किक है कि अन्य उत्पादकों ने क्षति की अवधि के दौरान अपनी क्षमता का विस्तार किया है। उपर्युक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि जब केएलजे लगातार अपनी उच्च कीमतें बनाए हुए हैं तो अन्य उत्पादकों ने आयात किया और याचिकाकर्ता की कीमत के अनुरूप प्रयोक्ता को संबद्ध सामानों की बिक्री है। परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को जांच की अवधि के दौरान कोई हानि नहीं हुई जिसने अपने घरेलू उत्पादन पर भारी लाभ अर्जित किया, जबकि अन्य विनिर्माताओं ने भारतीय बाजार में डीओपी की पुनः बिक्री से भारी लाभ अर्जित किए।
- xiv. जैसा कि लाभ के मामले में नियोजित पूंजी पर आय में 2015-16 और जांच की अवधि में काफी सुधार आया है, जब आयात अपनी ऊंचाई पर थे। वस्तुतः 2014-15 में नकारात्मक आय की स्थिति से घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर आय हासिल की जो कि उस समय आधार वर्ष में आय से भी अधिक है, जब कोई पाटन नहीं है। आयात मात्रा और आयात कीमतों तथा घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। किसी भी दशा में, घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर उपयुक्त आय ले रहा है, जो 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच है, जो इस तथ्य का संकेतक है कि वह किसी भी लागू उपाय के बिना आयातों से लाभप्रद रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम है।
- xv. यह नोट किया जाए कि देश में उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग ने संयंत्र एवं मशीनरी में काफी निवेश किए हैं। इसके अतिरिक्त, पाटित आयातों के बजाए संयंत्र एवं मशीनरी में बढ़े हुए निवेशों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की संभावना नकारी जाती है। यह देखते हुए कि अन्य उत्पादकों यथा मैसर्स रचना प्लास्टिसाइजर, दहेज (38,400 मी. टन), मैसर्स आरती इंडस्ट्रीज लि., दहेज (12,000 मी. टन) और मेघारिका इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा पर्याप्त विस्तार किया जा

रहा है। साथ ही, प्राधिकारी ने यह सही नोट किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और बिक्री के मद्देनजर वे नए निवेश करने की स्थिति में हो सकते हैं, जैसा कि उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि अन्य उत्पादक पर्याप्त विस्तार कर रहे हैं।

- xvi. यह अनुरोध है कि इस तथ्य के मद्देनजर कि प्राधिकारी ने पाया है कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की तुलना में वैकल्पिक उत्पाद बनाना बेहतर समझा है, पाटन एवं क्षति के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है और इसीलिए गिरावट पाटित आयातों के कारण नहीं है।
- xvii. यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग भारी लाभ प्राप्त करने के लिए नए उत्पाद/किस्म/ प्रकार/प्रतिस्थापनों में जानबूझकर गया है। इस परिवर्तन की आवश्यकता नहीं था और यह अनौचित्यपूर्ण था क्योंकि डीओपी उत्पादन की लाभप्रदता क्षति की अवधि में लगभग दोगुनी रही है। यह डीओपी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में किया जाना चाहिए था। यह विचार करना भी महत्वपूर्ण है कि जांच की अवधि के दौरान बिक्री कीमत एनआईपी से अधिक है, अतः याचिकाकर्ता नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की अधिकता में पर्याप्त लाभ एवं आय अर्जित करने में सक्षम हैं। यह स्वयं ही घरेलू उद्योग को क्षति का पूर्ण अभाव दर्शाता है।
- xviii. डीओपी के लिए कोई समर्पित संयंत्र क्षमता नहीं है और चूंकि डीओपी सहित सभी फिथालेट्स के उत्पादन के लिए वही तरीके अपनाए जा रहे हैं, अतः डीओपी के लिए संयंत्र का उपयोग न करने के निमित्त मात्रात्मक क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा सिद्ध नहीं किया जाता है।
- xix. डीओपी के विनिर्माण के लिए प्राथमिक कच्ची सामग्री 2-एथिल हेक्सानॉल और फिथालिक एंहाइड्राइड है और इन दोनों उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। अतः यदि संबद्ध सामानों पर कोई और पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो इससे संबद्ध सामानों के अंतिम प्रयोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाईयां होंगी तथा प्रपाती प्रभाव पड़ेगा। इससे अंतिम प्रयोक्ता उद्योग द्वारा प्रयुक्त उत्पादों पर तीन पाटनरोधी शुल्क लगेंगे। परिणामी प्रभाव उपभोक्ता पर होगा और वह सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। संबद्ध सामानों के प्राथमिक अंतिम प्रयोक्ता केवल उद्योग, अपहोस्टरी विनिर्माण उद्योग, फुटवियर उद्योग और पीवीसी तथा प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन में लगे लघु विनिर्माण एकक आदि हैं। तीन पाटनरोधी शुल्कों का प्रभाव उन्हें अपनी यूनिटें बंद करने पर मजबूर कर देगा जिससे पूंजी की हानि होगी तथा भारी बेरोजगार होगा क्योंकि तीन पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव से कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि से क्रेता अपने उत्पादों का घरेलू लघु विनिर्माताओं से खरीद करने के बजाए आयात का सहारा ले सकते हैं। डीओपी में प्रयोक्ता उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत के निमित्त लगभग 10-40 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, यह मेक इन इंडिया को गति देने की भारत सरकार की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध भी होगा।
- xx. घरेलू उद्योग ने सीमा प्रशुल्क शीर्ष 29173920 के तहत कानाटोल 800 आदि ब्रांड नामों के तहत बेचे जा रहे डीओपी के आधार पर याचिका प्रस्तुत की है। एनआईपी के संबंध में यह सूचना ऐसे उत्पादों के लिए ही प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए थी और प्राधिकारी द्वारा जांच तदनुसार की जानी चाहिए थी। तथापि, उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर और प्राधिकारी द्वारा जांच के आधार पर यह स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि घरेलू उद्योग के अन्य ब्रांड नामों में डीओपी का उत्पादन एवं बिक्री अर्थात् कानाटोल 900, कानाटोल 400 (एन) आदि/सीमा प्रशुल्क शीर्ष 29173400 को इस याचिका में शामिल नहीं किया गया है।
- xxi. विचाराधीन उत्पाद में अन्य स्टेबलाइज्ड सॉफ्टनरों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए जो कि केएलजे के अध्यक्ष, सीबीईसी को लिखे 17.05.2017 के पत्र से बहुत ज्यादा सिद्ध है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि डीओपी एक सामान्य नाम है और इसमें (क) डी-ऑक्टाइल ऑर्थो फिथालेट, (ख) डी-ऑक्टाइल मेटा फिथालेट, (ग) डी-ऑक्टाइल टेरे फिथालेट (डीओटीपी) शामिल हैं। इससे आगे केएलजे ग्रुप के कानाटोल 8080 की सूची की प्रति भी है जिसमें यह सूचित किया गया है कि डीओपी और कानाटोल 8080 के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में लगभग कोई अंतर नहीं है। यह नोट किया जाए कि डीओपी एक फिथालेट आधारित प्लास्टिसाइजर है और कानाटोल 8080 एक गैर फिथालेट आधारित प्लास्टिसाइजर (डीओटीपी) है।
- xxii. यह भी अनुरोध है कि याचिकाकर्ता ने आयात आंकड़ों का सार्थक अगोपनीय सारांश तथा आंकड़ों को छांटने का आधार नहीं दिया है। चूंकि, विचाराधीन उत्पाद फिथालेट प्लास्टिसाइजर होना चाहिए, अतः घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित/छांटे गए आयात आंकड़े गलत भी हो सकते हैं और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा क्षति मानदंडों का कोई वस्तुपरक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध किया गया है कि याचिका में निहित सूचना और

वार्षिक रिपोर्टों (सांविधिक फाइलिंग) 2016-17 में निहित सूचना में विरोधाभास हैं। यह याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाता है।

- xxiii. यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। विशेष रूप से, याचिकाकर्ता विभिन्न ब्रांड नामों के तहत घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री के ब्यौरे देने में विफल रहा है। तथापि, जबकि वह प्राधिकारी को अनुबंध डब्ल्यूएस 4 के रूप में लिखित अनुरोधों के भाग के रूप में गोपनीय आधार पर दी गई थी, उसका कोई अगोपनीय रूपांतर नहीं दिया गया।

ण.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

106. यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियां प्रकटन विवरण के संदर्भ में मुख्य रूप से उनके पूर्व के अनुरोधों की पुनरावृत्ति और पुनः प्रस्तुतियां हैं। संगत विरोधी विचारों और अनुरोधों का समाधान इस अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त खंडों में किया गया है जो संगत तथ्यों के मूल्यांकन के आधार पर और प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले न्यायाधिकार तथा संगत नियमों के मद्देनजर भी स्वतः स्पष्ट है। फिर भी, पक्षकारों द्वारा उठाई गई प्रकटन विवरण संबंधी कुछ विशिष्ट टिप्पणियों का समाधान निम्नलिखित रूप में किया जाता है:

- जहां तक तथ्यों के और अधिक प्रकट करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले से संबंधित सभी संगत सूचना प्रकट की गई है और संगत स्थानों पर समुचित रूप से हल की गई है। सीआईपीईटी के पत्र के मुद्दे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में इसे शब्दशः पुनः प्रस्तुत किया है और उसकी प्रति सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध भी कराई है जो सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध है। यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अपने जांच परिणाम निकालने के लिए विस्तार एवं विचार किया गया है और जांच की गई है।
- जहां तक डीओपी के वर्गीकरण का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि यह मुद्दा उत्पाद के वर्गीकरण और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार संगत पैरा में हल कर दिया गया है। तथापि, एचएस कोड में उत्पाद वर्गीकरण में किसी परिवर्तन को समुचित प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
- सीमा शुल्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उस पर प्रकटन विवरण के समय 7.5 प्रतिशत की दर पर विचार किया गया है, जैसा कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान दावा किया था। तथापि, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से प्राप्त टिप्पणियों के अनुरूप उसमें प्रकटन विवरण के बाद संशोधन किया है और संबद्ध सामानों के लिए सीमा शुल्क दर पर संगत सीमा प्रशुल्क अधिसूचना के आधार पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त, भारत-कोरिया सीईपीए के मद्देनजर कोरिया गणराज्य के संबंध में सीमा शुल्क अप्रैल, 2016 – दिसंबर, 2016 के लिए 1.56 प्रतिशत और जनवरी, 2017 – मार्च, 2017 के लिए 0 प्रतिशत माना गया है। तदनुसार, पहुँच मूल्य निकाला गया है और संगत पैराओं में संगत स्थानों पर संशोधन किया गया है।
- समान स्तर पर कीमतों की तुलना के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों के लिए पहुँच मूल्य की तुलना समान स्तर पर घरेलू उद्योग की एनआईपी के साथ की गई है जिसमें बल्क, पैकड तथा फ्लैक्सी बेगों की पैकिंग की लागत कारक है।
- जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता ने डीओपी के उत्पादन और बिक्री के संबंध में सूचना छिपाई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सूचना तथा याचिकाकर्ताओं की सत्यापित सूचना के आधार पर इस जांच में कार्यवाही की है।
- जहां तक जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के क्षमता विस्तार का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य उत्पादकों की भी संबद्ध सामानों के बढ़ते हुए बाजारों में संबद्ध सामानों की विस्तार योजना थी। यद्यपि, अन्य बड़े उत्पादक घरेलू उत्पादक नहीं हैं, क्योंकि वे स्वयं आयातक हैं, परंतु यह क्षमता विस्तार भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादक का सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है।
- विचाराधीन उत्पाद के क्षमता उपयोग के संबंध में, घरेलू उद्योग के दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि में याचिकाकर्ता ने अपनी क्षमता बढ़ाई है और जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का उपयोग कम हुआ है। तथापि, 2014-15 से क्षमता उपयोग की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए यह सिद्ध है कि संयंत्र क्षमता उपयोग में पूरी शेष अवधि में सुधार हुआ है। इस प्रकार, यह समझा जाता है कि क्षमता उपयोग में गिरावट मुख्य रूप से क्षमता

विस्तार के कारण है और साथ ही यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि, समग्र संयंत्र उत्पादन में सुधार हुआ है, तथापि, डीओपी के उत्पादन में गिरावट आई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग का तर्क तथ्यों के अनुरूप नहीं है बल्कि यह याचिकाकर्ता का ध्यान विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन से गैर-विचाराधीन उत्पाद में जाना दर्शाता है।

- viii. इस अनुरोध के संबंध में कि कीमत कटौती का निर्धारण आयातों के पहुँच मूल्य के लिए केवल लेन-देन पर विचार करके किया जाना चाहिए जो कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह डीजीएडी की स्थापित परिपाटी है कि कीमत कटौती के कार्य को जांच की अवधि के दौरान पूरे आयातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और यही परिपाटी कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए भी अपनाई जाती है।
- ix. एनआईपी से संबंधित दावों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुरूप निकाली गई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि लाभ के प्रतिशत के रूप में कमीशन के रूप में निदेशक को दी गई राशि पर एनआईपी निकालने में विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह लाभ में सिद्ध की जाती है जो कि प्रचालनात्मक व्यय नहीं है।
- x. याचिकाकर्ता के संबंधित पक्षकार द्वारा आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता से संबंधित कंपनियों द्वारा डीओपी के आयात पर प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध डीजीसीआईएंडएस की सूचना के आधार पर विचार किया गया।
- xi. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के दावे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के तहत गोपनीयता के दावे के अध्यक्षीन संगत सूचना प्रकट की है। तथापि, अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराए जाते हैं। तथापि, आवेदक विशिष्ट गोपनीय सूचना उन्हें दी गई है।

ण.4. निष्कर्ष और सिफारिशें

107. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उस पर उठाए गए मुद्दों की जांच करने के पश्चात् और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि:
 - (1) विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों सामान्यमूल्य से कम पर भारत को निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है।
 - (2) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण आर्थिक क्षति नहीं हुई है।
 - (3) संबद्ध देशों से आयातों घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं।
 - (4) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना उपयुक्त नहीं समझते हैं और एतद्वारा पाटन-रोधी नियमावली के नियम 11 (2) के साथ पठित नियम 14 (ख), (ग) और नियम 17 (1) (3) के अनुसार वर्तमान जांच को समाप्त करते हैं।

ण.5 आगे की प्रक्रिया

108. इस जांच परिणाम से उत्पन्न मुद्दों के लिये केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध एक अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

मुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th April, 2018

Final Findings**(Case No. OI/03/2017)**

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of Diocetyl Phthalate, originating in or exported from Korea RP and Chinese Taipei.

No. 6/2/2017–DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof:

2. Whereas M/s KLJ Plasticizers Limited, (hereinafter also referred to as the petitioners or the applicants or domestic industry) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the Rules, for initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of “Diocetyl Phthalate” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from Korea RP and Chinese Taipei (hereinafter also referred to as the Subject Countries), alleging dumping and consequent injury and requested for levy of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the Subject Countries.
3. And whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence, submitted by the applicant issued a public notice vide Notification No. 6/2/2017 -DGAD dated 01st June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the sub Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

A. Procedure

4. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

- (i) The Authority notified the Embassies of the Subject Countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 *supra*.
- (ii) The Authority issued a public notice dated 01st June, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.
- (iii) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the Subject Countries in India, known producers/exporters from the subject Countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
- (iv) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject Countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules *supra*.
- (v) The Embassies of the subject Countries in India *were* also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- (vi) The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. M/s Chemcross Inc. Asia
 - b. M/s Humade Corporation
 - c. M/s Woori P & C Corporation
 - d. M/s UPC Technology Corporation
 - e. M/s Advance Tekno chem
 - f. M/s Dah Sheng Plasticizer Co. Ltd
 - g. M/s LG Chem Co. Ltd

- (vii) The following producers/exporters from the Subject Countries filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:
- a. M/s OCI Company Ltd. Korea RP
 - b. M/s Nan Ya Plastics Corporation, Chinese Taipei
 - c. M/s Everlite Korea Co Ltd, Korea RP
 - d. M/s JC Petrochem Limited, HongKong
 - e. M/s Aekyung Petrochemical Co. Ltd, Korea RP
 - f. M/s Canko Marketing Inc, Korea RP
 - g. M/s Chemtown Co. Ltd, Korea RP
 - h. M/s Humade Corporation, Korea RP
 - i. M/s Hyundai Corporation, Korea RP
 - j. M/s Ubesco Corporation, Korea RP
 - k. M/s Woori P&C Corporation, Korea RP
- (viii) The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- a. M/s Alpha Polymers
 - b. M/s Anukampa Polymers & Technologies Pvt. Ltd.
 - c. M/s Gloster Cables Limited
 - d. M/s Prime Polymers
 - e. M/s S. Gopal Kamath (Cochin)
 - f. M/s Coir Tuft International Pvt. Ltd.
 - g. M/s Kerafibertex Int. Pvt. Ltd
 - h. M/s The Alleppey Company
 - i. M/s Kerala Baars (P) Ltd
 - j. M/s Tube Products
 - k. M/s Gee Tee (India) Ahmedabad
 - l. M/s Nishan Marketing
 - m. M/s Sigma Organics and Chemicals Pvt Ltd
 - n. M/s Laser Cables Pvt Ltd
 - o. M/s Plastic Pack
 - p. M/s Jain Chemicals (Jaipur)
 - q. M/s Jain Chemicals & Plastic (Delhi)
 - r. M/s Leo Vinyls Kapurthala Road
 - s. M/s Jainco Enterprises
 - t. M/s Arvind Plastic Udyog
 - u. M/s Radha Plastic Inds. (Daman)
 - v. M/s Varun Organics Pvt Ltd
 - w. M/s Krishna Enterprises
 - x. M/s A.D. Industries
 - y. M/s Diamond Pipes & Tubes Pvt Ltd
 - z. M/s BDS Industries
 - aa. M/s Poonam International
 - bb. M/s Royal Cushion Vinyl Products Ltd
 - cc. M/s Vinyl Royal Plasticoats Ltd
- (ix) The following importers filed importer's questionnaire response in the prescribed format:
- a. M/s Sterling Impex
 - b. M/s Shiv Polymers

- c. M/s Kiwi Overseas
 - d. M/s RMG Polyvinyl India Ltd
 - e. M/s Swastik Polyvinyls Pvt Ltd
 - f. M/s Sonarg Plastics Pvt Ltd
 - g. M/s Kkalpana Industries
 - h. M/s Blhani Manufacturing Co. Pvt Ltd
 - i. M/s Shankla Industries
 - j. M/s Bihani Group
- (x) Submissions were also received from following parties as well
- i. IEEMA
 - ii. All India Plasticizer Consumer Association
 - iii. Taipei Economic and Cultural Center in India
- (xi) Apart from the respondent exporters and importers mentioned above, submissions have been received on behalf of the following parties during the course of this investigation. However, no importer questionnaire have been filed by the following parties.
- i. M/s Beetapoly Coats Pvt Ltd.
 - ii. M/s Yash Enterprise
 - iii. M/s Takkar Industries
 - iv. M/s Yashraj Industries
 - v. M/s Gopal Plastics
 - vi. M/s Havells
 - vii. M/s SAC Polymers
 - viii. M/s BLS Polymers Ltd
 - ix. M/s KEI Industries Limited
 - x. M/s Yash Poly Industries
 - xi. M/s Finolex Cables Limited
 - xii. M/s SAC Polymers Limited
 - xiii. M/s Technovinyl Polymers India Limited
 - xiv. M/s J & K Industries
 - xv. M/s Farcom Cable Systems Pvt. Ltd.
 - xvi. M/s Konnark Polymer Private Limited
 - xvii. M/s Rialto cables Pvt. Ltd.
 - xviii. M/s Dugar Polymers Limited
 - xix. M/s Polynova
 - xx. M/s Welset
 - xxi. M/s Currency Cables Private Limited
 - xxii. M/s Polyester Industries
 - xxiii. All India Plasticizers Consumers Association
 - xxiv. The Plastic Export Promotion Council
 - xxv. All India Laminated Fabric Manufacturers Association
 - xxvi. M/s Plast Impex
 - xxvii. M/s Marvel Vinyls Ltd.
- (xii) Following consumers/users filed letters supporting the claim of domestic industry for imposition of anti-dumping duties, post initiation of the investigation.

SN	Party Name	SN	Party Name
1	Ashish Agro Plast Pvt Ltd	40	Jainco Enterprises
2	Ashish Poly Plast Ltd	41	Krishna Enterprises
3	Ashriwad Polymers	42	Nishan Marketing
4	D.R.G Leather Cloth Pvt Ltd	43	Plasti Pack
5	Dawar Sons Pvt Ltd	44	Pritsons Polymers
6	Dutron Plastics (Bharuch)	45	Rako Mercantile Traders
7	Dutron Plastics Ltd	46	S.Gopal Kamath (Cochin) Pvt Ltd
8	ELES Vinyl Pvt Ltd	47	Varun Organics
9	Eva Synthetic LLP	48	Ac Polycoaters Pvt.Ltd.
10	Frontier Alloys	49	Ac Unicoaters Pvt.Ltd.
11	Gajindra Plastic Industries	50	Alert India
12	J & K Indsutries	51	Alpha Medicare And Devices Pvt.Ltd.
13	Janta Footwear Private Limited	52	Alpha Organics
14	Kamal Polymers	53	Amco India Ltd.
15	Lotus Industries	54	Andhra Petrochemicals Ltd.
16	Lucky Plast Ltd	55	Arvind Plastic Udyog
17	Medicare Industries	56	Bajaj Polymer
18	National Healthcare	57	Bansal Polyplast Pvt.Ltd.
19	National Industries	58	Dhan Laxmi Industries
20	National Products	59	Fleetguard Filters Private Limited
21	Nippon Polymers Pvt Ltd	60	Harion Polymers
22	Opera Polymers	61	Hillson Footwear Pvt.Ltd.
23	Paras Udyog	62	I.G.Petrochemicals Ltd.
24	Parshv Polymers Pvt Ltd	63	Jain Chemicals
25	Patkar Extrusions Pvt Ltd	64	Jayashree Polymers Pvt.Ltd.
26	Polyfines India Ltd	65	Mahalaxmi Plastic Industries
27	Prabhat Industries	66	Major Footwears Pvt. Ltd.
28	Rainbow Enterprises	67	National Traders
29	Rama Vyapar Pvt Ltd	68	Paras Udyog
30	Ridhi Sidhi Polymers	69	Pathfinder Woodplast
31	Sakkthi Polymers	70	Plasti Lami Coats Pvt.Ltd.
32	Shri Shyam Polycoats Pvt Ltd	71	Pragati Enterprises
33	Soft Turf	72	Pvc Converters India Pvt.Ltd.
34	Sree D.R.G Vinyl Industries	73	Rextile Leather Pvt.Ltd.
35	Tekmak Cables India (P) Ltd.	74	Roman Industries LLP
36	Tirupati Plastics	75	Shital Text Pvt.Ltd.
37	Yash Enterprises	76	Standard Flex Pvt.Ltd.
38	Haryana Plastic	77	Thirumalai Chemicals Ltd.
39	Jain Chemical & Plastics	78	Vandana Enterprises Pvt.Ltd.

- (xiii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- (xiv) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- (xv) The Non-injurious Price (NIP) based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- (xvi) Verification of the information provided by the applicant domestic industries, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present final findings.
- (xvii) The Period of Investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is the period from 1st April, 2016 to 31st March, 2017 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the POI.
- (xviii) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 22nd December, 2017 and thereafter on 3rd January, 2018. All the parties who had attended the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were advised to offer their rebuttals.
- (xix) Subsequent to the public hearing, based on the issues raised by the various interested parties, the domestic industry vide e-mail dated 28th of March, 2018 was asked to clarify with evidence regarding the product under consideration mainly, whether all other Kanatol apart from Kanatol-800, and Kanatol 800 FG, stabilized softener Kanatol-800 and stabilized softener Kanatol-800 FG do not constitute the PUC, regarding disclosure of production and sales of other producers and their disclosure of the total turnover as DOP for the period of investigation before the Ministry of Corporate Affairs.
- (xx) The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered in the present final findings.
- (xxi) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final findings.
- (xxii) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- (xxiii) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- (xxiv) In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 12th April, 2018 to the concerned interested parties. Comments were requested by 19th April, 2018. Comments received on the disclosure statement to the extent considered relevant by the Authority are considered in this final finding.
- (xxv) *** In this findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (xxvi) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs 67.95

B. Product Under Consideration and Like Article

5. Based on the information filed by the petitioner, the Authority initiated the Anti-dumping investigation and defined the product under consideration as “Dioctyl Phthalate (DOP)”. It is chemically known as Bis (2-ethylhexyl) phthalate, also abbreviated as DEHP. Dioctyl phthalate is an organic compound with the chemical formula $C_{26}H_{54}O_4$ ($C_{26}H_{54}O_4$) 2 and was classified under Chapter 29 under the Customs Tariff Act, 1975 at 29173920.

B.1 Submissions made by the Domestic industry

6. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:

- (i) The domestic industry is selling the product under consideration under following brand names viz, Kanatol 800, Kanatol 800S, Kanatol 800FG and Stabilized Softener K 800.
- (ii) The domestic industry is not selling its product as “Plasticized Softener”. The domestic industry never said that they are selling the product under consideration under the name of “Plasticized Softener”. The Authority has already verified the data filed by the domestic industry. The domestic industry is not selling its product as “Plasticized Softener”.
- (iii) DOP and Kanatol 8080 are two different products and cannot be used interchangeably. While DOP is Phthalate based Plasticizer, Kanatol 8080 is non phthalate based plasticizer. The raw materials for both the products are different. From the technical sheet of both DOP and Kanatol 8080, it would be seen that both the products have entirely different properties. The applications of both the products are different. Whereas DOP is used for fabricating flexible vinyl products, Kanatol 8080 is used for vinyl gloves, wall covering etc. As regards, DINP, DIOP, DIMT, DOTP (Kanatol 8080) and Kanatol 1056, It would be seen that these products differ not only in properties but also in application.
- (iv) Reference is placed on US findings on DOTP, wherein USITC stated that DOTP and DINP cannot be used interchangeably because they are chemically different products. The two products are different in molecular weight, chemical formula, raw material and toxicity.
- (v) The domestic industry has included the sales and production of Kanatol 800 in its data. Kanatol 800 is nothing but a type of DOP. Further, the petitioner has produced and sold DOP by using different trade/brand names. The petitioner has provided information in the petition with regard to various types or forms of the DOP produced and sold by the petitioner in the market
- (vi) The domestic industry has provided all the data for all the grades of DOP. As regards the question of viable substitute, it is reiterated that there is no viable substitute of the product under consideration produced by the domestic industry. Different brand names of the same product cannot be construed as viable substitutes of the product.
- (vii) As regards, DINP, DBP, TOTM, DIBP and Di (2-Propylheptyl) Phthalate, it would be seen that these products differ not only in properties but also in application. The domestic industry has sold DOP under heading 29173920 from Main Unit Silvassa and sold DOP under heading 29173400 from Unit-III Silvassa in the name Stabilized Softeners K-800. The domestic industry has provided copies of ER-1 to establish the same. Stabilized softener is one of the forms of the product under consideration and the data of the same is included. The product under consideration in the present case is not all Plasticizers but only DOP.
- (viii) Payal Petrochem Pvt. is producing various types of Plasticizers. As regards accuracy of the production figures of Payal Petrochem Pvt, the domestic industry has provided letter which is given by the said company to the legal representative of the domestic industry providing information of their production of DOP.
- (ix) The domestic industry has sought anti-dumping duty only on DOP and not all Phthalate Plasticizers.

B.2 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

7. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:

- (i) Domestic Industry is selling the PUC and other phthalate plasticizers and specialty plasticizers under an ambiguous name of “Plastic Softeners”. Domestic Industry is selling and invoicing two or more products one being PUC and the other being Non-PUC, under the same name, there is a doubt regarding the authenticity of their production and sales details. During the hearing they have accepted that the invoices pertaining to “plastic softeners” have been included in the PUC. There is no explanation on record as to how the Domestic Industry has considered the Non-PUC sold under the name of “Plastic Softeners”
- (ii) There are gross mis-declarations by the Domestic Industry with regard to the issues of substitutability of the PUC. The specialty plasticizer Kanatol 8080 is a perfect substitute of the PUC, it is stated that there is no “technical or chemical” difference between the two except some minor structural differences and

Kanatol- 8080 is in fact a better substitute of PUC. There are at least five more substitutes of the PUC which are DINP, DIOP, DMT, DOTP (Kanatol 8080) and Kanatol 1056. Domestic Industry offers them at cheaper rate claiming that they are better performing inputs than the PUC.

- (iii) Initiation is based on incorrect information. Domestic industry has provided information only in respect of goods sold under the name of DOP and has failed to disclose sales of DOP under the brand name Kanatol 800 which is admittedly DOP. If the sales and production information is correctly reflected, there would be no decline during the POI.
- (iv) Domestic Industry has not disclosed all the grades of DOP in the petition which they are selling and made an incorrect statement "There is no technically and commercially viable substitute for the product under consideration" in the petition. M/s KLJ Plasticizers Limited are manufacturing and selling DOP under various names such as "Plasticized Softener"/ Stabilized Softener" etc., which has not been disclosed anywhere in the petition.
- (v) Various substitutes of DOP are DINP, DBP, TOTM, DIBP and Di (2-Propylheptyl) Phthalate. Petitioner is selling these plasticizers under the trade name -Kanatol 900- DINP, Kanatol 3800- TOTM, Kanatol 8005 (DOP Super), Kanatol 1010 Kanatol 400 (M). Petitioners are selling other Phthalate Plasticizers which are partial substitutes of DOP, is evident from KLJ's own brochures.
- (vi) Domestic industry has limited the data provided to Tariff Heading 2917 3920, while they have been importing and selling DOP under other Tariff Headings also, such as Tariff heading 29173400. Domestic Industry is promoting DOP under the trade name of Plasticized/Stabilized Softener. The petitioner have mislead the Authority by linking the data to the extent under Tariff Head 29173920 while they have been importing and selling DOP under Tariff Head 29173400 also.
- (vii) The production figure of other producers collectively is incorrect and misleading. According to Annual Report of M/s Payal Petrochem Pvt. Ltd. for year 2015-16, the sales of Plasticizers are Rs. 419 Crores, i.e. 60,000 MT. This sales of other producers in the petition is shown as 25,421 MT, which does not even reflect the sales of a single producer.
- (viii) There are similar product to PUC in terms of characteristics, technical properties, uses, users, common plant and commercial substitutability. PUC and the Stabilized Softener are used interchangeably and are like article, both are manufactured by the domestic industry. Stabilized softener may be included in PUC and cannot be kept out of the purview of investigation. Domestic industry may have used multiple HS Code to clear the goods (stabilized softener as DOP). KLJ: Product Kanatol 800: HS Code is 29173400, Payal: Product: PayflexPSO0(O): HS Code is 29173990 and Ritzy: Product: Ritzy 100: HS Code is 29173990. DOP is a kind of Phthalate Plasticizer, hence PUC is not DOP per se but PHTHALATE PLASTICIZERS.
- (ix) The statement of domestic industry is in itself false that Kanatol 8080 is a type of DOP and petitioner has produced and sold DOP under different trade/brand names. No justification has been given on available substitutes of DOP. Reliance is placed on the product data sheet wherein kanatol 8080 as a substitute of DOP, having "almost no difference in physical and chemical properties" has been mentioned.
- (x) Domestic industry has admitted that the other product such as Stabilized Softener although are not identical with the imported product but is having characteristics closely resembling the PUC and is physically and commercially substitutable with PUC. On this basis the Stabilized Softener is required to be included as part of present investigation. Authority should examine the production and sales of DOP of the domestic industry, cleared under different chapter headings/ brand names by reconciling with the Excise records and as per the annual report of the petitioner.
- (xi) If the duties are imposed on DOP, the petitioner would raise the prices of the substitutes which would result in hardship to users. Petitioners are promoting sales of DINP, claiming them to be substitute of DOP. Petitioner has not denied that DINP is a substitute of DOP, only the issue of like article has been raised. Reliance is placed on the email of Indian Producers wherein it has been admitted that DINP is a substitute of DOP.
- (xii) Substitutes of DOP available in the market are Di Isononyl Phthalate (DINP), Dibutyl Phthalate (DBP), Tri octyl Trimellitate (TOTM), Di iso butyl Phthalate (DIBP), Di (2-Propylheptyl) Phthalate. Moreover Petitioner is selling these Plasticizers under the trade names which are Kanatol 900- DINP, Kanatol 3800- TOTM, Kanatol 800S (DOP Super), Kanatol 1010, Kanatol 400 (M). Further, petitioner has admitted in its catalogue, that these are partial substitutes KANATOL-800S, KANATOL-800, KANATOL-900, KANATOL-1001, KANATOL-1010, KANATOL-1210, KANATOL-1212, KANATOL-400(I), KANATOL -400(M), KANATOL- 40 (N), KANATOL-1056, KANATOL-8A, KANATOL-8S,

KANATOL-40S, KANATOL -80S, KANATOL-4M, KANATOL-4S, KANATOL-TM 8-10L, KANATOL-3800, KANATOL-3430E, KANATOL-8080, KANATOL-3400AC

B.3 Examination by the Authority

8. The Authority has noted submissions made by various interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article offered by the domestic industry. With respect to the product under consideration, the Authority notes:
 - (i) The product under consideration in the present case is “Diocetyl Phthalate (DOP)”. It is chemically known as Bis (2-ethylhexyl) phthalate, also abbreviated as DEHP. Diocetyl phthalate is an organic compound with the chemical formula C₈H₄ (C₈H₁₇COO) 2. It is also known as [bis (2-ethylhexyl) benzene- 1, 2-dicarboxylate].
 - (ii) With regard to scope of the product under consideration, the Authority notes that the product under consideration has been considered at the time of initiation notification dated 1st June, 2017, based on the facts available before the Authority, wherein the PUC has been classified under Tariff head at 29173920.
 - (iii) The domestic industry has submitted that the product under consideration does not include DOTP (Kanatol 8080), DIOP, DIMT, Kanatol 1056, DINP (Kanatol 900), TOTM (Kanatol 3800), DBP and DIBP. The domestic industry has sought anti-dumping duty on Diocetyl phthalate (DOP) and has claimed injury with respect to performance of the product under consideration.
 - (iv) The opposing interested parties have raised the issues with regard to various types of stabilised softeners and stated that these all stabilised softeners are DOP and being sold under the brand Kanatol. The opposing interested parties have brought the copy of invoices raised by different domestic producers including the petitioner in order to establish that the domestic industry has not brought the correct information before the Authority with regard to the product under consideration. The other interested parties have stated that the domestic industry has not disclosed information under Tariff Head at 29173400 as the limited information with regard to the tariff head 29173920 has been provided at the time of initiation treating the product as DOP. During the course of investigation, domestic industry has provided evidence that apart from stabilized softener K800, other stabilized softeners being produced and sold by the domestic industry, does not constitute the product under consideration i.e. DOP. In support of their claim they have filed the information with regard to product specification in terms of chemical composition, molecular structure, chemical properties, physical properties, carbon chain, and specific user application.
 - (v) In order to ascertain the facts which have been raised by the opposing parties, the authority has obtained the views of Central Institute of Plastic Engineering and Technology (CIPET), Govt. of India. CIPET in its letter dated 5th April, 2018, has stated that, “Generally phthalates plasticizers are frequently used in PVC Industries for making plasticized/flexible PVC products for various applications. Plasticizers from KLG group (K-800 & K-800FG) are used for specific purposes in PVC Raisin depending upon the characteristic properties to be achieved in the products. When we are looking for the products where the properties like smell less, higher volume, sensitivity, less volatility etc. are considered important then they could be best option as per the information in the brochure of the company. In the KLJ Group catalogue other phthalate products are not having such characteristics and therefore cannot be recommended. However, Phthalates (from any source) with similar property profile as K-800 can be used for such applications after proper quality check of the end product in this regard. From the data given in the brochure it is clear that there is no phthalate products in the list to match such property in the end product.” In comments to the disclosure statement the domestic industry has filed an e-mail reply from Department of Polymer and Surface Engineering, Institute of Chemical Technology (ICT), Mumbai stating that K800 & K800 FG are having exclusive properties viz, less in odour, less volatility, and higher volume resistivity which made them different than the other phthalates as mentioned in KLJ product catalogue. However, it may have different dosage in PVC compounding. Phthalates from any other source with nearly matching properties as K800 and K800FG can be used for similar application after proper quality check of the end users. The clarifications made by CIPET & ICT do not clearly establish that other stabilized softeners are not DOP or dissimilar product as being raised by the interested parties. Even the petitioner were not able to establish with evidence that the other stabilized softeners were used for specific uses/applications and the same cannot be substituted. The Authority also notes that the domestic industry could not adduce sufficient evidence to prove or nullify the issue raised by the other interested parties that the other stabilised softeners being sold as Kanatol do not constitute DOP and cannot be used for similar application.
 - (vi) As regards different HS codes used by the petitioner in order to capture the production and sales of DOP, the domestic industry has stated that they have two units for production and sale for product under consideration- namely main unit and unit 3. The domestic industry claimed that from main unit the

petitioner sells product under consideration with the brand name “Kanatol 800 which is a 100% DOP under HS Code 29173920 and from Unit 3 the petitioner produces DOP and sells it under the brand name “stabilised softener” having purity of DOP as 99.5% under HS Code 29173400 (other esters of orthophthalates). However, the other interested parties has claimed and provided copies of invoices of stabilised softeners of Kanatol that the petitioner has sold under HS code 29173400. In view of the import data filed by the domestic industry and collected under HS Code 29173920, the Authority moved in this investigation with the information under this head only instead of entire information of DOP as claimed by the other interested parties and during the course of investigation petitioner has claimed that production and sale of the PUC has been carried out under HS Code 29173400 also along with other stabilized softeners under the same ITCHS code.

- (vii) In view of the above, the authority confirms that the product under consideration in the present investigation is “Dioctyl Phthalate (DOP)”. It is chemically known as Bis (2-ethylhexyl) phthalate, also abbreviated as DEHP. Dioctyl phthalate is an organic compound with the chemical formula $C_{24}H_{38}O_4$ ($C_{12}H_{17}COO$)₂. It is the most important "phthalate," being the diester of phthalic acid and the branched-chain 2-ethylhexanol. This colourless viscous liquid is soluble in oil, but not in water. It possesses good plasticizing properties. The subject goods is widely used as a plasticizer in manufacturing of articles made of PVC. Plastics may contain 1% to 40% of DOP depending upon requirements. It is also used as a hydraulic fluid and as a dielectric fluid in capacitors. It also finds use as a solvent in glow sticks as it has suitable properties and the low cost. The product is primarily sold on weight basis. The product under consideration is classified under Chapter 29 under the Customs Tariff Act, 1975 at 29173920 and 29173400. The customs classification is indicative and not binding on the scope of the product under consideration and present investigations.

C. Scope of Domestic Industry & Standing

C.1 Submissions made by the Domestic industry

9. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:
- (i) The production of the petitioner in the present investigation constitutes a major proportion of the Indian Production and unless this claim of the domestic industry is rebutted, any argument on production of other Indian producers is baseless and irrelevant
 - (ii) Even if the production of M/s Ritzy Chemicals P. Ltd is included, the petitioning domestic industry still holds major proportion of the Indian production. The production of the petitioner in the present investigation constitutes a major proportion of the Indian producer.
 - (iii) Petitioner has not imported the product under consideration. However, the petitioner is related to the importers of the product under consideration.
 - (iv) The production figures of the other Indian producers have been provided as per the best information available with the domestic industry.
 - (v) Petitioning domestic industry is related to two importers of the subject goods. Petitioning domestic industry should be considered as an eligible domestic producer despite imports by their related company in view of (i) past decisions of the Designated Authority, (ii) production of the company in India being quite significant, (iii) focus of the company being on domestic production (iv) Imports made by related companies constitute 0.73% of total imports, 0.59% of Indian production and 0.51% of demand in the period of investigation.

C.2 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

10. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:
- (i) Names of the other Indian producers are not disclosed. M/s Ritzy Chemicals P. Ltd (plant - Daman & Jammu) a producer of DOP, has not been included in the details of Domestic producer. If M/s Ritzy Chemicals is added the Domestic Industry will fail to establish its standing in the present investigation and same should be terminated.
 - (ii) Petitioners are themselves importers of the subject goods. DOP itself has been imported and sold by the petitioner as adequate raw material for producing DOP is not available within India.
 - (iii) Applicant is related to the importers from subject countries, Rule 2(b) has been referred. Judgments relied upon by the Domestic Industry are no longer good law and the same cannot be even used for any persuasive value.

- (iv) Petition by Domestic industry brings out that applicant is related to importers of PUC. According to Rule 2(b), the domestic producer cannot be considered as domestic industry if *they have self-imported or* are related to importers/exporters. Reliance has been placed on the judgments of Madras High Court and Kolkata High Court by the domestic industry, to claim the relationship of a domestic producer with importers/exporters. Authority holds discretion to consider domestic producer as domestic industry. Authority has been requested to decide upon the issue of domestic industry without being influenced by the decisions quoted by the domestic industry.
- (v) Domestic industry has placed the picture of DOP industry which is dated back “two decades” and hence is not relevant in the present investigation. It is stated that the industry has seen the decline for past 20 years but the phenomena of dumped imports are of recent *origin*. Lastly, the petitioner’s claim that only 5 companies are engaged in the manufacturing of the PUC does not match with the data provided in the petition.
- (vi) It is to be noted that the producers who have closed their production as per domestic industry are not before the authority for imposition of anti-dumping duty but the petitioner who is making high profits and having no injury came before the authority for duty on PUC. Further, domestic industry has not disclosed the name of other Indian producer, M/s Ritzy Chemicals P. Ltd. which has substantial production. If the same is included, the petitioner will fail to establish standing of domestic industry. The claim of the domestic industry that other Indian producers of DOP are making imports against the dumping, as production and sale of DOP is not viable in India, is without legal and factual basis.
- (vii) Closure of the companies in the last two decades has no relevance in the present investigation. The Indian producers have control on the market dynamics, including the price at which both the imported and indigenous DOP is bought and sold. Hence, the Indian producers cannot be considered as small scale industry.
- (viii) The submission made by the domestic industry that there are only 5 producers of DOP is not correct. M/s Ritzy Chemicals Pvt Ltd is a related entity of PCL Oil & Solvents Ltd., engaged in the manufacturing of DOP. By excluding M/s Ritzy from the list of manufacturers, the petitioner has reduced the total production of DOP.
- (ix) All the manufacturers including M/s KLJ, M/s Ritzy and M/s Payal work in tandem, which is evident from their invoices and pricing strategies. Earlier, they were selling DOP as DOP under Chapter Heading 2917 39 20, whereas, lately for the last 3 years, they have started selling DOP under Different names and different chapter Headings, such as 2917 34 00, 2917 39 90. The petition for ADD was filed with a clear intent to conceal and under report the production and sales data of DOP Manufacturers, making it easily omissible. We believe that the sales figure are extremely low, and that a significant quantity of sales have been suppressed from the Authority.

C.3 Examination by the Authority

11. Rule 2(b) provides as under;

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

- 12. The petition was filed by M/s KLJ Plasticizers Ltd. (KLJ) who is a major producer of subject goods in India. The petitioner has not imported the product under consideration. However, the petitioner is related to two importers of the subject goods namely M/s KLJ organic Limited and M/s KLJ Polymers & Chemicals Ltd. *Imports made by related companies constitute 945 MT as per DGCI&S import data*. The imports made by the related companies constitutes insignificant share in relation to total imports of the product under consideration, its production and consumption of the product under consideration in India. In view of the insignificant import by the related parties to the petitioners, the Authority did not find appropriate to treat such imports sufficient to disentitle petitioner from being an eligible domestic industry.
- 13. During the course of investigation, it was stated by the petitioner that there are number of other producers of DOP in India, however, they provided the information with regard to five other Indian producers namely M/s Payal Petrochem Pvt Ltd, M/s PCL Oil & Solvents Ltd., M/s Rachna Plasticizers Pvt. Ltd., M/s N K Polymers & Mfg Company and M/s Lalitha Chem Industries Pvt. Ltd. The other interested parties in their submissions have stated that the domestic industry did not provide the information with regard to the production and sales of other major producers namely M/s Ritzy Chemicals and others, in order to establish injury to the domestic industry. Moreover, the interested parties also did not provide information with evidence regarding production and sales of other domestic producers. The domestic industry subsequent to the oral hearing provided the information of production and sales of M/s Ritzy chemical but M/s Ritzy being one of a major importer of the subject goods could not be considered a constituent of the domestic industry. It is also noted that based on the DGCI&S import statistics, M/s Ritzy Chemicals Pt. Ltd. and its related parties have imported substantial volume of DOP during the POI and at the same time as an interested party, they didn’t file the information with regard to production and sales.

14. As per the Anti-dumping Rules, the Authority is required to examine whether (a) domestic producers expressly supporting the application account for more than twenty five percent of the total production of the like article by the domestic industry; and (b) the application is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. The applicants alone constitute 73% of the total domestic production based on the information provided by them, however, this share may further increase *if other stabilised softeners are treated as the part of the product under consideration*.
15. The authority notes that the AD Investigation was initiated based on the facts available before the authority. However, during the course of investigation, the information which has been brought to the notice of the authority by the other interested parties, have been considered in this AD Investigation. In view of the issues raised by the interested parties regarding production and sales, the authority even tried to obtain the production and sales figure from the administrative Ministry, however, it was stated by the Ministry of Chemical and Fertilizers that such information is not maintained by them since, they monitor only selected large and medium scale units. However, information filed by the interested parties during course of investigation, have been considered for computation of demand. The authority notes that if the production figure of the other domestic producers would have been provided, it would have made change in volume parameters including demand and percentage share.
16. In view of the above and after due examination, the Authority holds that the applicant satisfy the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules. Applicant satisfies the requirement of standing under the Rules. Further, the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

D. Confidentiality

D.1 Submissions made by the Domestic industry

17. With regard to confidentiality, the submissions made by the domestic industry during the course of the investigation are as follows:
 - (i) Domestic industry has claimed confidentiality wherever required and have also provided non confidential summary wherever feasible. Further, the interested party has failed to establish even a single instance where petitioners have claimed confidentiality where information was available publicly and which cannot be permitted by the authority as a matter of need of the present case. The confidentiality claims of the petitioners are consistent with the practice of authority. The domestic industry has provided trends of all injury parameters which is sufficient for the opposing interested parties to argue on merits of the case.
 - (ii) The DGCI&S data is “Third Party business proprietary information” and the domestic industry is not authorized to disclose. Further, it has been consistent practice of the Authority to treat DGCI&S data as confidential.
 - (iii) Further, if the opposing interested party requires DGCI&S data, they can very well take authorization letter from the Authority and purchase the data. The data is available to all on payment basis, subject to authorization by the Authority

D.2 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

18. The submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are as follows:
 - (i) Excessive Confidentiality has been claimed, even the economic parameters are confidential in the petition which has resulted as respondents are not able to fully undertake a meaningful examination of injury parameters of the industry. Neither a good cause for the purpose of claiming confidentiality on certain parameters, nor made available in NCV. Confidentiality has been claimed for capacity and capacity utilization, costing of the industry - Statement B, Format CI, Format CII, Format D, Format E and certain other key information.
 - (ii) As per the established practice being followed in DGAD at the time of initiation of the present investigation, the non-confidential version of the import data was mandatorily provided with each and every petition and the same was placed in the public file, however opposite to the rule has been permitted by the authority.
 - (iii) For confidentiality claims, the respondent has scrutinized its own responses and found that no excessive confidentiality has been claimed.
 - (iv) Right to make effective comments has been curtailed as domestic industry did not file the complete information in NCV petition. We reserve our rights to comment as and when the information is provided to us.
 - (v) Initiation of investigation is based on incorrect information and therefore, the test of adequacy and accuracy in rule 5 of Anti-dumping Rules has not been met. The petitioner has furnished data/information only in respect of subject goods sold under the name of DOP, if the complete sales and production of the product was given, there would have been no decline in the sales of DOP during the POI. Petitioners are themselves selling plasticizers under different varieties of Kanatols and they themselves have admitted that it is near substitute of DOP.

- (vi) It is contended by the petitioner that all types of DOP have been included for the purposes of the injury parameters such as capacity utilisation, production and sales, if that be the case, why the details of different types of DOP considered was not disclosed.
- (vii) The domestic industry has a history of using the mechanism of trade remedial measure to oppress the user industry for gaining monopolistic position in India. Earlier, the domestic industry has sought protection like safeguard duty imposed on import of DOP and now they are seeking the way of protection under anti-dumping by distorting the data.
- (viii) Domestic industry is a phthalate plasticizers and total installed capacity for all the products by it is 1, 80,000 MT per annum as per its annual report. However, there is no dedicated installed capacity for the PUC.

D.3 Examination by the Authority

19. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

20. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business related information as confidential.
21. As regards disclosure of DGCI&S transaction wise data, it is noted that the domestic industry has claimed that such data has been purchased by obtaining authorization from the Authority. Domestic industry has also stated that DGCI&S data is confidential information and the petitioner is not authorized to disclose without specific authorization from DGCI&S. However, any interested parties may obtain the DGCI&S data on receipt of authorization from DGAD. Moreover, the summary of import statistics has been provided to all the interested parties in the non-confidential version of the petition filed by the domestic industry.

E. Miscellaneous Submissions

E.1 Submissions made by the Domestic industry

22. The miscellaneous submissions made by the domestic industry are as follows:

- (i) The information filed by the domestic industry is duly verified by the Authority and also the costs are certified by the Cost/ Chartered Accountants.
- (ii) The purpose of the petition is not to take any kind of price advantage from the ADD that is proposed to be imposed. The petitioner simply wishes to gain the market that has been lost by Indian producers to the imports. The petitioner has suffered adverse volume effect as a result of dumping in the country. If the authority imposes ADD, the petitioner will be able to regain the volumes that have been lost and shall maintain its share in the market. Thus, when the petitioner is not intending to increase prices in any manner barring the price increase or reduction that might be necessary due to changes in raw material; in any case, there shall be no adverse impact of the proposed duty on the consumers. Therefore, the interested parties need not be concerned about the ADD that is proposed to be imposed.
- (iii) The opposing interested party is trying to mislead the Authority. The Balance Sheet shows total sales of all products and not of DOP sales. The product under consideration in the present is not all Plasticizers but

only DOP. Opposing interested party are equating the production of all Plasticizers with production of DOP. Further the production figures of M/s Lalitha Chem Industries Pvt. provided by the opposing interested party is for the year 2015-16 which is not even the period of investigation.

- (iv) The opposing interested party has not provided any evidence to prove that 8500MT of imports is duty free imports. There has been plethora of cases wherein the Designated Authority has included imports under advance license for examination of dumping and injury. It is purely presumptive on the part of the interested parties that imports made under advance license are not capable of causing any injury to the domestic industry. Such imports are clearly causing injury to the domestic industry. Import for export production are exempted by the Govt. of India from purview of anti-dumping duty under advance authorization scheme, does not imply that these imports are not causing injury. It only implies discretion of the Govt. of India while imposing anti-dumping duties.
- (v) The period of investigation for the present investigation is April 2016 – March 2017 and the case was initiated on 1st June, 2017. Therefore there is only a gap of 2 months between a period of investigation in the petition and initiation of investigation. Therefore it is consistent with the WTO's Anti-dumping Committee document G/ADP/6. Regarding change in period of investigation, it has been consistent practice globally including Designated Authority, to change the period of investigation by the Authority from what has been adopted by the petitioner in their petition. There is no inconsistency in such practice.
- (vi) Reference is placed on Panel report in the matter of Mexico – Anti-Dumping Duties on Steel Pipes and Tubes from Guatemala wherein the Panel stated that there is no inconsistency if the gap between the end of the period of investigation and initiation is even 8 months. The domestic industry was also provided 40 days' time period to file updated information just like the other interested parties were to give data for the purpose of the investigations. This was consistent with the past practice of the Designated Authority. Further, there was no bar on the interested parties to file comments on the updated information to the domestic industry. The non-confidential version of the updated information was placed in the public file.
- (vii) While DOP is not a major cost item for the consumers, it is a vital material for manufacturing of Polyvinyl Chloride (PVC) to produce Plastic Film, Imitation Leather, Electric wire, Cable wearer etc. Thus, viable and vibrant domestic industry is in the larger interest of the Country.
- (viii) A lot of parties made themselves known for the first time after five months of the deadline. Such being the case, any submissions filed by any of these parties should be rejected on the ground of delayed submission. The authority had earlier specified a time limit of 15 days for registration of interest parties vide trade notice No. 01/2012 dated 9th January 2012. Not only that none of the said parties registered themselves as an interested party within the stipulated time as per the Trade Notice, but also these parties never filed response to the questionnaire or submissions with the Authority. This trade notice has been heavily abused.

E.2 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

23. The submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties with regard to miscellaneous issues during the course of the investigation are as follows:
 - (i) Data/information considered by authority to arrive at conclusion for initiation in terms of provisions of Rule 5 of Anti-dumping rules has not been provided. Right to participate in the investigation has been curtailed. Hearing held on 22nd December cannot be referred as effective hearing in terms of rule 6(6).
 - (ii) Present proceedings are not maintainable as they have not been initiated according to the rule 5 of the AD Rules. For the purpose of initiation, all the parameters have to necessarily show a decline. However, there is no injury or decline as far as price related aspects of injury are concerned. Domestic Industry has clearly stated in the hearing that there is no price injury in the present case and is earning significant profits.
 - (iii) There are 1,500 to 2,000 compounding units in India for PUC. Imposition of Anti-dumping duty will have disastrous result on the compounding and downstream industries. Imposition of duty would increase the cost, which would result in higher increase of prices, on account of taxes and duties. Petitioner is manufacturing DOP as well as compounds, imposition of ADD will adversely affect the importers/users which would result in manufacturing of compound at much lower cost by the petitioner. Authority is requested to balance the interests of the petitioners and the users, as both are Indian Industry and entitled to equal treatment.
 - (iv) Annual Report of M/s KLJ Plasticizers for POI states DOP sales as a worth INR 1,100 crores which results in Volume of around 1,40,000-1,50,000 MT. In petition the data provided, states that the sales are 45,319 MT. Domestic Industry is trying to mislead and misguide the Authority by filing false data.
 - (v) ADD on Raw materials of DOP have already been levied, the duty on the PUC will cause hardship and cascading effect on to the end users, with three duties on the product will be against the public interest.

With increase in cost of raw material the buyers of their products may prefer to import rather than buying from the domestic small manufacturers, this will go against the Govt. policy of MAKE IN INDIA.

- (vi) DOP consumers are all in SME; creating huge jobs and are giving the “Make in India” initiative a major boost, hence imposition of Anti-Dumping Duty will lead to shutting down of many industries and downstream industries will suffer and would promote the monopolistic attitude of the petitioner.
- (vii) Difference in POI between the one in the petition and the one approved by the Designated Authority is different and raises serious concerns. As per WTO’s Anti-dumping Committee document G/ADP/6, the period of data collection in an Anti-Dumping investigation should end close to date of initiation of the case. In the current case, the petition ended in Sep, 2016 however it was initiated on 1ST June, 2017 which shows a gap of 8 months.
- (viii) Updated petition was not placed in public file immediately after initiation of the case. The Domestic Industry has not followed the procedure as it filed the NCV version of the revised petition after the initiation of the case.
- (ix) Imposition of Anti-Dumping Duty would have adverse effect not only on the users of the Product under consideration but also the downstream industries. Imposition of Anti-Dumping Duty would result in shifting of manufacturing abroad and import of value added product in India threatening their survival and also of downstream industries.
- (x) Imposition of Anti-Dumping Duty on DOP Import may result in domestic suppliers taking advantage of the situation and further increase the price of DOP. Due to the same, PVC Compound cost will go up and will result in increase in cable and wire price in the market. Imposition of Anti -Dumping duty will adversely impact the cable and wire industry as well as interest of consumers.
- (xi) Petitioner has made certain submissions claiming that despite existence of unutilized capacities, other Indian producers were compelled to import PUC. Request has been made to Authority to reject this submission, as other Indian producers have submitted that producers faced issues of increased cost of production as well as availability of raw material due to AD duties on raw materials of PUC. It was admitted that increased cost and lack of raw material availability were the cause of such import, during oral hearing.
- (xii) With regard to acceptance of delayed response, reliance has been placed on PTFE from China PR-MTR, PVC Suspension Grade, PVC Flex and Barium Carbonate China PR wherein delayed response has been accepted not only from the interested parties but also from the domestic industry.
- (xiii) With regard to that delayed responses filed by the importers, the petitioner has not deliberately disclosed the names of major importers/users in their petition. As importers/users were not mentioned in the petition, they did not receive any communication regarding initiation of the investigation or the Questionnaire Response, and were unable to file the submissions within the time limits.
- (xiv) The petitioner knows that there are 500 consumers of the product in India out of which 425 have not agreed to the imposition of Anti-dumping duties and their participation is necessary in the investigation. Reliance has been placed on Automotive Tyre Manufacturers Association vs. Designated, wherein it was held that in an adversarial proceeding, having a quasi-judicial character, the participation of the opposing parties is essential to ensure that the correct result is reached.
- (xv) During the POI, M/s KLJ has claimed injury due to dumped import. However, during the same period DI has substantially increased its profits, achieving its highest profits. When there was no dumping, the return on capital employed was negative. However, the DI has the highest return on capital employed during the POI when the imports are at the highest level. Thus, injury so claimed is not due to imports.
- (xvi) During the POI, KLJ is producing and earning profit on its sales. The producers of DOP in general are in process of enhancing capacity expecting a good prospectus of growth in this industry. There are no sign of industry suffering due to dumped import rather they are well competing with the imports.
- (xvii) The initiation of anti-dumping duty on DOP itself has led to steep rise in DOP prices, the DI has created an artificial shortage by hiking the prices every day. PVC industry is facing steep competition from cheap imports of finished goods like PVC floorings, PVC Geomembrane, Sheetings, and Films etc. from countries having no anti-dumping duty. With imposition of anti-dumping duty on DOP will be highly detrimental to the survival of processing industry in India.

E.3 Examination by the Authority

24. Various submissions made by the interested parties with regard to miscellaneous issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- (i) With regard to the argument of insufficient information of domestic industry duly filed by them, the Authority notes that the application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after deriving satisfaction that application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation, decided to initiate the present investigation.
- (ii) As regards contention regarding POI, it is noted that the Period of Investigation (POI) proposed by the applicant was for the period from April 2015 to September 2016 (18 months). However, for enabling the Authority to make required analysis on the basis of more updated data, the Authority has considered more recent period of POI as April 2016 to March 2017 (12 Months). The injury investigation period, however, covered the periods 2013-14, 2014-15, 2015-16 and period of investigation. The information with regard to revised period of investigation was made available in the public file.
- (iii) The period of investigation fixed by the Authority was communicated to the domestic industry on initiation of the investigation. The Authority provided 40 days to the domestic industry, similar to that provided to other interested parties to provide data for the updated period of investigation. The updated information was timely filed by the domestic industry and was placed in the public file.
- (iv) As regards the contention that imposition of Anti-dumping duty will have disastrous result on the compounding and downstream industries, the Authority notes that the objective of imposing anti-dumping measure is to rectify unfair trade practices and to redress its injurious effect by providing level playing field to domestic industry. Moreover, imposition of anti-dumping measures does not prevent imports, however imports will be available at fair prices and it will also allow competition in the domestic market.
- (v) As regards the contention of the domestic industry that injury has been caused due to the other products, the Authority notes that injury to the domestic industry is required to be analysed for the product concerned and not for the sector as a whole or due to non PUC. Being a multi-product group, data/information has been segregated for the product concerned in order to examine their injury, if any, due to dumping from imports of subject goods from subject countries.
- (vi) As regards the concerns raised by the other interested parties with reference to petitioner's submission of financial statements in Ministry of Corporate Affairs (MCA), the Authority has examined the said submissions and it is noted that the turnover mentioned in the financial statements as submitted to the MCA is for total turnover of DOP. Subsequent to the oral hearing, this issue was specifically asked from the domestic industry and it has been stated by the domestic industry that there has been an inadvertent error in filing the information to MCA as the company faced certain technical glitches at the time of filing the return. However, in order to supplement its committed error, the domestic industry has stated that the Cost Audit Report (CAR) establishes the facts that the total turnover of Rs.1158 crores of the company matches with the figure as reported to the MCA. The domestic industry further clarified that the cost audit report for the period of investigation establishes that the number of products produced and sold by the company during the relevant period matches with the audited P&L account figure of the company, which was duly verified by the Authority. In reply to the submission of financial statement before MCA, the petitioner has stated that there has been inadvertent error for filing information for the entire injury period. However, Authority is of view that such claim of 'inadvertent error' is not acceptable as such unrectified mistakes in statutory filing of information before the regulatory authority is incomprehensible.
- (vii) With regards to exclusion of imports under advance licence, it is noted that these imports have been taken into account for the purpose of working out total imports, demand and volume assessment in order to examine the volume impact in this AD investigation.
- (viii) As argued by the other interested parties about the quality of the product manufactured by the domestic industry and those imported into India, it is noted that since the product manufactured by the domestic industry is held as like article to the product being imported into India and the two are used interchangeably by the users/importers, such issues raised by the interested parties is without evidence to establish the same.
- (ix) As regards the concerns raised by the domestic industry that a number of parties have appeared for the first time at the oral hearing and have filed belated submissions. It is noted that the parties have not availed opportunity provided to them in timely manner to file their submissions/information. The Authority notes that anti-dumping duty investigations being time bound, it requires exchange of submissions being filed by registered interested parties and file comments, in order to assist the authority to arrive at a fair determination. Exporters, producers, importers and other interested parties who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperative.

However the Authority, taking a pragmatic judicious view, has considered and examined their submissions appropriately and addressed the submissions made by them at appropriate places.

- (x) As regards the determination of non-injurious price for the product, it is noted that the total plant production has been taken for the purpose of optimization of production for determination of NIP. Since, the domestic industry claims that the other products are also produced using the same production facility, authority found it appropriate to consider the total plant production for normation and determination of NIP.

F. Normal Value, Export Price and Dumping Margin

25. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:-

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either*
 - (a) *Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

F.1 Submissions by Domestic Industry

26. Following submissions made by the domestic industry with regard to Normal Value:

- (i) None of the exporters have fully replied to the question with regard to the valuation of raw material i.e. PA and 2EH. Further, some of the exporter's has not even provided any information on the valuation of raw material which are captively produced by them or claimed to have negotiated the prices. Whereas, the website information of majority responding exporters are procuring raw material captively. It needs to be established by the exporters that the prices of such raw materials reasonably reflect the costs associated with production and sale of DOP.
- (ii) In the present investigation, questionnaire responses are unclear on sales channels adopted and how the response filed presents comprehensive sales channels adopted by these producers. The completeness of the questionnaire response is vital for determination of individual dumping margin. In this scenario, the responding exporters'/producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value and export price unless it is established that the questionnaire response filed by them are complete and meets the statutory requirements. This is particularly important in this case as there is a complex web of value chain involved, and the producers are backward-forward integrated either directly or through related company. Due to the absence of complete value chain of the exports, the Authority should not determine individual dumping margin.
- (iii) In the present investigation, questionnaire responses are unclear on sales channels adopted and how the response filed presents comprehensive sales channels adopted by these producers. The completeness of the questionnaire response is vital for determination of individual dumping margin. Based on the questionnaires filed by the exporters, it is noted that Everlite Korea Co Ltd is supplying the products made by Hanwa Chemicals, who is one of the producer of product under consideration in Korea. Hanwa Chemicals have not responded in the present investigation. Further, Nan Ya Plastics (Taiwan) and OCI Co Ltd have stated that they are exporting the product under consideration through traders. However, it is not clear whether all these traders have filed the questionnaire response.
- (iv) In the present investigation, one producer has exported the product through several exporters, and one exporter has exported goods produced by several producers. Nothing has been mentioned in the questionnaire which depicts the functions being performed by these producers, traders, exporters and shippers. As Aekyung Petrochemicals Co Ltd (Korea) is a producer who has exported the product through Humade Corporation (Korea), Ubesco Corporation (Korea) and Everlite Korea Co Ltd (Korea). Humade Corporation and Ubesco

Corporation are related companies. Also, Nan Ya Plastics (Taiwan) is a producer who has exported the product through different traders including JC Petrochem Ltd (Hong Kong).

- (v) In the same way, OCI Co Ltd is a producer who has exported the product through different traders/distributors including Everlite Korea Co Ltd. Everlite Korea Co Ltd (Korea) is a trader who has exported to India the product manufactured by OCI Co Ltd (Korea), Hanwa Chemicals (Korea) and Aekyung Petrochemicals Co Ltd (Korea). Hanwa Chemicals has not cooperated in the subject investigation. With regard to such complex web trade channel, the exporters would take advantage of the individual duties assigned to a particular sales channel.

F.2 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

27. The submissions made by the exporters, importers and other interested parties are summarized below:

- (i) The export prices from China or Taiwan or Korea is same except the ocean freight which is equalized to ensure buyers in India have same prices. The local producers are correcting the prices every month or fortnightly based on Demand and supply ability.
- (ii) The traders of OCI have participated in the investigation and the value chain is complete. With respect to Everlite, respondents are seeking individual duty margin with respect to trade/export chain. Authority in India grant individual margin not to specific exporter but to participating trade/export chain. Non participation of Hanwa chemicals would not impact the duty to OCI-Everlite trade/export chain.
- (iii) Authority must note that the case laws cited by the petitioner refer to situations where exports of PUC could not be evidenced rather than situations where response of exporter has been rejected for one trade chain due to non-participation of producer of another trade chain
- (iv) Claim of the petitioner regarding complex web of trade channel and dumping margin should be rejected as duty margins determined by the Authority are on the basis of the trade channel, including a producer and exporter rather than either one in isolation. Such practice is followed globally, where different producers are assigned different duty rates.
- (v) As per the established practice of authority to impose different duty margins for the same exporter when supplying the goods of different producers. Such producers have unique normal value and a unique ex-factory export price, therefore determination of different duties for same exporter supplying goods of different producer becomes inappropriate to fair assessment by authority. Reference has been placed upon “O-Acid from China”, wherein authority determined different duty margins.
- (vi) In India, authority does not determine individual dumping margin but identifies duties based on channel of trade between producer and exporter to India. Such distinction ensures that a fair trade channel is encouraged.

F.4 Examination by the Authority

28. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
- (ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

29. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, barring the following producer and exporters, none of the other producers/exporters from subject countries co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses

- a) OCI Company Ltd., Korea RP
- b) Nan Ya Plastics Corporation, Chinese Taipei
- c) Everlite Korea Co Ltd., Korea RP
- d) JC Petrochem Limited, HongKong
- e) Aekyung Petrochemical Co. Ltd., Korea RP

- f) Canko Marketing Inc., Korea RP
 - g) Chemtown Co. Ltd., Korea RP
 - h) Humade Corporation, Korea RP
 - i) Hyundai Corporation, Korea RP
 - j) Ubesco Corporation, Korea RP
 - k) Woori P&C Corporation, Korea RP
30. Since the above mentioned producers/exporters have filed the questionnaire response, the Authority proposes to determine individual dumping margin in respect of these companies. The general methodology adopted by the Authority for determination of Normal Value for these exporters is to first examine whether the domestic sales of the subject goods by the responding exporters in their home markets were representative and viable for permitting determination of Normal Values on the basis of domestic selling prices and whether the ordinary course of trade test was satisfied as per the data provided by the respondents.
31. In the case of non-cooperating exporters in the subject countries, the Authority proposes to determine the normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6 (8) of AD Rules read with Article 6.8 of the Agreement.

Normal Value for Aekyung Petrochemical Co., Ltd., Korea RP

32. M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., during the POI, has sold 13801.00 MT of the subject goods having invoice value *** KRW in the domestic market. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. If profit making transactions are more than 80% then the authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. In this case, based on the ordinary course of trade test, all domestic sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were more than 80%.
33. M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., has claimed adjustments on account of freight expenses, bank charge, commission, credit expense and packing expenses which have been duly verified and considered by the Authority except the commission since it was not substantiated. Accordingly, weighted average normal value for M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., has been determined as ***US\$/MT.

Normal value for M/s OCI Co. Ltd., Korea

34. M/s OCI Co. Ltd., during the POI, has sold 16,705.51 MT of the subject goods having invoice value ***KRW in the domestic market. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. If profit making transactions are more than 80% then the authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. In this case, based on the ordinary course of trade test, only profitable domestic sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80%.
35. OCI has claimed adjustments on account of packing cost, inland freight, Warehouse Charge and credit expenses which have been duly verified and considered by the Authority. Accordingly, weighted average normal value for M/s OCI Co., Ltd., has been determined as ***US\$/MT.

Normal Value for non-cooperating producers and exporters from Korea RP

36. The Authority notes that no other producer/exporter from Korea RP has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Korea RP, the Authority has determined normal value as ***US\$/MT as facts available.

Export Price

Export Price for M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., Korea RP with M/s Canko Marketing, INC., M/s Humade Corporation, M/s Ubesco Corporation, M/s Chemtown Co., Ltd., M/s Hyundai Corporation and M/s Woori P&C Corporation, Korea RP.

37. M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., has filed the questionnaire response along with its unrelated trading companies, namely, M/s Canko Marketing, INC., M/s Humade Corporation, M/s Ubesco Corporation, M/s

Chemtown Co., Ltd., M/s Hyundai Corporation and M/s Woori P&C Corporation, Korea RP. These companies exported the subject goods, manufactured by M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., during the POI.

38. M/s Canko Marketing, INC., has exported 15387 MT of subject goods having invoice value *** US\$ to India, manufactured by M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd. Out of total exports to India by M/s Canko Marketing, INC., 12874.00 MT of subject goods having invoice value *** US\$ have been sold to India directly by M/s Canko Marketing, INC., and rest of 2017.00 MT of subject goods having invoice value *** US\$ and 496.00 MT of subject goods having invoice value *** US\$ respectively sold to India through two traders namely M/s Innovesco, Singapore and United Raw Material, Singapore. Since these two traders did not file their EQR the Authority did not consider these exports to India for determination. M/s Canko Marketing, INC., has claimed adjustments on account of insurance, bank charges, commission, certificate of origin expenses, freight charges, L/C expenses. Adjustments claimed by M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., with regards to M/s Canko Marketing, INC., have been considered after due verification. Accordingly, the weighted average export price has been determined for M/s Canko Marketing, INC., as *** US\$/MT.
39. M/s Chemtown Co., Ltd., has exported 480 MT of subject goods, having invoice value *** US\$ to India, manufactured by M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., and claimed adjustment on account of ocean freight, handling expenses, commission, bank charges, insurance, L/C expenses and credit expenses. Adjustments claimed by M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., with regards to M/s Chemtown Co., Ltd., has been considered after due verification. Accordingly, the weighted average export price has been determined for M/s Chemtown Co., Ltd., as ***US\$/MT.
40. M/s Humade Corporation., has exported 15581 MT of subject goods having invoice value *** US\$ to India manufactured by M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., and claimed adjustment on account of L/C expenses, bank charges, freight expenses, insurance, commission, and credit expenses. Adjustments claimed by M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., with regards to M/s Humade Corporation, has been considered after due verification. Accordingly, the weighted average export price has been determined for M/s Humade Corporation, as ***US\$/MT.
41. M/s Hyundai Corporation, has exported 630 MT of subject goods having invoice value *** US\$ to India manufactured by M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., and claimed adjustment on account of insurance, bank charges, L/C expenses, document fee and credit expenses. Adjustments claimed by M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., with regards to M/s Hyundai Corporation, has been considered after due verification. Accordingly, the weighted average export price has been determined for M/s Hyundai Corporation, as ***US\$/MT.
42. M/s Ubesco Corporation, has exported 1617 MT of subject goods having invoice value *** US\$ to India manufactured by M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd. and claimed adjustment on account of L/C expenses, bank charges, insurance and credit expenses. Further adjustments claimed by M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., with regards to M/s Ubesco Corporation, has been considered after due verification. Accordingly, the weighted average export price has been determined for M/s Ubesco Corporation, as ***US\$/MT.
43. M/s Woori P&C Corporation, has exported 16 MT of subject goods having invoice value *** US\$ to India manufactured by M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd., who has further exported subject goods to India through another trader namely M/s Oxyde Chemicals China Limited, Hong Kong. Since, trader namely M/s Oxyde Chemicals China Limited, Hong Kong, did not file the EQR, thereby, Authority did not consider these exports to determine the net export price with regard to M/s Woori P&C Corporation.
44. Accordingly, the weighted average export price has been determined for exports to India by M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd. through M/s Canko Marketing, INC., M/s Humade Corporation, M/s Ubesco Corporation, M/s Chemtown Co., Ltd., and M/s Hyundai Corporation Korea RP, as ***US\$/MT.

Export Price for M/s OCI Co. Ltd. along with M/s Everlite Korea Co. Ltd., Korea RP

45. M/s OCI has filed questionnaire response along with its unrelated trading company, namely, M/s Everlite Korea Co. Ltd., Korea RP. During the POI, OCI has exported 500 MT of the subject goods to India only through Everlite. M/s OCI has sold the subject goods to Everlite on FOB terms. M/s OCI has claimed adjustments on account of inland freight, port handling expenses, flexi-tank fees, credit expenses and bank charges. The same have been allowed, after due verification. From the response filed by Everlite, Authority also notes that Everlite has exported 3 export transactions of subject goods manufactured by Hanwha Chemical, who has not cooperated with the authority. Further, Everlite also exported 4 export transactions of subject goods manufactured by Aekyung Petrochemical Co., Ltd. However, Aekyung Petrochemical Co., Ltd has sold the subject goods prior to

POI to Everlite. Therefore, Authority *did not consider* the transactions of Aekyung Petrochemical Co., Ltd and Hanwa Chemical for determination of individual margin.

46. Accordingly, the weighted average export price has been determined for OCI exported through Everlite as ***US\$/MT

Export Price for non-cooperating producers and exporters from Korea RP

47. The Authority notes that no other producer/exporter from Korea RP has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Korea, the Authority has determined weighted average export price as ***US\$/MT as facts available.

Chinese Taipei

Normal Value for M/s Nan Ya Plastic Corporation, Chinese Taipei

48. M/s Nan Ya Plastic Corporation, during the POI, has sold 6987.59 MT of the subject goods having invoice value *** NTD in the domestic market. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. If profit making transactions are more than 80% then the authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. In this case based on the ordinary course of trade test, only profitable sales have been taken for determination of normal value since the profit making sales were less than 80%.
49. Nan Ya Plastic Corporation has claimed adjustments on account of freight expenses, packing expenses and credit expense which have been duly verified and considered by the Authority. Accordingly, weighted average normal value for Nan Ya Plastic Corporation has been determined as ***US\$/MT.

Normal Value for non-cooperating producers and exporters from Chinese Taipei

50. The Authority notes that no other producer/exporter from Chinese Taipei has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Chinese Taipei, the Authority has determined normal value as ***US\$/MT as facts available.

Export Price for M/s Nan Ya Plastic Corporation, Chinese Taipei with M/s JC Petrochem Ltd., Hong Kong

51. M/s Nan Ya Plastic Corporation has filed the questionnaire response along with its unrelated trading company, namely, M/s JC Petrochem Ltd., Hong Kong and they have exported the subject goods which were manufactured by M/s Nan Ya Plastic Corporation during the POI.
52. M/s Nan Ya Plastic Corporation has directly exported 278.34 MT of PUC and exported 12985.13 MT through M/s JC Petrochem Ltd., Hong Kong. Since, M/s JC Petrochem Ltd., Hong Kong did file the EQR, thereby, authority has determined the export price based on the total quantities exported to India.
53. They have claimed adjustment on account of commission, ocean freight, insurance, inland freight, packing, back charges, trade promotion service fee, customs clearance fee, harbor service fee, harbor facility charge, dockage fee, slot fee and credit expenses and the same have been considered, after due verification in order to arrive at ex-factory export price. Accordingly, the weighted average export price has been determined as ***US\$/MT.

EXPORT PRICE for non-cooperating producers and exporters from Chinese Taipei

54. The Authority notes that no other producer/exporter from Chinese Taipei has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Chinese Taipei, the Authority has determined weighted average export price as ***US\$/MT based on facts available.

Dumping Margin Table

55. The dumping margin during the POI for all exporters/producers from the respective subject countries have been determined as provided in the table below:

<u>S.No.</u>	<u>Country</u>	<u>Producer</u>	<u>Exporter</u>	<u>Normal value (US\$)</u>	<u>Export Price (US\$)</u>	<u>Dumping Margin (US\$)</u>	<u>Dumping Margin %</u>	<u>Range</u>
1.	Korea RP	M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd.,	a) M/s Canko Marketing, INC., b) M/s Humade Corporation, c) M/s Ubesco Corporation, d) M/s Chemtown Co., Ltd., e) M/s Hyundai Corporation	***	***	***	***	0-10
2.	Korea RP	M/s OCI Co. Ltd.	M/s Everlite Korea Co. Ltd.	***	***	***	***	0-10
3.	Korea RP	All Others	All Others	***	***	***	***	15-25
4.	Chinese Taipei	M/s Nan Ya Plastic Corporation	a) M/s Nan Ya Plastic Corporation b) M/s JC Petrochem Ltd., Hong Kong	***	***	***	***	20-30
5.	Chinese Taipei	All Others	All Others	***	***	***	***	35-45

G. Injury Determination

G.1 Submissions made by domestic industry

56. The following submissions with regard to injury and causal link have been made by the domestic industry:

- (i) The quantum of imports are significantly undercutting the prices of domestic industry as the landed price of imports is much lower than the cost of sales and selling price of the domestic industry.
- (ii) Price underselling is not a prescribed parameter under AD rules, therefore domestic industry did not provide information in this regard. The injury margin and price underselling is same as per the past practice of the Authority. The landed price of imports was significantly below the non-injurious price of the domestic industry. Thus, the subject imports are underselling the domestic prices.
- (iii) Domestic industry has claimed injury during the period of investigation and the same has been accepted by the opposing party. The production and capacity utilisation of domestic industry has declined over the period which is due to dumping of the subject goods. The decline in 2014-15 is due to commencement of production in the enhanced capacities, the capacity utilization even after two years is much below the levels that were achieved in 2013-14.
- (iv) The capacity utilization of the domestic industry has declined from 39% to 26% over a period, which cannot be considered as stable.
- (v) The imports have increased significantly thereby causing volume injury to the domestic industry. With such increase in imports, the performance of the domestic industry has deteriorated both on volume and price in post investigation period. There is a direct relation in performance of the domestic industry.
- (vi) The petitioner does not have any intention to increase the prices in any manner barring the price increase or reduction that might be necessary due to changes in the price of raw material, there shall be no adverse impact of the proposed duty on the consumers.
- (vii) Domestic industry is not selling any substitute of DOP for capturing the market as there is no viable substitute of DOP. With regard to the prices of DOP, they are much higher than the other products sold by the domestic industry.
- (viii) Injury has been claimed on the basis of volume parameter. The domestic industry has maintained the prices, thereby suffering on volume front. The industry has only two options, either to compromise on price to maintain volumes and suffer losses, or maintain price and suffer decline in volumes. The dumped imports have

resulted in mounting losses for not only the petitioner but to DOP industry as a whole in India making operations unviable, which resulted in suspending the production and resorting to imports. There were about 70 companies in India manufacturing DOP earlier but at present out of 70 only 5 companies have continued their production.

- (ix) Domestic Industry has provided the data to the Authority for both bulk and packed. Even the comparison is made for bulk and packed DOP, it would be seen that the imports are undercutting the prices of the domestic industry in these segregated forms as well.
- (x) While assuming and not admitting, lack of price suppression does not mean there is no injury to the domestic industry. The existence of positive price undercutting is sufficient to establish the price effect caused by the dumped imports to the domestic industry. Rules have placed price undercutting and suppression/ depression as alternates, as established by the use of “OR” under the law.
- (xi) Both the production and capacity utilization of the domestic industry has shown decline over a period.
- (xii) The figures of sales for product under consideration have already been verified by the authority and it includes sales of the stabilized softener. The overall sales of the domestic industry have declined over a period.
- (xiii) Injury has not been claimed by the domestic industry on account of profits, cash profits, return on capital employed or increased inventories. Imposition of the anti-dumping duty would result positive as the petitioner will be able to regain the volumes that have been lost and shall maintain its share in the market.
- (xiv) As regard the level of employment, the domestic industry has not claimed injury on this ground. These are governed by several legislative requirements in the Country and various business compulsions with the domestic industry. Employment and wages are not reflective of the adverse effects of the dumping on the domestic industry, as these factors are governed by overall operations of the company and the economy.
- (xv) The petitioner does not have any intention to export the product under consideration. The capacities installed by the company are for the Indian market. If export would have been the intention then the petitioner would have installed capacity in EOU or SEZ to avail benefits for such exports.
- (xvi) The landed price of imports is below the NIP and the injury margin is positive.
- (xvii) The effect of dumped imports on the performance of the domestic industry has to be evaluated cumulatively and not country wise. In any case, the imports from Taiwan are undercutting the prices of the domestic industry.
- (xviii) As regards price parameters are showing increase. Domestic industry has not claimed price injury during the present investigation period but has claimed volume injury in investigation period and price & volume injury in post investigation period.
- (xix) In present case, imports under advance license are causing injury to the domestic industry, as the capacities with the domestic industry are remaining unutilized. If the exporters sell at undumped prices, the domestic industry would be able to cater to this requirement of the consumers.
- (xx) The imports are entering the Indian market at price even lower than the cost of sales, and selling price and causing price undercutting to the domestic industry. Further, participation of domestic industry in Phthalic Anhydride anti-dumping duty investigation does not have any relevance in the present case. Opposing imposition of anti-dumping duty on raw materials does not debar a party for seeking anti-dumping duty on its product.
- (xxi) The opposing interested party has admitted that there is an increase in imports. As regards dumping, the petitioner has already established the existence of dumping of the product concerned in the petition which has caused injury to the domestic industry.
- (xxii) The import of product under consideration is undercutting the prices of the domestic industry, which clearly shows that the price of imports is lower than the selling price of the product under consideration. Further, the fact that Payal Petrochem Pvt Ltd, having its own manufacturing facilities and is forced to suspend its production keeping its facilities idle and instead import in order to maintain its customers is enough to prove that the DOP industry is faced with injurious imports. The representative of Payal Petrochem Pvt Ltd itself states the same in the public hearing.

G.2 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

57. The following submissions with regard to injury and causal link have been made by the Exporters, Importers, Users and other Interested Parties:

- (i) Domestic industry has failed to provide any evidence for material injury due to dumped imports of PUC.
- (ii) Applicants have not been able to make out a case of any injury, let alone material injury. Almost all the injury parameters demonstrates improvement from the base year as well as from the preceding years which cannot lead to a conclusion of injury let alone “material injury”.
- (iii) Cost of sales and selling prices have dropped drastically. The prices of raw material have declined price undercutting claimed by the petitioner is flawed as the drop in the prices of imported goods have actually been in proportion to the drop in prices of raw material and the cost of sales and selling prices of the Domestic

Industry. Price undercutting is not a factor of injury. No information has been given regarding price underselling; we are entitled to presume that they are not having any issue with price underselling.

- (iv) Production of the domestic industry has increased except for the POI. Plant capacity utilization has remained same. Decline in market share is due to the focus from PUC to other products, which could be more profitable products for them.
- (v) Per unit profit and cash profit has been increased from the base year. ROCE is in the range of 15-25% which is significantly high but it rules out the possibility of any injury. From the table, it can be seen that Cost of sales declined by 34%, while the selling price only declined by 31%, Profit per unit increased by 71%, Cash Profit increased by 58%, Profit before interest and tax increase by 42%, Employment increased by 14%, wages by 21%, Capital Employed increased by 21%, Return on Capital Employed surged to 15-25%
- (vi) Claim of injury by Domestic industry is baseless, misconceived, legally unsound and do not hold any value in terms of the Anti-Dumping Rules. There is no occasion to claim either the volume or price injury.
- (vii) Domestic Industry has included the self-imports from the subject countries while computing the injury and is flawed on the basis of calculation of demand and its trend, Market share of imports from the subject countries in imports, Market share of imports from the subject countries in demand and Market share of imports from the subject countries in production.
- (viii) The trend of imports has no correlation with the trend of the injury parameters. There is inverse relationship between the imports and the injury parameters (sales, cash profits and profits).
- (ix) Petitioner is enjoying healthy profits and returns on capital employed while importers are operating on thin margins and are extremely vulnerable to changes in raw material price.
- (x) Domestic Industry is selling these substitutes of DOP at a lower price, to capture market claiming that these are better performing products. The claim of injury due to imports is baseless. If duty is imposed, domestic Industry would raise the prices of even the substitutes.
- (xi) In Proforma IV-A, production of Plant as a whole has increased over the injury period, while the production and Capacity Utilization of PUC has remained stable.
- (xii) Domestic Industry is manufacturing and selling DOP at profitable prices, during the POI, so the argument that other producers are being forced to import because production of the DOP is unviable in India is absurd. Domestic Industry is able to double its profit in the POI, as compared to the previous years, it is unimaginable as to why the other producers had to abandon production activities, in favour of making imports. It is illogical to say that the Domestic Industry has increased its capacity during the injury period.
- (xiii) It has been claimed that there is a significant price undercutting of 5% to 15%, this is the result of unfair comparison of the selling price of the Domestic Industry with the landed value of imports. The price undercutting arises only because the bulk imports have been compared to the sales in drums. Request has been made to determine the undercutting, underselling and price suppression separately for the product in bulk and in packed condition.
- (xiv) The question of price suppression does not arise as the cost of sales has fallen more than the selling price resulting in an increase in profit as compared to the previous year and the profits have doubled in the POI.
- (xv) The capacity utilization for the plant is more or less consistent during the injury period, it has declined due to diversion of capacities for other products (substitutes) and due to expansion. Whereas, profitability, returns on investment, cash flow etc, reveal a positive trends.
- (xvi) For capacity utilisation, claim of 26% by Domestic industry is grossly incorrect. As per annual report total installed capacity for all the products produced is 1,80,000 MT and there is no dedicated capacity of the product. Therefore the analysis of capacity utilization is misleading.
- (xvii) Imports have increased due to the growth in demand, Domestic industry through its related parties has imported the PUC and so the injury appears to be self-inflicted.
- (xviii) Sales volume has reduced and the same should be analyzed together with sales volume of the product Stabilized Softener sold by the domestic industry. Examination can be done when the sales of both the products are undertaken together as both are mutually substitutable and are like article.
- (xix) The profits of the domestic industry have increased and the imports have no role in affecting their prices or their performance in the domestic market. Cash profit has also increased over the injury investigation period in view of not passing the full reduction in cost on to its buyers. ROCE has increased over the injury period, there is no injury.

- (xx) For Capacity and capacity utilization of Petitioner, 2014-15 should be treated as base year, as DI increased its capacity in this year. Injury is caused because of unjustified increase in capacities.
- (xxi) As profit, cash profit and profit before interest and tax has increased. Imports are not causing injury to DI.
- (xxii) As regards return on capital employed, there is no material injury to the DI as Petitioner is selling its product above NIP.
- (xxiii) Price undercutting is in isolation and does not give meaningful price effect.
- (xxiv) No negative trends as no. of employees have increased.
- (xxv) petitioner is doing well and achieving 22% return on capital employed and increasing its profitability year by year, no injury to the Domestic Industry by the imports from the subject countries.
- (xxvi) Taiwan's share in total demand is only 5% during the POI hence no volume effect or price effect can be determined from such minimal imports.
- (xxvii) Profits of the Domestic Industry was highest in the POI when imports were highest hence no injury and no price undercutting. The case should be terminated as data shows huge profitability in the face of alleged dumped imports. The petitioner is a profit making industry and have been consistently expanding clearly shows that it is growing.
- (xxviii) ADD in this case will be inconsistent with the long-term and interests of the Indian domestic industry and its downstream industries. It will cause an unfair competitive environment and cause damage to the fundamental interests of their respective.
- (xxix) Imports are at prices, lower than those by the users of DOP. False statement has been made during hearing by Domestic industry as Indian producers have maintained a strong hold on the Indian DOP market. Situation is same in POI, while some producers have opted for imports, while others have continued the manufacturing operations. Users are at mercy of Indian producers.
- (xxx) Decrease in the import price is due to decrease in raw material prices, Domestic industry has admitted that there has been huge drop in the international prices of raw material. Domestic industry has opposed duty on phthalic anhydride, which is the main raw material for PUC.
- (xxxi) Shortage in supply is due to the acute shortage of raw material namely Octonol and also the presence of only one producer of the same. Thus Octonol is also imported to bridge the demand supply gap.
- (xxxii) Through anti-dumping petitioners are again restoring to quotas, creating shortages and would push up their profits by adjusting their prices based on landed prices post Anti-Dumping Duty being levied. Imposing of Anti-Dumping Duty would lead to ceasing of imports having impacts on consuming industry of DOP.
- (xxxiii) Increase in imports is not because of dumping but due to the Comprehensive Economic Partnership Agreement between India and Korea which has resulted in a reduction of duty of customs on imports of DOP from Korea vide Notification No. 152/2009. The increase in imports is a result of the change in applicable tariffs and duties.
- (xxxiv) Claim for injury, material or otherwise is suspected as Petitioner has earned high profits throughout the injury period and even in POI.
- (xxxv) While examining the parameters, authority is required to examine both the volume of dumped imports and its impact on domestic prices together. It is clear in the present investigation that increasing volume of imports has no impact on domestic prices. Such lack of impact is evidenced by lack of price suppression / depression. Moreover, the profitability has remained high despite of both the increased imports and price undercutting.
- (xxxvi) The figures while comparing the increase in imports (367%) and increase in demand (47%) by the domestic industry are misleading and isolated. Rather, with such increase the dumped imports accounts for 47% of demand in question. Moreover, with such substantial increase there is no effect on profitability of the petitioner. Authority cannot focus only on volume of import but should also consider the effect of imports on prices in domestic market for like article.
- (xxxvii) The claim of petitioner that landed price of imports was significantly undercutting the selling price of the Petitioner and same was below non-injurious price is without merit. Further, the undercutting of the Petitioner's selling prices is based on average for all exporters and not specifically to OCI and Everlite. The range of undercutting is within 15-25%. It can also be seen that, the petitioner is having high profits throughout injury period where there is positive undercutting.
- (xxxviii) Reliance has been placed upon the DGAD's Findings, imports of X-ray Baggage Inspection Multi Energy System (XBIS) from the European Union and imports of Ammonium Nitrate originating in or exported from Russia and Iran, wherein Net Sales Realization was higher than the determined NIP, there could not possibly be any material injury against the claim of petitioner that that landed value is lower than the Non-Injurious Price.

- (xxxix) No submission has been provided against the claim of enhanced capacity in 2014-15 and manufacturing the PUC with other products in the plant by the petitioner. Further, the loss experienced in 2014-15 is due to increased fixed costs and/or overhead costs because of expansion in the capacity of production of DOP. Moreover, negative price undercutting has been recorded in 2014-15 during which losses were incurred.
- (xl) The claim of injury is on the basis that both the production and sales of domestic industry has declined during period of investigation when compared to base year. In this regard, there has been marginal decline only and if we exclude only one year then the production and sales of domestic industry has increased despite of increase in imports. So, there is no causation between the increase in imports and the increase or decrease in production and /or sales of petitioner.
- (xli) The situation of curbed production and lower capacity utilization is due to the anti-dumping duties on raw materials for DOP and not due to dumped imports in India. Petitioner is focused on the increase in imports as a factor of injury, which is actually due to anti-dumping duties on raw materials of DOP and also accounts for decline in capacity utilization.
- (xlii) Present investigation should be terminated as no injury has been suffered by the domestic industry and high profits have been earned by them. Reliance has been placed on AA Dry Cell Batteries originating in or exported from China PR and Vietnam, wherein similar facts existed and the Authority terminated the investigation.
- (xliii) Price undercutting has no relevance in the present investigation as both the profits and ROCE are increasing. Further price underselling is not a factor of injury, reliance has been placed upon the decision of Hon'ble CESTAT in the Radial Tyre case, wherein same was held. Moreover with regards to price suppression or depression, the selling price as compared to reduction in cost has declined due to decline in raw material price.
- (xliv) Examination of the injury parameter with regard to utilization of installed capacity is incorrect and misleading. The authority should examine the capacity utilization by drawing a conclusion that this parameter does not provide any indication of injury to the domestic industry. It may be noted that, there has been increase in the plant production by 35% over the injury period and indicates no injury in terms of capacity utilization
- (xlv) With regard to argument by the domestic industry for decline in their market share, the analysis of market share of both the PUC and other products are to be considered together as both are mutually substitutable and are like article for a meaningful examination of market share.
- (xlvi) As per annual report of the domestic industry there has been no injury from the alleged dumped imports. The contents and data provided by the domestic industry in their petition are in contradiction with the facts, statements and affirmation made by the company in its annual reports.
- (xlvii) 70% of the total imports are being made by the manufacturers of DOP, at prices, which are lower than those by the users of DOP. However, this supports that the injury, if any, is self-inflicted.
- (xlviii) All types of DOP have been included for the injury parameters such as capacity utilization, production and sales by the domestic industry. Request has been made to the authority to make public the description, brand name, of all types of DOP which have been included or not included for the purposes of the injury analysis. Nothing has been mentioned regarding the sale of DOP under heading 3904 22 90, or heading 2917 3400 by some of the Indian producers. Moreover, petitioner has cleared Kanatol 800 under heading 2917 3400 during POI.
- (xlix) The injury suffered by the petitioner is not due to dumping but due to change in tariffs and duties between Korea and India. 8,500MT of imports are duty free and need to be disregarded to arrive the correct figure of volume of imports from subject countries. No ADD can be imposed on imports made under Export Promotion Schemes.
- (l) Imports made by the manufacturers of DOP are at lower prices than the users of DOP. Therefore, the undercutting is not by the imports made by the users but due to the imports made by the Indian producer themselves.
- (li) With regard to impact of dumped imports on capacity utilization, profitability, returns on investment, cash flow etc, it is to be noted that capacity utilization is consistent during injury period. Capacity utilization for PUC has declined due to diversion of capacities for substitutes and expansion. Whereas, profitability, returns on investment, cash flow etc, reveal positive trends.
- (lii) The claim of the petitioner for significant loss of production on the basis of notional achievable production should be rejected, as the analysis has been done on the basis of actual figures, which do not show any decline.
- (liii) Petitioner is unable to establish a causal link as there is no correlation between the increase in imports, steady price undercutting and economic parameters.
- (liv) Petitioner has unintentionally admitted that DOP industry is cost driven and is high as 90%, in Para 5 of the submission. Authority should note that the Anti-dumping duty on raw material has led to higher costs. This is true for small scale producers of subject goods.
- (lv) The fact that other Indian producers are being forced to import, as production of DOP is unviable in India is illogical. The petitioner has been successful to make profits during POI. Moreover, there is no justification for the imports made by the Indian Producers.
- (lvi) As evidenced by the District Industrial Potential Survey Report of 2016-17, wherein the petitioner has been mentioned, as one of the top 50 large scale and medium scale units and turnover is admittedly in excess of Rs.1000 crores. In such a situation the argument that they are small scale is totally illogical.
- (lvii) With regard to Post POI data, the authority cannot rely on the same while making determinations in an anti-dumping investigation.

- (lviii) Present application is an attempt to have monopoly in domestic market and to make profits after the imposition of anti-dumping duty on PUC.
- (lix) The injury to the domestic industry is due to the high cost of raw materials as anti-dumping duties are imposed on them. It is also the reason for performance of domestic industry.

G.3 Examination of the Authority

58. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as below:
59. As regards contention of other interested parties that injury to the domestic industry is on account of other products manufactured by domestic industry, it is noted that Anti-dumping duty, if recommended, on account of injury from the product concerned. The Authority further notes that the verified information with regard to the PUC has been considered in order to examine the injury to the domestic industry, if any, due to the dumped imports from subject countries.

H. Cumulative Assessment:

60. Annexure II para (iii) of the Anti-dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article and
 - Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
61. The Authority notes that:
- The subject goods are being dumped into India from subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the *de minimis* limits prescribed under the Rules.
 - The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.
 - Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries directly compete with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
62. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries.
63. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-dumping Rules.

I. Volume Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

i. Demand and Volume of Imports

64. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

It would be seen that the demand of the product under consideration has increased over the injury period.

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Sales of Domestic Industry	MT	46,220	50,456	53,858	45,319

<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>117</i>	<i>98</i>
Sales of Other Producers	MT	27,329	26,451	26,622	16,951
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>62</i>
Subject Countries	MT	11,235	9,007	36,291	56,527
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>323</i>	<i>503</i>
Other Countries	MT	904	305	344	813
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>34</i>	<i>38</i>	<i>90</i>
Demand/Consumption	MT	85,687	86,218	1,17,115	1,19,610
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>137</i>	<i>140</i>

ii. **Import Volume and Market Share**

65. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject good from the subject country have been analysed as under:

Imports volume	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Subject Countries	MT	11,235	9,007	36,291	56,527
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>323</i>	<i>503</i>
Other Countries	MT	904	305	344	813
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>34</i>	<i>38</i>	<i>90</i>
Total Imports	MT	12,139	9,312	36,636	57,340
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>77</i>	<i>302</i>	<i>472</i>
Market Share in Imports					
Subject Countries	%	93	97	99	99
Other Countries	%	7	3	1	1
Total	%	100	100	100	100
Imports in relation to					
- Imports	%	92.55	96.72	99.06	98.58
- Production	%	15.54	11.89	45.36	89.87
- Demand	%	13.11	10.45	30.99	47.27

66. It is noted that that

- The volume of imports from subject countries have increased in absolute terms over the injury period.
- Imports from subject countries have increased in relation to total imports of product under consideration in India.
- Imports from subject countries have increased in relation to production and consumption in India over the injury period.

J. **Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry**

i) **Price Undercutting**

67. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of like

product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

68. In order to determine whether the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level. This comparison showed that during the period of investigation, the subject goods originating in the subject countries were imported into the Indian market at prices which were lower than the selling prices of the domestic industry. It is thus noted that imports of subject goods were undercutting the domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below: Imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market.

Particulars	Unit	Korea RP	Taiwan	Subject Countries
Landed price of imports	Rs/MT	62,940	62,371	62,876
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***
Price undercutting	(Range %)	10-20%	15-25%	10-20%

S.No.	Country	Producer	Exporter	Landed Value (US\$)	Selling Price (US\$)	Price Undercutting (US\$)	Price Undercutting %	Range
1.	Korea RP	M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd.,	a) M/s Canko Marketing, INC., b) M/s Humade Corporation , c) M/s Ubesco Corporation , d) M/s Chemtown Co., Ltd., e) M/s Hyundai Corporation	***	***	***	***	10-20
2.	Korea RP	M/s OCI Co. Ltd.	M/s Everlite Korea Co. Ltd.	***	***	***	***	0-10
3.	Chinese Taipei	M/s Nan Ya Plastic Corporation	a) M/s Nan Ya Plastic Corporation b) M/s JC Petrochem Ltd., Hong Kong	***	***	***	***	0-10

The price undercutting from the subject countries, is positive.

ii) **Price underselling**

69. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from subject countries. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports. Comparison of weighted average NIP of the domestic industry with weighted average landed price of imports shows as follows:

<u>S.No</u>	<u>Country</u>	<u>Producer</u>	<u>Exporter</u>	<u>Landed Value</u> <u>(US\$)</u>	<u>NIP</u> <u>(US\$)</u>	<u>Injury Margin</u> <u>(US\$)</u>	<u>Injury Margin</u> <u>%</u>	<u>Range</u>
1.	Korea RP	M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd.,	a) M/s Canko Marketing, INC., b) M/s Humade Corporation, c) M/s Ubesco Corporation, d) M/s Chemtown Co., Ltd., e) M/s Hyundai Corporation	***	***	***	***	5-10
2.	Korea RP	M/s OCI Co. Ltd.	M/s Everlite Korea Co. Ltd.	***	***	***	***	0-(5)
3.	Korea RP	All Others	All Others	***	***	***	***	25-30
4.	Chinese Taipei	M/s Nan Ya Plastic Corporation	a) M/s Nan Ya Plastic Corporation b) M/s JC Petrochem Ltd., Hong Kong	***	***	***	***	(5)-(10)
5.	Chinese Taipei	All Others	All Others	***	***	***	***	10-15

70. Based on the verified data/information, it is noted that the price underselling is negative in case of OCI from Korea RP and Nan Ya Plastics from Chinese Taipei.

iii) **Price Suppression/Depression**

71. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

<u>Particulars</u>	<u>Unit</u>	<u>2013-14</u>	<u>2014-15</u>	<u>2015-16</u>	<u>POI</u>
Landed Price of Imports	Rs/MT	1,10,916	1,04,054	67,487	62,876
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>94</i>	<i>61</i>	<i>57</i>
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>94</i>	<i>70</i>	<i>67</i>
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>90</i>	<i>70</i>	<i>69</i>

72. It is seen that cost of sales and selling price of the domestic industry has declined over the injury period but the selling price is much above the non-injurious price of the domestic industry during the POI. Hence, in a situation of falling costs, the domestic industry has been able to realise a price which has improved its margin of profit. Since the selling price has fallen less than the cost of production, it is evident that the imports have not suppressed or depressed prices of PUC.

K. Economic Parameters Relating To The Domestic Industry

73. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
74. Accordingly, various economic parameters of the Domestic Industry are analysed herein below.

I. Sales, Capacity, Production, and Capacity Utilization

75. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization was as follows:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Capacity	MT	120,000	180,000	180,000	180,000
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
Production PUC	MT	46,262	50,533	54,594	45,945
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>118</i>	<i>99</i>
Plant Production	MT	115,378	135,200	155,139	155,252
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>117</i>	<i>132</i>	<i>135</i>
Capacity Utilization PUC	%	38.55	28.07	30.33	25.52
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>73</i>	<i>79</i>	<i>66</i>
<i>Capacity Utilization Plant</i>	%	<i>96.15</i>	<i>75.11</i>	<i>86.19</i>	<i>86.25</i>
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>78</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
Domestic Sales	MT	46,220	50,456	53,858	45,319
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>117</i>	<i>98</i>
Demand	MT	84,391	84,983	115,914	119,610
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>128</i>	<i>142</i>

76. Authority notes that the domestic industry has enhanced its capacity in the year 2014-15. The production and sales of the domestic industry has increased till 2015-16 but declined in period of investigation. The demand of the product under consideration has increased by 42%, but the domestic industry instead of using the plant for production of DOP used this facility for producing other phthalates as such the plant production has not gone down. It is also noted that there is no dedicated plant capacity for DOP and since the same lines are being used for production of all phthalates including DOP, therefore, the claim of domestic industry of volume injury on account of not utilizing of plant for DOP, is not substantiated. Moreover, the plant has been used for production of other plasticizers and there is no sign of decline.
77. It has been contended by the interested parties that the petitioner has produced other products in the plant and there is no injury to the domestic industry. The domestic industry has contended that they have set up the plant for manufacturing DOP and no other products, however they have been forced to do so due to presence of dumped imports. The Authority has examined the contentions of all the parties and after due verification of records, it is noted that domestic industry has used the plant for manufacturing other products of plasticizer

group instead of using for production of DOP in order to utilize plant capacity. There is no decline in the plant production.

II. Market Share in Demand

78. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

Particulars	UNIT	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Domestic Industry	%	54.77	59.37	46.46	37.89
Other Producers	%	30.85	29.67	21.93	14.17
Subject countries - Imports	%	13.31	10.60	31.31	47.26
Imports from Other Countries	%	1.07	0.36	0.30	0.68
Total	%	100	100	100	100

79. It is noted that market share of the domestic industry has declined as compared to base year as well as previous year. Market share of other Indian producers have also declined during the injury period. Market share of the imports from subject countries has increased over the injury period whereas market share of other countries have remained constant. The Authority notes that the imports of subject countries have captured the market share of DOP of the domestic industry in view of plant is being used for other plasticizers instead of plant being used for production of DOP. It is also noted the same line production is being used for making all kind of plasticizers including DOP which could be reason of decline in shares.

III. Profit/Loss, Cash Flow, Return on Capital Employed

80. The profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analysed as follows:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	70	67
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	70	69
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(94)	81	171
ROI	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(57)	73	117
Cash profit	Rs lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(68)	98	158

81. The Authority notes that the profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry *has increased during the POI. It is noted that the petitioner has added the plant capacity during 2014-15 which led to loss, however, subsequent to that period, they have improved both in profit and loss and ROI which is quite substantial in the situation where imports have increased during POI..*

IV. Employment and Wages

82. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Employment	No	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	98	84

Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	98	98
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	120	118

83. It is noted that the employment levels of the domestic industry has declined during period of investigation. Productivity per employee has increased and wages have shown decline during period of investigation.

V. Inventories

84. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table :

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	2015-16	POI
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	MT	100	85	70	64

85. It is seen that inventories with the domestic industry have declined during period of investigation.

VI. Impact of Net Selling Price

86. The net selling price has been compared with the non-injurious price of the domestic industry both in packed and bulk form and it is noted that the net sales realization is higher in both bulk and packed form compared with the NIP of the domestic industry and they are earning good profit.

Index	NIP	NSR
Packed	***	***
Bulk	***	***

VII. Growth

87. The Authority notes that growth of the domestic industry is positive with regard to production, domestic sales, capacity utilization and market share in demand taking into account the total plant capacity as plasticizer during period of investigation and it is also noted that demand of the product has increased due to expanding market for both plastics and PVC products. The growth in respect to profit, ROI and cash profit was positive in the increasing demand and growing imports. On the whole, the growth of the domestic industry has been positive over the injury period.

VIII. Ability to raise capital investment

88. The Authority notes that the performance of the domestic industry has improved in terms of production, domestic sales, capacity utilization, profit and ROI. In view of the profitability and the growth of the domestic industry, their ability to make fresh investment does not seem to be impaired.

IX. Level of dumping& dumping margin

89. It is noted that subject countries imports are entering the country at dumped prices and that the margin of dumping is significant.

X. Factors affecting prices

90. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price of the domestic industry, and selling price of the domestic industry is much above the non-injurious of the domestic industry *and making good profit*. In view of the above, landed value of imports may not be in a position to drive the domestic prices.

XI. Conclusion on Injury

91. It is thus seen that there has been an increase in the volume of dumped imports from subject country in absolute terms in view of increasing demand. The dumping margin determined by the Authority is significant. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic industry, it is noted that dumped imports from subject countries have not impacted the performance of the domestic industry in respect of volume and price parameters; rather it has shown improvement.

L. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

92. The Authority has determined Non Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in anti-dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been done with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure-III and being followed by the Authority. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries to determine the injury margin as follows;

<u>S.No</u>	<u>Country</u>	<u>Producer</u>	<u>Exporter</u>	<u>Landed Value</u>	<u>NIP</u>	<u>Injury Margin</u>	<u>Injury Margin %</u>	<u>Range</u>
1	Korea RP	M/s Aekyung Petrochemical Co., Ltd.,	a) M/s Canko Marketing, INC., b) M/s Humade Corporation, c) M/s Ubesco Corporation, c) M/s Chemtown Co., Ltd., d) M/s Hyundai Corporation	***	***	***	***	5-10
2.	Korea RP	M/s OCI Co. Ltd.	M/s Everlite Korea Co. Ltd.	***	***	***	***	(0)-(5)
3	Korea RP	All Others	All Others	***	***	***	***	25-30
4	Chinese Taipei	M/s Nan Ya Plastic Corporation	a) M/s Nan Ya Plastic Corporation b) M/s JC Petrochem Ltd., Hong Kong	***	***	***	***	(5)-(10)
5	Chinese Taipei	All Others	All Others	***	***	***	***	10-15

M. Causal Link and other factors

93. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry. Accordingly, the following parameters have been examined:

I. Imports from third countries

94. The Authority has examined the imports data of the subject goods from other countries. It is noted that imports from third countries are negligible and could not have caused claimed injury to the domestic industry.

II. Contraction in demand

95. There has been rise in demand of the product concerned over the injury period. Possible decline in demand could not have caused injury to the domestic industry.

III. Changes in the patterns of consumption

96. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any material change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the Domestic Industry.

IV. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

97. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

V. Developments in technology

98. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic injury.

VI. Export performance

99. The performance of the domestic industry and injury has been examined with respect to the domestic performance to the extent possible. Possible deterioration in the export performance of the domestic industry may, therefore, not a cause of injury to the domestic industry, since the domestic industry is mainly involved in domestic business and having good profitability.

VII. Performance of the domestic industry with respect to other products

100. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the economic health since they have shown good profitability during the POI. However, on examination of information with regard to PUC, it has also shown improvement.

VIII. Productivity of the domestic industry

101. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has followed the same trend as production. Deterioration in productivity is not a cause of injury to the domestic industry.

N. Factors establishing causal link:-

102. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has improved on most of the parameters. Causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is not established on the following grounds-

- a.) The Net Sales Realization of the domestic industry is higher than the Non Injurious Price of the domestic industry.
- b.) The performance of the domestic industry has improved both in volume and price parameters. In view of this, injury if any cannot be attributed to dumped imports from subject countries.
- c.) The Selling price of the domestic industry is higher than the landed value of imports from the subject countries.

O. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

103. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under:

O.1 Submissions by Domestic Industry

104. The submissions made by the domestic industry post-disclosure and considered relevant by the Authority are as follows:
- i) The domestic industry vide the reply to the e-mail dated 28th March, 2018 filed relevant documents to establish that all other Kanatol apart from Kanatol-800, and Kanatol 800 FG, stabilized softener Kanatol-800 and stabilized softener Kanatol-800 FG, do not constitute the PUC. The Authority, however, obtained the views of Central Institute of Plastic Engineering & Technology and ignored its recommendation, instead held that “the domestic industry could not adduce sufficient evidence to prove or nullify the issue raised by the other interested parties that the other stabilised softeners being sold as Kanatol do not constitute DOP”.
 - ii) Govt. of India through Union Budget has substituted the words Dioctyl Phthalate and specified “Dioctyl isophthalate” and “Dioctyl Tetraphthalate” as the relevant description and 29173920 as the relevant HS code. It is, thus, evident that while all parties (including Customs authorities, Importers, users and domestic producers) were considering 29173400 or 29173920 as the classification for DOP in any of its form, the Govt. has now specified that only 29173200 shall be used as the right classification. Therefore, it is requested to the Authority to modify the product description accordingly.
 - iii) The domestic industry has sought disclosure of exporter’s verification report, the communication made with them and the non-confidential version of information filed by them. They have sought additional disclosure of information vide e-mail dated 12th April, 2018 and 16th April, 2018, however, no disclosure has been received. Thus, the present inadequate disclosure of facts is not only contrary to Rule 16 of AD Rules but also hinders the right of the domestic industry to defend its interest.
 - iv) The domestic industry has sought clarification with regard to the documents based on which, it has been assumed that the commission is linked to sales. The statements in the disclosure statement makes it evident that the information documents and submissions made by the domestic industry has been ignored and some other information, documents and submissions not disclosed to the domestic industry, relied upon assuming that expenses is in the nature of commission on sales, is not an operational expense.
 - v) In the disclosure statement, it is stated that the imports are undercutting the prices of the domestic industry, therefore, the exporter-wise price undercutting is meaningless when overall price undercutting is positive. The price underselling/ injury margin is a comparison of NIP and landed value of imports, the overall price underselling is positive in the present case, however, the authority has made a statement with regard to only negative price underselling, which is not objective in nature.
 - vi) The Designated Authority has itself considered that the domestic industry has under-utilized its capacities to the extent of 86% whereas it could have utilized the same to the extent of 96% and despite the same, Designated Authority has held that the petitioner has not suffered any adverse effects on its production, sales and capacity utilization. An underutilization of production capacities by 10% implied loss of production to the extent of 18,000, which translates into 15% of demand and 39% of actual DOP production. The Designated Authority found that domestic industry’s market share declined by 8%, which translates into a loss of sale by 8500 MT. Evidently, in the absence of dumping, domestic industry could have produced and sold higher volumes. This clearly indicates adverse effects of dumped imports on the domestic industry. Further, the product under consideration production, sales and capacity utilization of the domestic industry has declined.
 - vii) The market share of the domestic industry has declined in period of investigation as compared to base year as well as previous year. The market share of other Indian producers has also declined and the market share of the imports has increased. However the disclosure statement thereafter states that the market share of petitioner has declined because the plant was used for production of other plasticizers and not for DOP. An underutilization of production capacities by 10% implied loss of production to the extent of 18,000, which translates into 15% of demand and 39% of actual DOP production. The Designated Authority found that domestic industry’s market share declined by 8%, which translates into a loss of sale by 8500 MT. Evidently, in the absence of dumping, domestic industry could have produced and sold significantly higher volumes.
 - viii) Whereas Para 75, 76 and 78 states that the domestic industry could not have produced more of DOP and the company preferred to produce other types of plasticisers but in the NIP disclosure it was observed that the plant was underutilised by more than 10% and resulted in a lower production of DOP. The Authority has incorrectly determined NIP and adopted an approach to lower the NIP without any legal and factual basis or ignoring its own practices.
 - ix) All imports from Korea are under FTA and were attracting 1.5% duty till 31st Dec., 2016 and ZERO duty thereafter. This can be verified from the importer responses as well as other import documents filed by the domestic industry relating to imports by related parties of KLJ, imports by Payal and Ritzy. However, it is

apprehended that the Authority has considered 7.5% of customs duties for Korea while computing landed price of Imports. The same is accordingly be modified.

- x) It is requested while comparing imported product with domestic product, appropriate adjustment of packing cost (bulk, packed and flexi bags) is required to be made. The Designated Authority however, has considered only two forms in which the material has been transported i.e. packed and Bulk and has not considered Flexi bags.
- xi) The disclosure statement at various places states absence of injury to the domestic industry on the basis that NSR determined is higher than NIP. This contention in the disclosure statement is contrary to the past findings of the Designated Authority and decision of the CESTAT. We refer and rely upon decision of CESTAT in the matter of All India Glass Manufacturers Federation Versus Union of India, wherein CESTAT categorically stated that there is no legal provision to mandate the DA to compare NIP with NSR in order to determine the price effect.
- xii) In view of the arguments made by the interested parties and despite providing sufficient material by domestic industry, Designated Authority earlier sought views from CIPET. Despite CIPET holding in an unambiguous term fact with regard to the scope of product under consideration in the present case, the Designated Authority first brought this letter in the disclosure statement, thereafter ignored the same and made technically incorrect statements in the disclosure statement. While it can be appreciated that Designated Authority is a non-technical body on the technical matters relating to product under consideration, having sought an opinion from CIPET, the Designated Authority could not have ignored the same that too when we have provided significant documents to establish what is DOP and what is not DOP. Domestic industry has also sought opinion from Institute of Chemical Technology (ICT) and it may be seen that ICT has also confirmed that there are no other Phthalate products in the catalogue which can impart similar characteristics to the end products.
- xiii) There is inadvertent error in filing electronic return in MCA return filing. This is totally on account of lack of understanding, knowledge and expertise in feeding information on computerized environment. Moreover, no adverse consequence follows as far as present investigation is concerned. However, the Designated Authority accepted argument of the interested parties and has held that "such claim of 'inadvertent error' is not acceptable as such unrectified mistakes is statutory filing of information before the regulatory authority is incomprehensible". This is an excessive penalty for an inadvertent and inconsequential error in electronically filing return and ignores the fact that there is no possibility of rectification on this account.
- xiv) The domestic industry has submitted that the Authority has accepted excessive and misleading claims of confidentiality by the exporters, leading to severe prejudice to the Petitioner.
- xv) The Authority has considered the imports of DOP by petitioner's related party as 945MT, despite clarification that the actual imports was only 420MT.

O.2 Submissions by exporters and other interested parties

105. The following submissions have been made post-disclosure by the Exporters, Importers, Users and other Interested Parties:

- i) In the petition filed by the domestic industry, only a few of the names of the importers / actual users were mentioned. Consequently, many importers / users were not aware of the investigations and did not file any information to the Authority. However, as soon as they came to know of these investigations, they made a request to the Authority for a public hearing at the earliest. The Authority was pleased to grant a separate oral hearing to the importers / users wherein detailed oral submissions were made, which were followed by written submissions. Thereafter, the importer's questionnaire responses were filed by the following parties: -

- i) M/s Swastik Polyvinyls Pvt Ltd
- ii) M/s Sonarg Plastics Pvt Ltd
- iii) M/s Kkalpana Industries
- iv) M/s Blhani Manufacturing Co. Pvt Ltd
- v) M/s Shankla Industries
- vi) M/s Bihani Group

The names of the importer's may kindly be taken into consideration and the findings in paragraph 4 of the disclosure statement may be modified accordingly.

- ii) The stabilized softener and Kanatol 800 are nothing but DOP that is the product under consideration. The distinction sought to be made based on purity is not correct and has been made only to mislead the Authority. It is difficult to appreciate as to why the same product Kanatol 800 is being cleared under different headings and different nomenclature from different units. We, therefore, apprehend that the correct information has still not been furnished to the Authority and some of its clearances of DOP have been concealed from the Authority, so as to claim injury which is otherwise non-existent.
- iii) The arguments raised were concerning reliability of the information furnished by the petitioner. The domestic industry failed to give details of major producer in India with the sole motive of creating a false impression before the Authority. This aspect has not been dealt with in the disclosure statement. It is submitted that a

- party, which at the very stage of initiation deliberately conceals information from the Authority, should not be allowed to derive any advantage of its own wrong.
- iv) As regards the issues regarding end use, it is submitted that the imposition of Anti-dumping duty will have disastrous effect on the user industry. We reiterate our submission that the continuation of investigations is not in the public interest. There are about 1,500 to 2,000 compounding units in India, using the subject goods. The imposition of anti-dumping duties will have a disastrous result on the compounding industry, as well as, on other downstream industries, such as footwear industry, and for medical applications. Footwear used by the weaker sections of society, contains DOP in significant quantity, almost up to 40% in certain cases. The imposition of duty would result in the escalation of costs, which would result in an even higher increase in prices, on account of taxes and duties. Such price increase would be difficult to absorb, especially by the weaker sections of the society. A similar situation arises in the case of blood bags used for medical applications.
- v) Apart from DOP, the petitioner is also engaged in the manufacture of compounds. Imposition of anti-dumping duties on DOP, will adversely affect the importers / users, since the petitioner would be in a position to manufacture compounds at a much lower cost, and would totally wipe out the user industry. It is submitted that having regard to the serious consequences, which may arise in the event of imposition of duties, the importers request the Authority to balance the interests of the petitioners and the users, as both are Indian Industry and entitled to equal treatment. It would be evident that while the petitioner enjoys healthy profits and returns on capital employed, the importers are operating on thin margins and are extremely vulnerable to changes in raw material price.
- vi) The increase in imports is, therefore, a result of the change in applicable tariffs and duties and is not a result of dumping. The Anti-dumping provisions can only be invoked to redress injury being caused on account of dumped imports. The increase in imports is, therefore, not an indicator of injury consequent to dumping. Further, 8,500 MT of imports made are duty free imports, and need to be disregarded to arrive at the correct figure of volume of imports from the subject countries, as no Anti-dumping Duty can be levied on imports made under Export Promotion Schemes.
- vii) The Authority notes that consequent impact of the dumped imports is not evident from the capacity utilization, profitability, returns on investment, cash flow etc. In this context, it is submitted that we agree with the view of the authority that the capacity utilization for the PUC has declined only due to diversion of capacities for other products (substitutes) and due to expansion. Also that, the profitability, returns on investment, cash flow etc. reveal a positive trends.
- viii) It may be noted that the sales of domestic industry have remained stable over the injury period. The sales of other producer, who are also importer has fallen significantly. This is for the reason that the bulk of the imports are by other producer in fact as far as the petitioner is concerned, there is no impact or volume effect on it.
- ix) It is submitted that the comparison be made separately for the PUC in bulk packing and in bags. While, there is price undercutting by the subject imports, the domestic industry has been able to make profitable sales, and achieve a substantial improvement in profitability during the POI, as compared to the previous year.
- x) As regards the issue of price suppression, it is important to note, that the cost of sales has fallen more than the selling price resulting in an increase in profit as compared to the previous year. Therefore, the question of any price suppression does not arise.
- xi) The landed value of imports, the selling price of domestic industry as well as the cost to make and sell in India, have fallen significantly during the injury period and the POI. The landed value has declined the most, falling from indexed figure 100 in the base year to 60 in the POI. This is a fall of almost 40% as compared to base year. As against this, the selling price of domestic industry has fallen by 31% whereas the cost to make and sell the goods, has declined by 33%. Hence, in a situation of falling costs, the domestic industry has been able to realise a price which has improved its margin of profit. Since the selling price has fallen less than the cost of production, it is evident that the imports have not suppressed or depressed, the prior of domestic industry, especially since the profits of domestic industry have been at their highest level during the POI, demolishing any claim of injury consequent to dumped imports.
- xii) The argument of the domestic industry that other producers are being forced to import because production of the DOP is unviable in India, is not a valid statement, as the petitioner himself is manufacturing and selling DOP at profitable prices, during the POI. In fact both their absolute and per unit profits have substantially increased during the POI, the profit per MT has almost doubled i.e., increased by 1.7 times during the POI as compared to previous years. The cash profit and profit before the interest and tax have increased 1½ times during the POI, as against the base year of 2013-14, and by even more, when compared to the preceding year i.e., 2015-16. The return on capital employed is already in the range of 15% to 25%, even though, there has been an expansion of capacity during the injury period. It is submitted that if the petitioner is able to double its profit in the POI, as compared to the previous years, it is un-imaginable as to why the other producers had to abandon production activities, in favour of making imports.

- xiii) This is even more illogical, in view of the fact, that the other producers have expanded their capacity during the injury period. The aforesaid facts indicate that while KLJ continues to maintain its high prices, the other producers imported and re-sold the subject goods to the user matching the price of petitioner. As a result, there was no loss to the petitioner during the POI, who earned huge profit on its domestic production while the other manufacturers earned exorbitant profits by re-sale of the DOP in the Indian market.
- xiv) As in the case of profits, the return on capital employed has improved significantly in 2015-16 and POI, when the imports were at their peak. In fact, from a situation of negative returns in 2014-15, the domestic industry has achieved a return on capital employed which is even higher than the return in the base year, when there are no dumping. There is clearly no linkage between the import volumes or import prices and the return on capital employed of the domestic industry. In any case, the domestic industry is enjoying a reasonable return on capital employed during the POI, ranging between 15% -25%, which is indicative of the fact, that it is able to profitably compete with the imports, without any measures in force.
- xv) It may be noted that given the rising demand of the product in the country, the domestic industry has made significant investments in plant and machinery. Further, the possibility of injury to the domestic industry caused by the increased investments in plant and machinery instead of dumped imports cannot be ruled out, given that there is substantial expansion underway by other producers, namely M/s Rachna Plasticisers, Dahej (38,400 MT), M/s Aarti Industries Ltd., Dahej (12,000 MT) and Meghaarika Enterprises Ltd. Also, the Authority has rightly noted that in view of the profitability and the growth of the domestic industry, they may be in apposition to make fresh investments, as can also be seen from the above, that other producers are making substantial expansions.
- xvi) It is submitted that there is no causal link between dumping and injury, in view of the fact, that the Authority has found that the domestic industry has preferred to make alternate products as compared to PUC and the decline is, therefore, not on account of the dumped imports.
- xvii) It is submitted that the domestic industry has deliberately shifted to new product / types / variant / substitutes, so as to earn exorbitant profits. This shift is uncalled for and unjustified since profitability of DOP production has almost double over the injury period. This should have acted as an incentive to increase production of DOP. It is also important to consider that during the period of investigation, the selling price is above the NIP, therefore, the petitioner is able to earn adequate profits and returns in excess of 22% of capital employed. This itself indicates a total absence of injury to the domestic industry.
- xviii) There is no dedicated plant capacity for DOP and since the same lines are being used for production of all phthalates including DOP, therefore, the claim of the domestic industry of volume injury on account of not utilizing of plant for DOP is not substantiated.
- xix) The primary raw materials for the manufacturing of DOP are 2-Ethyl Hexanol and Phthalic Anhydride and on both these products anti-dumping duties have been levied. Therefore, any further anti-dumping, if, levied on the subject goods, it shall cause extreme hardship and cascading effect on to the end users of the subject goods. This will amount three anti-dumping duties on the products used by the end user industry. Resultant effect shall be on the consumer and the same shall be against public interest. The primary end users of the subject goods are the cable industry, upholstery manufacturing industry, Foot wear Industry and small scale manufacturing units engaged in production of PVC and Plastic products etc. Impact of three anti-dumping duties shall force them to close their units resulting into loss of capital and creation of widespread unemployment as with the increase in cost of raw material with the impact of three anti-dumping duties, the buyers of their product may resort to import rather than buying from the domestic small manufacturers. DOP constitute around 10-40% towards the cost of raw material of the user industry. Besides, this will also be against the public policy of the Government of India to give impetus to Make in India.
- xx) The domestic industry has submitted the petition on the basis DOP being sold under the brand names Kanatol 800 etc., under Customs Tariff heading 29173920 . As such information with regard to NIP must have been submitted with the Authority for such products only and examination by the Authority might have been undertaken accordingly. However, based on the evidences submitted by the respondent and examination by the Authority, it is clearly evident that the production and sales of DOP in other brand names of the domestic industry viz. Kanatol 900, Kanatol 400(N) etc./ customs tariff heading 29173400 have not been included in its petition.
- xxi) PUC ought to include other stabilized softeners within scope of PUC which is very much evident from KLJ's letter dated 17/05/2017 to the Chairman, CBEC stating that DOP is general name and it includes-a) Di-Octyl Ortho- phthalate, b) Di-Octyl meta-Phthalate, c) Di-Octyl tere-phthalate (DOTP). In furtherance to this, copy of catalogue of Kanatol 8080 of KLJ Group informing there is almost no difference in physical and chemical properties of DOP and Kanatol 8080. It may be noted that DOP is a phthalate based plasticizer and Kanatol 8080 is a non-phthalate based plasticizer (DOTP).
- xxii) It is also submitted that the Petitioner has not provided meaningful non-confidential summary of the import data and the basis of sorting out the data. Since the PUC should be Phthalate Plasticisers, the import data as structured / sorted out by the domestic industry may also be incorrect and no objective analysis of injury parameters can be undertaken by the Authority in accordance with the AD Rules. Further, it has been submitted that there exist contradictions in the information contained in the Petition and the information

- contained in the Annual Reports (Statutory Filing) 2016-17. This raises questions as to the reliability of the Petition filed by the Petitioner.
- xxiii) It has been submitted that domestic industry has claimed excessive confidentiality. Specifically, the Petitioner has failed to supply details of the production and sales of the domestic industry under different brand names. However, while the same was supplied to the Authority on a confidential basis as part of the Written Submissions as Annexure WS 4, no non-confidential version of the same was provided.

O.3 Examination by the Authority

106. It is noted that the comments on Disclosure statement filed by the interested parties are primarily reiterations and reproductions of their earlier submissions in the context of Disclosure statement. The relevant opposing views and submissions are inter alia addressed under the appropriate sections in this final finding which are self-explanatory based on evaluation of the relevant facts and also in view of the relevant rules and jurisprudences to be followed by the Authority. Nevertheless, certain specific comments on the Disclosure statement raised by the parties are addressed as follows;

- i) As regards the request of further disclosure of the facts, the Authority notes that all relevant information pertaining to this case has been disclosed and addressed appropriately at relevant places. Regarding the issue of CIPET's letter, it is noted that the Authority has reproduced it in verbatim in the disclosure statement and also made available the copy of the same in the public file, which is available to all the interested parties. It is noted that the issues raised by the interested parties have been considered and examined in detail in order to arrive at its findings regarding the PUC.
- ii) As regards the classification of DOP, it is noted that this issue has been addressed at the relevant para as per the claim and classification of the product, made by the domestic industry, however, any change in the product classification with the HS code will be dealt by the appropriate Authority.
- iii) With respect to the Customs duty, it is noted that the same has been considered at the time of the disclosure statement at the rate of 7.5% as claimed by the domestic industry during the course of investigation. However, the authority has rectified the same in line with the comments received from the domestic industry subsequent to the disclosure statement and considered the custom duties rate for the subject goods based on the relevant customs tariff notification. Further, in view of the India-Korea CEPA, the custom duty with respect to Korea RP has been considered as 1.56% for April, 2016-Decemembr, 2016 & 0% for January, 2017-March, 2017. Accordingly, the landed value has been worked out and relevant para have been modified at relevant places.
- iv) With regard to the comparison of prices at the same level, the Authority notes that the landed value of the imports has been compared with the NIP of the domestic industry at the same level, factoring the cost of packing of bulk, packed and flexi bags.
- v) As regards the contention of interested parties that the petitioner has concealed the information with regard to production and sales of DOP, the Authority notes that during the course of investigation, authority has proceeded in this investigation based on the information received from the other interested parties and the verified information of the petitioners.
- vi) As regards the capacity expansion of subject goods during the POI, the Authority notes that other producers had also expansion plan of subject goods in the expanding market of the subject goods. Although, the other big producers do not constitute domestic industry, since, they themselves are importers but this capacity expansion indicates positive outlook of producer of subject goods in India.
- vii) With regard to the claim of the domestic industry pertaining to capacity utilization of the PUC, the Authority notes that the petitioner has increased its capacity over the period of injury and in the POI, the utilization of PUC in turn declined. However, considering the trend of capacity utilization since, 2014-2015, it is evident that plant capacity utilization has improved throughout the remaining period. Thus, it is understood that decline in capacity utilization is mainly due to capacity expansion and at the same time it is also noted, while the overall plant production has improved, the production of DOP has declined, Thus, the argument of the domestic industry is not commensurate with facts rather it shows a shift in focus of the petitioner from production of PUC to Non-PUC.
- viii) With regard to the submission that price undercutting should be determined by considering only transaction for landed value of imports which is below the selling price of the domestic industry, the Authority notes that it is the established practise of DGAD that price undercutting exercise is undertaken, taking into account the entire imports during the POI and the similar practise is adopted for determination of underselling/injury margin also.
- ix) With regard to the claims pertaining to NIP, the Authority notes that NIP has been worked out in line with annexure-III of AD Rules. The authority further notes that the amount paid to the Director as commission as a percentage of profit cannot be considered in the NIP working as this is paid out of profits which is not an operational expenses.

- x) With regard to the volume of imports by the related party of the petitioner, the Authority notes that import of DOP by the petitioner related companies has been considered based on the DGCI&S information available before the Authority.
- xi) As regards the claim of excessive confidentiality by the interested parties, the Authority notes that it has disclosed the relevant information subject to the claim of confidentiality under Rule 7 of anti-dumping rules, 1995, however, non-confidential versions of the submissions are made available in the public file. However, applicant specific confidential information has been shared with them.

P. Conclusions and Recommendations

107. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:
- I. The product under consideration has been exported to India from subject countries, below its normal value, resulting in dumping.
 - II. The domestic industry has not suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject countries.
 - III. Causal link between imports from subject countries and injury to the domestic industry is not conclusively established.
 - IV. In view of the above, the Authority does not consider it appropriate to recommend levy of anti-dumping duty on the imports of subject goods from subject countries and hereby terminates this investigation in accordance with Rule 14(b) (e) and Rule 17 (1) (iii) read with 11(ii) of the Anti-Dumping Rules.

Q. FURTHER PROCEDURE:

108. An appeal against the order of the Central Government arising out of this finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority